रांची, शनिवार
20.06.2026
वर्ष : 11, अंक : 198, पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

खबरे हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

संक्षिप्त खबरें

अभिषेक बनर्जी ने की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि तृणमूल से अलग होने की बात कहने वाले धड़े को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान स्पष्ट कहता है कि पार्टी की सदस्यता छोड़ने पर संसद की भी सदस्यता चली जाती है। अभिषेक बनर्जी को इससे पहले 15 जून को लोकसभा अध्यक्ष से मिलना था। हालांकि कोलकाता में ईडी के समन के कारण मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आज 5 बजे मिलने का समय दिया था। मुलाकात के दौरान अभिषेक के साथ कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा और डेरेक ऑ ब्रायन भी मौजूद थे।

तीन दिवसीय पंजाब के दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां तीन दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। वे 20 से 22 जून तक पंजाब में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। अध्यक्ष पद संभालने के बाद नितिन नवीन का यह पहला दौरा है। इस दौरान वे पंजाब में संगठन की तैयारी और विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। भाजपा ने पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी के अनुसार नितिन नवीन 20 जून को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब, जालियांवाला बाग, श्री दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ में मत्था टेककर यात्रा की शुरूआत करेंगे। 21 जून को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। 22 जून को वे चंडीगढ़ में सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, यूथ प्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे तथा पंजाब भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे।

सरकार, युवा और उद्योग साथ चलें तो रोजगार सृजन कई गुना बढ़ता है : मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार सृजन की गति कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) इसी नए भारत की पहचान है, जिसने अब तक करीब 70 लाख रोजगार सृजित किए हैं और पहली बार नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत की युवा शक्ति, प्रतिभा, कौशल और क्षमता को पहचान रही है। हाल ही में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत के युवाओं की चर्चा हो रही है और सरकार का प्रयास है कि देश का प्रत्येक युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-वीबीआरवाई के माध्यम से अब तक करीब 70 लाख नई नौकरियां सृजित हुई हैं और लगभग 70 लाख प्रथम बार रोजगार पाने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा से

जोड़ा गया है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख युवाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि युवाओं के परिश्रम का सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के सपनों को शक्ति देने और युवाओं तथा उद्योगों के बीच मजबूत सेतु का काम करने वाली पहल है।

मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और विकसित भारत का सपना देश के युवाओं के सपनों, कौशल और क्षमताओं पर निर्भर करता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिले, नवाचार करने वालों को मंच मिले और उद्यम शुरू करने वालों को हर संभव सहयोग प्राप्त हो।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की नीतियों और निर्णयों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बुनियादी ढांचा निवेश लाखों युवाओं के लिए रोजगार की नींव रख रहा है, जबकि मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता ने करोड़ों लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और तीन करोड़ से अधिक महिलाएं ह्यलखपति दीदीह्न बन चुकी हैं। वहीं देश में स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर दो लाख से अधिक हो गई है और अब हर जिले में स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रही है, जबकि भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करने में जुटी है और 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ेंगे जो कौशल, नवाचार और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

उन्होंने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसे भारत के निर्माण का माध्यम है जहां युवाओं को अवसर, उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप मिले।

झारखंड के विकास में केंद्र देगा हरसंभव सहयोग : मनोहर लाल

बिभा संवाददाता

रांची। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग और सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के ऊर्जा और शहरी विकास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार सहयोग कर रही है और भविष्य में भी आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा।

शुक्रवार को रांची स्थित एक होटल में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने राज्य की विद्युत व्यवस्था और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में झारखंड सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री सुदिव्य कुमार सहित राज्य सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक की शुरूआत में केंद्रीय मंत्री ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करते हुए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने

पर बल दिया। समीक्षा के दौरान पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की परिचालन एवं वित्तीय स्थिति, भविष्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता तथा पारेषण अवसंरचना (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) के विस्तार से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मनोहर लाल ने राज्य में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों और आपूर्ति लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के अंतर के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए इन दोनों मानकों में सुधार आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार को ठोस और समयबद्ध कदम उठाने होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से सरकारी वितरण कंपनियों के ऋण दायित्वों के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी विभागों द्वारा लंबित बिजली बिलों के शीघ्र भुगतान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि सरकारी उपभोक्ताओं और संस्थानों में लगे बिजली मीटरों को 31 अगस्त 2026 तक प्रीपेड मीटरों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाए, ताकि नियमित भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित उच्च भार वाले सभी उपभोक्ताओं के यहां 31 अगस्त 2026 तक स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्य की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए संसाधनों की पर्याप्तता और पारेषण नेटवर्क के विस्तार की भी समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत जनजातीय परिवारों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण की प्रगति पर संतोष जताते हुए कार्यों में और तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मनोहर लाल ने राज्य सरकार से इन योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने सरकारी भवनों की छतों पर प्राथमिकता के आधार पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी। उनका कहना था कि इससे ग्रिड पर निर्भरता कम होगी और राज्य सरकार के बिजली व्यय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

बैठक के दौरान झारखंड सरकार की ओर से राज्य में चल रही विभिन्न विद्युत एवं शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि स्वीकृत परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन तथा ऊर्जा क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

समीक्षा बैठक को राज्य के ऊर्जा और शहरी विकास क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट मीटरिंग, सौर ऊर्जा विस्तार, वित्तीय सुधार और विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण जैसे निर्णय राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाने में मदद करेंगे।

रांची समेत कई इलाकों में बारिश, गर्मी मिली राहत, 25 जून तक हल्की वर्षा और वज्रपात की संभावना

बिभा संवाददाता

रांची। राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को हुई बारिश से लोगों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक रुक-रुक कर हुई वर्षा के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश रांची के नामकुम क्षेत्र में दर्ज की गई। वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान नामकुम में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि 12 जून को झारखंड में मानसून के प्रवेश के बाद से रांची को छोड़कर अधिकांश जिलों में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। मानसून की कमजोर सक्रियता के कारण राज्य के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि शुक्रवार को हुई बारिश ने राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है।

मौसम विभाग ने फिलहाल राज्यभर में व्यापक और भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। विभाग के अनुसार 25 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

शुक्रवार को रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय मूसलाधार बारिश हुई, जबकि दोपहर बाद भी कई स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज की गई। बारिश के कारण तापमान में कमी आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रांची में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 27.1 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 38.1 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री तथा चाईबासा में अधिकतम 36.8 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

तीन लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन तथा 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य समय से पहले हासिल करेंगे: राजनाथ

एजेंसी

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और तीन लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन तथा 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लिया जायेगा।

श्री सिंह ने शुक्रवार को नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ यंत्र इंडिया लिमिटेड की आयुध निमार्णी अंबाझरी इकाई में अत्याधुनिक 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के भूमि पूजन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा है कि निगमीकरण के बाद आयुध निमार्णी बोर्ड का उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में 26,282 करोड़ रुपए तक पहुँच गया जो वित्त

वर्ष 2019-20 में 12,755 करोड़ रुपए था। निर्यात भी 81 करोड़ से बढ़कर 4,561 करोड़ रुपए पहुंच गया है।

उन्होंने कहा , ₹जो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होता है, वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है।₹ उन्होंने कहा कि यह एक्सट्रूजन प्रेस देश के दृष्टिकोण में उस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें आयात पर निर्भर रहने के बजाय महत्वपूर्ण वस्तुओं का घरेलू उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर नियंत्रण को अनिवार्य बताया।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रेस देश में अपनी तरह की सबसे उन्नत सुविधाओं में से एक होगी। यह रक्षा प्रणालियों एवं विभिन्न प्लेटफॉर्म, अंतरिक्ष एवं विमानन संरचनाओं, मिसाइल कार्यक्रमों, रेलवे एवं परिवहन क्षेत्रों तथा अन्य रणनीतिक औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक बड़े और जटिल एल्यूमिनियम मिश्रधातु प्रोफाइलों के निर्माण में सहायता करेगी। यह परियोजना महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन के आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से रणनीतिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी।

रक्षा मंत्री ने कहा, ₹यह एक्सट्रूजन प्रेस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइलें और उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम ऐसे धातुओं की मांग करते हैं जो हल्की होने के साथ-साथ मजबूत भी हों और अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। ऐसी धातुएँ विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं। यदि धातु की गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी, तो वह हर परिस्थिति में प्रभावी सिद्ध होगी।₹

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत-निर्मित उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने मजबूत हार्डवेयर के स्वदेशी निर्माण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी मशीनों की वास्तविक शक्ति हजारों महत्वपूर्ण अवयवों से मिलकर बनती है और यह एक्सट्रूजन प्रेस इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण ट्रंप प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता : अमेरिकी राजनयिक

एजेंसी

सियोल/वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग के उप सहायक सचिव डेविड विलेजोल ने कहा है कि उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका की उत्तर कोरिया नीति का केंद्र बिंदु परमाणु निरस्त्रीकरण ही है।

दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप न्यूज के अनुसार, जापान, कोरिया और मंगोलिया मामलों के प्रभारी विलेजोल ने ट्राइ फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यदि उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग-उन बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो ट्रंप प्रशासन भी वार्ता के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ताकत के जरिए शांति की नीति जारी रखेगा और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ उसके

साइबर अपराधों और क्रिप्टो करेंसी चोरी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सहयोगियों के साथ काम करेगा।

गौरतलब है कि, ट्राइफोरम एक गैर-लाभकारी संगठन है जो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है।

विलेजोल ने बताया कि पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी और इस सप्ताह फ्रांस में जी-7 देशों के नेताओं ने भी ऐसा ही किया।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है और अपने परमाणु दर्जे को ₹अपरिवर्तनीय₹ बता रहा है। किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने भी जी-7 देशों द्वारा दोहराई गई परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को खारिज करते हुए इसे ऐसी लक्ष्मण रेखा बताया जिसे पार नहीं किया जा सकता। विलेजोल ने दक्षिण कोरिया को युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल (ऑपकॉन) सौंपने के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अमेरिका अपनी सैन्य नेतृत्व की राय को विशेष महत्व देगा और प्रक्रिया को सोच-समझकर और सावधानी से आगे बढ़ाया जाएगा।

भारतीय सेना का मेगा चिकित्सा दृष्टि 2026 शिविर संपन्नः 2500 लोगों की हुई जांच, 393 के मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन

बिभा संवाददाता

रांची : भारतीय सेना द्वारा आयोजित चार दिवसीय मेगा नेत्र चिकित्सा शिविर दृष्टि 2026 का आज नामकुम सैन्य अस्पताल में सफलतापूर्वक समापन हुआ। पूर्वी कमान के तत्वावधान में ब्रह्मास्त्र कोर द्वारा आयोजित यह मानवीय पहल 16 से 19 जून 2026 तक संचालित की गई, जिसमें नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सा दलों ने भाग लिया।

चार दिनों के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हजारों मरीजों को व्यापक नेत्र परीक्षण, उन्नत डायग्नोस्टिक जांच, विशेषज्ञ परामर्श तथा दृष्टि पुनर्स्थापन उपचार उपलब्ध कराया। इस विशाल चिकित्सा अभियान से लगभग 2500 लाभार्थियों ने लाभ प्राप्त किया, जिनमें पूर्व सैनिक, वीर नारियां, सैन्य परिवारों के सदस्य तथा रांची एवं आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के नागरिक शामिल थे। शिविर के दौरान कुल 393 नेत्र शल्यक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की गईं, जिससे अनेक लोगों को पुनः दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिला।

शिविर का समापन समारोह त्रिनेत्र ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल यश अहलावत, जीओसी ब्रह्मास्त्र कोर भी समारोह में सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ एक विशेष वृत्तचित्र के प्रदर्शन से हुआ, जिसमें नेत्र चिकित्सा शिविर की संपूर्ण कार्यप्रणाली, स्क्रीनिंग प्रक्रिया तथा दैनिक गतिविधियों को दर्शाया गया। समारोह का एक प्रमुख आकर्षण सम्मान समारोह रहा, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री ने टीम दृष्टि के समर्पित चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ-साथ चयनित लाभार्थियों को सम्मानित किया।

अपने संबोधन में संजय सेठ ने चिकित्सा विशेषज्ञों, आयोजकों एवं सहयोगी स्टाफ के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए शिविर की उत्कृष्ट योजना, प्रभावी क्रियान्वयन तथा सेवा-भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें भारतीय सेना की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं तथा समाज के वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम के अंत में अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों के साथ अनौपचारिक संवाद का आयोजन किया गया।

दृष्टि 2026 की सफलता इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है कि भारतीय सेना का दायित्व केवल राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के कल्याण एवं मानवीय सेवा के प्रति भी समान रूप से समर्पित है। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सैन्य परिवारों तथा जनजातीय समुदायों को अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सेना ने एक बार फिर अपने मूल आदर्श ह्यसेवा परमो धर्मःह्न को चरितार्थ किया है। यह पहल दर्शाती है कि भारतीय सेना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रहरी ही नहीं, बल्कि देशवासियों के जीवन में आशा, विश्वास और स्वास्थ्य का संबल भी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों एवं जिला जन संपर्क पदाधिकारियों संग की बैठक

बिभा संवाददाता

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं के बीच मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तृत प्रचार-प्रसार करें। उनके द्वारा सभी जिला जनसंपर्क अधिकारियों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में एसआईआर संबंधी संचार और मीडिया प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति और सोशल मीडिया संचार के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया को औपचारिक रूप से साझा किया गया है इसका अनुपालन करते हुए ही कार्य करें। उन्होंने कहा कि एसओपी के आधार पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग और एसआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करें। उन्होंने कहा कि अफवाहों को नियंत्रित करने के साथ ही, व्यापक मीडिया निगरानी के तहत क्षेत्रीय व राष्ट्रीय टीवी चैनलों की दैनिक ट्रैकिंग और सोशल मीडिया और भ्रामक व फेक खबरों की पहचान कर तथ्यों के साथ उनका ससमय खंडन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। के. रवि कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के डिजिटल क्रिएटर हेतु 27 जून को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इंफ्लूएंसर मीट कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी डिजिटल क्रिएटर एवं इंफ्लूएंसर इस मीटिंग में अवश्य भाग लें जिससे वर्तमान में राज्य में जारी एसआईआर के बारे में जानकारी साझा करते समय भारत निर्वाचन आयोग के तथ्यों की जानकारी उपलब्ध रहे।

संक्षिप्त खबरें

एसआईआर में खतियान को मिले मान्यता, बिना नोटिस न कटें नाम

चांडिल(बिभा): झारखंड में 30 जून से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पूर्ण पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड मिली फोरम, लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, ए.पी.एस.आर, भारत जोड़ो अभियान/ साझा कदम और झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मुलाकात की। संगठनों ने प्रक्रिया से जुड़े जमीनी मुद्दों और चिंताओं को रखा । ग्रामीण, आदिवासी, मुस्लिम और महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने का खतरा है, इसलिए खतियान और वंशावली को मान्य दस्तावेज माना जाए और प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की संवैधानिक भूमिका सुनिश्चित की जाए। सामाजिक अंकेक्षण यानी किसी का नाम छूट रहा हैं तो उसकी सूची को ग्राम सभा एवं वार्ड में सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए। खेती के सीजन को देखते हुए एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाने, तार्किक विसंगति के नियम को निरस्त करने और बिना 30 दिनों के लिखित नोटिस के किसी भी नागरिक का नाम न हटाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। यूनाइटेड मिली फोरम से अफजल अनीस , लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान से मंथन , एपीसीआर झारखंड से मोहम्मद जियाउलह, साझा कदम / भारत जोड़ो अभियान से प्रवीर पीटर एवं झारखंड जनाधिकार महासभा से एलिना होरो, प्रियशिला, रिया तुलिका पिंगुआ एवं टॉम कावला इस प्रक्रिया में जुड़े।

हरिणा मेला में उत्पाद विभाग का महा-अभियान, नशा मुक्त समाज के लिए हजारों ने लिया संकल्प

जमशेदपुर(बिभा) : पूर्वी सिंहभूम जिले में नशा मुक्ति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त और सक्रिय नजर आ रहा है। उपायुक्त के कड़े निर्देश पर जिले भर में 10 जून से 25 जून तक एक विशेष 15 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी अहम कड़ी में शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जन-जागरूकता का एक शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। सहायक आयुक्त उत्पाद के निदेर्शानुसार, पूर्वी सिंहभूम की उत्पाद टीम ने जिले के प्रख्यात हरिणा मेला में नशा मुक्ति के खिलाफ एक व्यापक और सघन जागरूकता अभियान चलाया। हरिणा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं और मेले में आए आम आगंतुकों को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होने का सीधा संदेश दिया गया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले इस ऐतिहासिक मेले के जरिए समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं तक नशे के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट संदेश पहुंचाना था।

आरजेडी नेताओं के बयानों से महागठबंधन की मयार्दा हुई तार-तार, कांग्रेस पर लगाए गए आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण : राकेश

रांची(बिभा) । झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने आरजेडी के कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेस और झारखंड प्रभारी के. राजू के खिलाफ दिए गए अमर्यादित और आधारहीन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि किसी दल को अपने विधायकों और नेताओं पर भरोसा नहीं है तो उसकी खीझ कांग्रेस पर निकालना उचित नहीं है। आरजेडी नेताओं द्वारा कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और संगठनात्मक स्थिति पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने आंतरिक मामलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। के. राजू के संबंध में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं बल्कि महागठबंधन की भावना के भी विरुद्ध हैं। जिन नेताओं ने उन्हें ₹बिकाऊ₹ कहने जैसी भाषा का प्रयोग किया है, उन्हें पहले अपने शब्दों की मयार्दा और राजनीतिक संस्कृति पर विचार करना चाहिए। बिना किसी प्रमाण के किसी वरिष्ठ नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास राजनीतिक दिवालियापन का परिचायक है। कांग्रेस यह भी कहना चाहती है कि राज्यसभा चुनाव के परिणामों और मतदान के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कई प्रश्न स्वयं आरजेडी के भीतर उठ रहे हैं। ऐसे में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाना सच्चाई को छिपाने का प्रयास मात्र है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी नेतृत्व से अपेक्षा करती है कि वह अपने नेताओं को संयमित भाषा का प्रयोग करने की सलाह दे और गठबंधन धर्म का पालन करे। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक असफलताओं को छिपाया जा सकता है, तो वह गंभीर भ्रम में है। सच्चाई यह है कि जो लोग अपने घर के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वे दूसरों के आंगन में धूल उड़ाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस न तो दबाव में आने वाली है और न ही झूठे आरोपों से विचलित होने वाली है।

विश्व सिकल सेल दिवस पर सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम

सिकल सेल अनुवांशिक, पर रोकथाम योग्य बीमारी : सीएस

बिभा संवाददाता

रांची। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रांची सदर अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया तथा बीमारी की पहचान, रोकथाम और उपचार को लेकर लोगों को जागरूक किया।

कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार, राज्य नोडल पदाधिकारी (ब्लड सेल) डॉ. प्रमोद कुमार सिन्हा, राज्य नोडल पदाधिकारी (आईईसी सेल) डॉ. राहुल किशोर सिंह, राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. पंकज, हेमेटोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक रंजन, डॉ. ए.के. झा सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन समय पर जांच और उचित उपचार से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल सहित राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच निःशुल्क उपलब्ध है। साथ ही गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच में भी सिकल सेल स्क्रीनिंग को शामिल किया गया है, ताकि बीमारी की समय रहते पहचान की जा सके।

हेमेटोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक रंजन ने कहा कि झारखंड में सिकल सेल जीन का प्रसार अपेक्षाकृत अधिक है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से प्रभावित मरीजों को हाथ-पैर, पेट और छाती में तेज दर्द, बार-बार बुखार, खून की कमी तथा संक्रमण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मरीजों के लिए हाइड्रॉक्सी यूरिया, फोलिक एसिड, आवश्यक टीकाकरण और नियमित चिकित्सकीय परामर्श को बेहद महत्वपूर्ण बताया।

राज्य नोडल पदाधिकारी (आईईसी सेल) डॉ. राहुल किशोर सिंह ने कहा कि जन-जागरूकता और नियमित जांच के माध्यम से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। राज्य नोडल पदाधिकारी (ब्लड सेल) डॉ. प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर आनुवंशिक विकार है, जो दीर्घकालिक एनीमिया, तीव्र दर्द, रक्त वाहिकाओं में अवरोध तथा विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में शीघ्र ही विशेष सर्वेक्षण एवं जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष तथा 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए निःशुल्क रक्त और आवश्यक वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कांग्रेस कार्यकताओं ने राहुल गांधी का 56 वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया

बिभा संवाददाता

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस सहकारिता विभाग के जिला अध्यक्ष चिन्ना राव के नेतृत्व में साकची पलंग मार्केट में देश के जनप्रिय नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन 11 पाउंड का केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चिन्ना राव ने कहा कि राहुल गांधी जी विपक्ष की आवाज बनकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। वे जनसरोकारों के प्रति संवेदनशील, युवाओं के प्रेरणास्रोत और सामाजिक न्याय के दृढ़ योद्धा हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने देश में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सत्य, निडरता और जनसेवा ही उनकी पहचान है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के ऑब्जर्वर रामेश्वर प्रसाद जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय यादव, श्री शैलेंद्र सिंह चंदेल, जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह, जिला महासचिव राकेश साहू, विश्वजीत जेना, अतुल गुप्ता, बबलू नौशाद, ज्योति मिश्रा, शाहिद इकबाल, धर्मेंद्र प्रसाद, अमर मिश्रा, श्रीमती गीता सिंह, खेगेन चंद महतो, जिला सचि देवेंद्र कुमार, श्री मनीष चंद्रवंशी रउप खान, वसीम हैदर, विशाल शर्मा अरुण पटेल, श्री मुकेश सिंह, लव कुमार निराला सिंह गोलमुरी प्रखंड अध्यक्ष सदाकत हुसैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

बिरसानगर में पीएम आवास योजना के 644 फ्लैट्स का महा-लोकार्पण, 322 परिवारों को मिली सपनों के घर की चाबी

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर : शहर वासियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बिरसानगर में बनाए गए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का शुक्रवार को शानदार आगाज हो गया है। इस बहुप्रतीक्षित आवासीय परियोजना के विधिवत उद्घाटन के साथ ही शहर के सैकड़ों परिवारों का अपने पक्के घर का सपना आखिरकार साकार हो गया। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिरसानगर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस डिजिटल उद्घाटन समारोह में रांची से मंत्री के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, निदेशक (नगर प्रशासन) और सूडा निदेशक भी जुड़े रहे। वहीं, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय भी इस खास मौके पर ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

322 लाभुकों को मिली घर की चाबी, हुआ गृह प्रवेश

बिरसानगर की इस विशाल परियोजना के तहत दो बड़े आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें कुल 644 फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। उद्घाटन समारोह में 322 भाग्यशाली लाभुकों को उनके नए फ्लैट की सांकेतिक चाबी और आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर 1000 से ज्यादा लोग अपने परिजनों के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू, नगर आयुक्त योगेन्द्र प्रसाद, उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार समेत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। चाबी मिलते ही लाभुकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने अपने नए घरों में पूरे विधि-विधान से गृह प्रवेश और पूजा-अर्चना की।

हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत, कुल्लू गांव में पसरा मातम

बिभा संवाददाता

नरकोपीः थाना क्षेत्र के कुल्लू गांव में शुक्रवार सुबह जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान खेदुवा उरांव पिता मंगरु उरांव निवासी ग्राम कुल्लू, पोस्ट बेयासी, थाना नरकोपी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेदुवा उरांव शुक्रवार सुबह किसी आवश्यक कार्य से घर से निकले थे। इसी दौरान गांव से सटे जंगल की ओर से निकले एक जंगली हाथी से उनका सामना हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। गंभीर चोटों के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद वन विभाग और नरकोपी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शैलेंद्र टुडू के नेतृत्व में पुलिस एवं वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

मृतक की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों और गांवों में लगातार विचरण कर रहा है। हाथियों के डर से लोग खेतों और जंगल की ओर जाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वन विभाग को सूचना देने के बावजूद हाथियों को आबादी से दूर रखने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई।

ग्रामीणों ने वन विभाग से नियमित गश्ती, हाथियों की निगरानी, समय पर अलर्ट जारी करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। साथ ही मृतक के आश्रितों को शीघ्र सरकारी मुआवजा, पारिवारिक लाभ एवं अन्य राहत सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकारी प्रावधानों के तहत मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में जंगली हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

आइडियल आर्चरी अकादमी का भव्य उद्घाटन, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

बिभा संवाददाता

रातू (रांची)। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल, दलादिली एवं कार्तिक उरांव आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर, रातू, रांची के संयुक्त प्रयास से स्थापित आइडियल आर्चरी अकादमी का भव्य उद्घाटन समारोह विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीता पुष्पा, आईएएस, अपर सचिव, शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार थीं। मुख्य अतिथि सीता पुष्पा ने दीप प्रज्ज्वलन एवं फीता काटकर अकादमी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी झारखंड की समृद्ध खेल विरासत का प्रतीक है और इस प्रकार की पहल राज्य की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेगी।

विद्यालय के निदेशक डॉ. सुबूल आलम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलों को बढ़ावा देना संस्थान की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अकादमी विद्यार्थियों को खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।

विद्यालय की प्राचार्या मंजू बग्गा अरोड़ा ने विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण एवं नियमित अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

कार्तिक उरांव आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर के अध्यक्ष रंजीत तिर्की ने कहा कि अकादमी की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्चस्तरीय तीरंदाजी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा उन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह पहल खेल प्रतिभाओं के सुनहरे भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्र की सचिव ज्योति खलखो ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए अकादमी की भावी योजनाओं की जानकारी दी तथा सहयोग के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

समारोह में विद्यालय परिवार, अभिभावकगण, खेल प्रेमी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने तथा नई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

क्लस्टर प्रणाली से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की अस्मिता और विरासत पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव

बिभा संवाददाता

रांची। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं भाषा प्रेमियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में लागू क्लस्टर प्रणाली से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराया तथा एक ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने कहा कि क्लस्टर प्रणाली लागू होने से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की स्वतंत्र पहचान, अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था, भाषा संरक्षण की प्रक्रिया तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित प्रभावित होंगे। इसका प्रतिकूल प्रभाव झारखंड की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक अस्मिता, लोक साहित्य, पारंपरिक ज्ञान और समृद्ध विरासत पर पड़ेगा। इससे भाषाओं की विशिष्ट पहचान कमजोर होगी तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को भी नुकसान पहुंचेगा।

ज्ञापन में मांग की गई कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को क्लस्टर प्रणाली से मुक्त रखा जाए तथा पूर्व की भांति स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाए, ताकि प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्टता, साहित्यिक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके। मुलाकात के दौरान इस विषय की गंभीरता पर चर्चा हुई और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही आगामी 1 जुलाई 2026 को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का एक कॉन्क्लेव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भाषाओं से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विमर्श कर समाधान की दिशा में पहल की जाएगी।

झारखंड के सभी सदर-रेफरल अस्पतालों को मिलेंगी चार-चार अतिरिक्त एंबुलेंस

15 दिनों में दिखे सुधार, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई : डॉ. इरफान

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी सदर और रेफरल अस्पतालों में चार-चार अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह एंबुलेंस व्यवस्था वर्तमान 108 एंबुलेंस सेवा से अलग होगी, ताकि गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों, अस्पताल अधीक्षकों (डीएस) और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में की।

बैठक में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें अस्पतालों की कार्यप्रणाली, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, एंबुलेंस सेवा, चिकित्सा संसाधनों की स्थिति तथा आगामी मानसून को देखते हुए तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि एंबुलेंस संचालन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए अस्पतालों को आवश्यक तकनीकी संसाधन एवं टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिविल सर्जन अथवा अस्पताल अधीक्षक को सूचना मिलने के बाद तत्काल एंबुलेंस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी जिले स्वास्थ्य सेवाओं में ठोस और दिखाई देने वाला सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने

चेतावनी दी कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या कार्य में ढिलाई को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किसी प्रकार की प्रशासनिक या स्थानीय बाधा आती है तो संबंधित विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर उसका समाधान निकाला जाए। अधिकारियों को भयमुक्त होकर जनहित में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए।

डॉ. अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने सदर अस्पताल परिसरों में ही निवास करें और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन सहित कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की छवि प्रभावित होती है, जिसे अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को निर्देश दिया कि सिविल सर्जनों को पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं, ताकि वे अपने जिलों में त्वरित और प्रभावी निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा कि जिले की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संबंधित सिविल सर्जन को पूर्ण रूप से जवाबदेह बनाया जाएगा।

स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार जैसे मुद्दों पर मंत्री ने कहा कि सरकार पहले संवाद और आपसी समझ से समाधान निकालने का प्रयास करेगी। हालांकि यदि कोई कर्मचारी जनहित के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारियों के वेतन और अन्य भुगतान ट्रेजरी संबंधी तकनीकी कारणों से लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं और अब उनके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देने चाहिए।

बैठक में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक, एनएचएम के वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

राहुल गांधी के जन्मदिन समारोह में शामिल हुई पूर्व विधायक अंबा प्रसाद

बिभा संवाददाता

रांची : नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इन्द्रा भवन में आयोजित समारोह में बड़कागांव की पूर्व विधायक एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद जी शामिल हुईं। कांग्रेस कार्यकताओं और नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं तथा उनके नेतृत्व और जनहितकारी संघर्षों की सराहना की। इस अवसर पर अंबा प्रसाद ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल राजनीतिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों की आवाज बनकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। समारोह के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद प्रियंका गांधी जी एवं देशभर से पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाने तथा जनसरोकारों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प लिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी कार्यकताओं द्वारा जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए तथा उत्साहपूर्ण माहौल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंबा प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का जनसेवा, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के प्रति समर्पण करोड़ों कांग्रेस कार्यकताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।

संक्षिप्त खबरें

23 को बलिदान दिवस और 25 को काला दिवस मनायेगी भाजपा

रांची(बिभा)। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सांसदों, विधायकों, जिला संगठन प्रभारियों की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जहां मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूर्व से चलाए जा रहे कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में भावी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक के दौरान सांगठनिक मजबूती, भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान 30 जून, 2026 से प्रारंभ होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए साहू ने कहा कि पार्टी के पास तय किए गए आगामी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। 21 जून को आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल एवं व्यापक आयोजन के लिए संगठन के सभी शक्ति केंद्रों पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शक्ति केंद्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी कार्यकताओं, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवम मंडल के पदाधिकारी को उस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साहू ने कहा कि 23 जून को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को सभी मंडलों में मनाने और 25 जून को देश में कांग्रेस सरकार की ओर से लागू की गई आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्षों की एक सबसे लंबी कालावधि तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के काल को यादगार बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम पर लगाने का आह्वान किया। वहीं 06 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महाजनसंपर्क, स्वच्छता, प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क अभियान चलाने और जैविक कृषि गोष्ठी, विकसित भारत संकल्प गोष्ठी का आयोजन करने पर बल दिया। वहीं 06 जुलाई को जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया।

30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर बांटेंगी मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म

बिभा सं वाददाता

रांचीः रांचीः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीके.रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं हेल्प डेस्क मैनेजर को एसआईआर के दौरान विभिन्न फेज में किए जाने वाले कार्यों के लिए पीपीटी के माध्यम से बिन्दुवार प्रशिक्षण दिया. के.रवि कुमार ने पीपीटी के माध्यम से बीएलए 2 की भूमिका, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साईन कैटेगरी, बीएलओ ऐप, इन्यूमरेशन फॉर्म, नागरिकता, मैपिंग आदि सभी बिन्दुओं पर पीपीटी के माध्यम से बिन्दुवार प्रशिक्षण दिया.

इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने राज्यभर में हो रहे एसआईआर को लेकर कहा है कि 30 जून से 29 जुलाई तक यानी इन्यूमरेशन फेज के दौरान बीएलओ घरझघर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे एवं मतदाताओं के वर्तमान रंगीन फोटो के साथ उनका सिग्नेचर किया हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म संकलित करेंगे. उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है.गैर-भारतीय नागरिक या

भारतीय नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति इन्युमरेशन फॉर्म बिना भरे या हस्ताक्षर किए बिना ही बीएलओ को वापस लौटा दें. के.रवि कुमार ने कहा कि गलत जानकारी देकर गणना/घोषणा पत्र जमा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है. के.रवि कुमार ने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक,भारतवर्ष में किसी एक ही विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत हो सकते हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र में भी एक ही बार पंजीकृत हो सकते हैं, अर्थात सम्पूर्ण भारतवर्ष में किसी मतदाता का नाम एक समय में एक ही मतदान केंद्र पर रह सकता है. ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दो बार है, वह अपने सामान्य निवास स्थान पर प्राप्त इन्युमनेशन फॉर्म में हस्ताक्षर कर बीएलओ को लौटाएं. दूसरी जगह पर प्राप्त इन्युमनेशन फॉर्म को हस्ताक्षर किये बिना, उचित कारण बताते हुए बीएलओ को वापस करें,ताकि वो एक ही स्थान पर पंजीकृत रह सके. उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम झारखंड के साथ किसी अन्य राज्य में भी है और वह झारखंड राज्य में अपना नाम रखना चाहते हैं तो झारखंड में इन्यूमनेशन फॉर्म भरकर जमा करें एवं अन्य राज्य में फॉर्म 7 भरकर अपना नाम विलोपित करवा लें.

उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों के तहत नागरिकता निर्धारण के लिए जन्म तिथि के आधार पर तीन मुख्य समय-सीमाएं तय की गई हैं. पहली समयावधि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच की है, जिसके तहत 'बर्थ राइट रूल' लागू होता है इस अवधि में भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता है. इसके बाद 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच 'वन पैरेंट रूल' के तहत भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है. वहीं, 2 दिसंबर 2004 के बाद 'टू पैरेंट रूल' लागू होता है, जिसके अनुसार माता-पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है या फिर एक पैरेंट भारतीय नागरिक हो और दूसरा गैर भारतीय पैरेंट बच्चे के जन्म के समय भारत के लिए मान्य पासपोर्ट और वीजा का धारक हो एवं अवैध अप्रवासी न हो.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होगा. ड्राफ्ट पब्लिकेशन में प्रकाशित होने के उपरांत वैसे मतदाता जिनकी मैपिंग सही पाई गई है उन्हें किसी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे. उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के समय भी मतदाता विगत के एसआईआर से अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म लौटाते समय एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साईन कैटेगरी के मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 से वेरिफिकेशन करते हुए ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ इसकी सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा.

के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करते समय बीएलओ द्वारा नए मतदाताओं को फॉर्म 6 एवं डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा मतदाताओं द्वारा भरे हुए फॉर्म 6 का ऑनलाइन अपडेट का कार्य नोटिस एवं सत्यापन की अवधि में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फॉर्म भरते समय मतदाताओं द्वारा घोषणा पत्र के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताये गये 11 दस्तावेजों में से कोई एक संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे.

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं हेल्प डेस्क मैनेजर मौजूद रहे.

इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार के बाद सभी विधायक रहें एकजुट : पांडेय

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि झामुमो के सभी 34 विधायकों ने इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में शत-प्रतिशत वोट दिया है। वह स्वयं पार्टी एजेंट के रूप में पूरे मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मौजूद थे और मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार के बाद सभी विधायक एकजुट रहें। पांडेय ने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बातें कही। विनोद पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले गठबंधन दलों की कई बैठकें की थीं। मतदान को लेकर रणनीति बनाई गई थी। विधायकों को चुनाव प्रक्रिया की व्यापक जानकारियां देने के लिए बकायदा अभ्यास (मॉक ड्रिल) भी कराया गया था। इन सभी प्रयासों के बावजूद गठबंधन के एक प्रत्याशी का चुनाव हार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। महासचिव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव परिणाम की महागठबंधन में समीक्षा की जाएगी।

प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर बचाएं पर्यावरण पर हुआ वेबिनार

बिभा संवाददाता

रांची। स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत सीसीएल द्वारा 19 जून, 2026 को एक व्याख्यान एवं वेबिनार का आयोजन किया गया। इसका विषय ह्यबेहतर कल के लिए प्लास्टिक कचरा कम करनाह्ण था। कार्यक्रम का उद्देश्य एकल-उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के उपायों को प्रोत्साहित करना था।

इस अवसर पर सीआईपीईटी, रांची के निदेशक एवं प्रमुख अवनीत कुमार जोशी ने प्लास्टिक अपशिष्ट के बढ़ते पर्यावरणीय प्रभावों, सतत विकास में अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका और

प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने के लिए अपनाए जा सकने वाले व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक जनभागीदारी एवं व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक (अधिकारी स्थापना/कल्याण), सीसीएल, श्री संजय कुमार ठाकुर ने मुख्य वक्ता श्री जोशी का स्वागत किया। उनके बहुमूल्य विचारों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सीसीएल मुख्यालय से अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की, जबकि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रतिभागियों ने प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी जानकारी प्राप्त की। स्वच्छ एवं हरित भविष्य के निर्माण के लिए अपने योगदान का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के आयोजन में प्रबंधक (सा.वि) श्रीमती पूजा प्रसाद और प्रबंधक (सा.वि) श्रीमती श्वेता हंसदा की सक्रिय भूमिका रही। यह कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न जन-जागरुकता गतिविधियों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

रांची एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने गयाजी पुलिस के इनपुट पर दो आरोपितों को हिरासत में लिया

बिभा संवाददाता

रांची। रांची में स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने गयाजी पुलिस से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर दो युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवक रांची से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान से यात्रा करने वाले थे, लेकिन विमान में सवार होने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया।

हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान मोहम्मद अरशद रेहान और मोहम्मद शाहबाज आलम के रूप में हुई है। दोनों के संबंध में गयाजी पुलिस ने पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद सीआईएसएफ उनके एयरपोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रही थी। दोनों युवक निर्धारित प्रक्रिया के तहत एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रा संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान एयरपोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों युवक रांची से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान से रवाना होने वाले थे। गयाजी पुलिस की ओर से मिले इनपुट के आधार पर सीआईएसएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट थाना के हवाले कर दिया गया।

एयरपोर्ट थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ बिहार के गयाजी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गयाजी पुलिस रांची पहुंची और दोनों आरोपितों को अपने साथ लेकर बिहार रवाना हो गई।

फिलहाल मामले से जुड़े आरोपों और दोनों युवकों की कथित संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व रेलवे

खुली निविदा सूचना संख्या: टीआरडी-डब्ल्यूसी-टी-2026-27-17, दिनांक: 17.06.2026। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/टीआरडी/पूर्व रेलवे, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए वैध विद्युतीय ठेकेदार का लाइसेंस एवं सुपरवाइजरी लाइसेंस रखने वाले तथा निम्नलिखित कार्य को आर्थिक रूप से पूरा करने में सक्षम सम्माननीय निविदादाताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **निविदा केस संख्या: टीआरडी-डब्ल्यूसी-टी-2026-27-17। कार्य का नाम:** निम्नलिखित टीआरडी पोर्शन कार्य: (i) आसनसोल मंडल- सहायक अभियंता/ बीआरएल/आसनसोल के अधीन सोनाचारा-तपसी खंड के बीच पुल संख्या 2 (स्पैन 2x24.689 मी.) की रीगार्डरिंग, जैकेटिंग एवं सुरक्षा कार्य सहित अन्य आनुषंगिक कार्य। (ii) आसनसोल मंडल- सहायक अभियंता/ बीआरएल/आसनसोल के अधीन खाना जंक्शन-आसनसोल खंड के बीच अप एवं डाउन डीएसपी लाइन पर पुल संख्या 9 एवं 9ए की रीगार्डरिंग तथा एम्बैंकमेंट का मज़बूतीकरण सहित अन्य आनुषंगिक कार्य। (iii) सहायक अभियंता/बीआरएल/आसनसोल के अधीन खाना जंक्शन-आसनसोल खंड के बीच अप डीएसपी लाइन पर पुल संख्या 4 (आरओआर) की रीगार्डरिंग एवं एम्बैंकमेंट का मज़बूतीकरण सहित अन्य आनुषंगिक कार्य। (iv) आसनसोल मंडल- आसनसोल-खाना जंक्शन खंड में कालीपहाड़ी-दामोदर जंक्शन के बीच पुल संख्या 2 डीके की रीगार्डरिंग सहित अन्य आनुषंगिक कार्य। (v) आसनसोल मंडल- मंडल अभियंता/4/ आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में सहायक अभियंता/1/अंडाल के अधीन अंडाल में पुल संख्या 20 के लिए पीएससी गार्डर की बदली एवं जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा कार्य सहित अन्य आनुषंगिक कार्य। (vi) आसनसोल मंडल- वरिष्ठ मंडल अभियंता/III/आसनसोल के खंड में प्रतिस्थापन के आधार पर मानकर स्टेशन पर नए पैदल ऊपरी पुल का प्रावधान। (vii) आसनसोल मंडल- वरिष्ठ मंडल अभियंता/III/ आसनसोल के खंड में प्रतिस्थापन के आधार पर गलसी स्टेशन पर नए पैदल ऊपरी पुल का प्रावधान। (viii) मार्शेलिंग यार्ड, अंडाल में नया आरओएच शेड। **निविदा मूल्य:** ₹ 3,30,63,974.52। **बयाना राशि:** ₹ 6,61,300। **निविदा खुलने की तारीख एवं समय:** 29.07.2026 को अपराह्न 3.00 बजे। **कार्य पूरा करने की अवधि:** स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तारीख से 12 (बारह) महीना। **कार्य हेतु प्रस्ताव की वैधता:** खुलने की तारीख से 60 दिन। सम्पूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(ASN-144/2026-27)

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

नाबार्ड और झारखंड राज्य सहकारी बैंक की बड़ी पहल : रांची में तीन दिवसीय आम महोत्सव का शानदार आगाज

अंतरराष्ट्रीय बाजार में धूम मचाएंगे झारखंड के आमः दीपमाला घोष

बिभा संवाददाता

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के शहीद चौक स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक लि. के प्रांगण में तीन दिवसीय आम महोत्सव 2026 की भव्य शुरूआत हो गई है। बैंक और नाबार्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चतुर्थ आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष और विशिष्ट अतिथि झारखंड राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्षा बिभा सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसएलबीसी के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड, प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता जमुना टुडू और

दिव्यायन कृषि विकास केंद्र के सचिव स्वामी भावेशानंद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

महोत्सव को संबोधित करते हुए नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने नाबार्ड की महत्वाकांक्षी ट्राइब्स परियोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में लाए गए सभी आम और कृषि उत्पाद नाबार्ड समर्थित जनजातीय परियोजनाओं से जुड़े किसानों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये आम 'एक्सपोर्ट क्वालिटी' (निर्यात गुणवत्ता) के हैं, जिनमें घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाने और किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है।

सहकारिता से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्थाः बिभा सिंह

झारखंड राज्य सहकारी बैंक की अध्यक्षा बिभा सिंह ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ फलों का मेला नहीं है, बल्कि हमारे राज्य के किसानों की मेहनत, धैर्य और सहकारिता की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिकने वाले सभी आम पूरी तरह से ऑर्गेनिक (जैविक) हैं।

अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि राज्य के किसान अपने-अपने क्षेत्रों में लैम्पस/पैक्स से जुड़ें और बैंक द्वारा चलाई जा रही डेयरी, मत्स्य पालन और वनोत्पाद जैसी विभिन्न सहकारी व वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाएं। यह उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा साधन बनेगा।

कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव राज्य के अन्य फल उत्पादकों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। वक्ताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य दिलाने और आम जनता को केमिकल-मुक्त (कीटनाशक रहित) उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए साल में कम से कम 3 से 4 बार ऐसे मेलों का आयोजन होना चाहिए। इससे लोग रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे।

इस उद्घाटन समारोह में नाबार्ड और झारखंड राज्य सहकारी बैंक के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में किसान व आम नागरिक उपस्थित थे। यह महोत्सव अगले तीन दिनों तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा, जहाँ लोग सीधे किसानों से शुद्ध ऑर्गेनिक आम खरीद सकेंगे।

मुहर्रम से पहले बोकारो में पुलिस का सघन अभियान, रातभर फुट पेट्रोलिंग व ड्रंक एंड ड्राइव जांच

बिभा संवाददाता

बोकारो। आगामी मुहर्रम पर्व एवं अन्य आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बोकारो पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रात्रिकालीन फुट पेट्रोलिंग, एंटी क्राइम चेकिंग तथा ड्रंक एंड ड्राइव अभियान तेज कर दिया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार संचालित किया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखना, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा अड्डेबाजी एवं अपराध पर अंकुश लगाना है।

इसी क्रम में सेक्टर-6 थाना, बी.एस. सिटी थाना सहित अन्य थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अपने-अपने क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सघन फुट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं गतिविधियों की गहन जांच कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

साथ ही सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों की जांच कर यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। नियमों की अनदेखी करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी गई। बोकारो पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने आम नागरिकों से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

सीसीटीवी में कैद चोरी-चोरों ने बेसमेंट से घर में घुसकर काटा पानी पाइप, सोने-चांदी के सामान ले गये

बिभा संवाददाता

बोकारो । जिले के चीरा चास थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के घर पर हुई चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो आरोपी मकान के निचले हिस्से यानी बेसमेंट के रास्ते अंदर दाखिल हुए और अंदर रखी कीमती चीजें पार कर गये।

घटना स्थल के आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उन्होंने पानी की मुख्य पाइप को काटकर ले जाने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वे सावधानी से घर के भीतर पहुँचते हैं और कुछ ही मिनटों में तमाम कीमती सामान उठाकर भाग जाते हैं।

स्थानीय निवासी ने बताया कि पिछले दिनों भी गंधा जोड़ इलाके में एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली थी। इन घटनाओं के बाद इलाके में लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है और वे अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिये मजबूर हो रहे हैं। चीरा चास थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है और पुलिस आसपास के अन्य कैमरों की भी रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। थाना अधिकारियों ने कहा कि संदिग्धों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। (पुलिस के विस्तृत बयान का इंतजार है।) पुलिस और स्थानीय लोगों ने घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाने तथा अज्ञात लोगों की संदिग्ध हरकतें देख कर तुरंत 100 पर सूचित करने की सलाह दी है। पड़ोसियों ने कहा कि रात के समय घरों के निचले हिस्सों और बेसमेंट पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए और सम्भव हो तो अलार्म तथा अतिरिक्त लाइटिंग लगाई जाए।

जबकि इलाके में चल रही सीसीटीवी फुटेज से चोरों के अंदाज और पहनावे की कुछ झलकें मिली हैं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई जानकारी हो तो तुरंत थाने में रिपोर्ट करें। चेहरा छिपा होने के कारण पहचान मुश्किल हो सकती है, इसलिए किसी भी संदिग्ध वाहन या अज्ञात व्यक्ति की सूचना अहम होगी।

बीएसएल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बिभा संवाददाता

बोकारोः ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी लाने तथा सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के मानव संसाधन विकास विभाग में ईसीएस विभाग के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गणना, उसके प्रभावों तथा उत्सर्जन में कमी लाने के उपायों की जानकारी देना था।

प्रशिक्षण के दौरान विश्व इस्पात संघ (वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन) की पद्धति के आधार पर उत्सर्जन गणना की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर लागू नियमों, नीतियों तथा इस्पात उद्योग में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत, जलवायु परिवर्तन पर उनके प्रभाव तथा उत्पाद लागत पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया गया। प्रतिभागियों को उत्सर्जन कम करने के लिए अपनाए जा सकने वाले नवाचारों और प्रभावी उपायों से भी अवगत कराया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

तेनुघाट उपकारा में 21 जून को जेल अदालत व कानूनी जागरूकता शिविर

तेनुघाट (बोकारो) : तेनुघाट स्थित उपकारा में 21 जून को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एक विशेष बेंच का गठन किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला एवं अधिवक्ता नीरज कुमार शामिल रहेंगे। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति की सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य बंदियों को कानूनी सहायता एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

संक्षिप्त खबरें

डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल में स्काउट गाईड का प्रशिक्षण शुरू

बोकारो(बिभा)। डॉ राजेन्द्र प्रसाद पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रानीपोखर में स्काउट गाईड का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें पहले सत्र के प्रशिक्षण शिविर में स्कूल के कुल 40 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। जिसमें स्काउट व गाईड के ट्रेनर आरके शर्मा व एसके शर्मा ने स्कूल के छात्र-छात्राओं को स्काउट व गाईड के बारे में विस्तृत जानकारी दी व उन्हें अनुशासन में रहकर इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। जिसमें उन्हें कदम ताल के अलावे कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट करने का विशेष प्रशिक्षण दिया। इसके अतिरिक्त स्काउट व गाईड का तीन तरह का ताली बजाने का भी प्रशिक्षण दिया। स्कूल परिसर में 10 दिनों को प्रशिक्षण देने के बाद प्रथम सत्र का प्रशिक्षण शिविर का प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। जिसमें स्कूल के प्राचार्य डॉ मुकेश कुमार ने इस स्काउट गाईड के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिए सभी 40 स्काउट व गाइड को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा छात्र व छात्राएं इस स्काउट व गाईड के प्रशिक्षण शिविर से काफी लाभान्वित हुए। इससे छात्रों में अनुशासन में रहकर मार्च पास्ट समेत अन्य प्रकार का कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किया। मौके पर स्कूल की शिक्षिका बिंदु सिंह, साक्षी कुमारी, गीता सिंह, राखी कुमारी, अनु सिंह, वीणा कुमारी, मंजुश्री, खुशबु कुमारी, वनशिखा तिवारी समेत अन्य शामिल रहे।

अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, 150 किलो जावा महुआ नष्ट

बोकारो(बिभा)। चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरी, डुमरदाह, सिधाबाद एवं सिंहडीह गांव में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले लगभग 150 किलोग्राम जावा महुआ को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना तथा इससे होने वाली सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकना है। अभियान के दौरान कई संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान के लिए जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

बोकारो(बिभा)। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है। नियमित योगाभ्यास से स्मरण शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास तथा मानसिक संतुलन का विकास होता है। इसी संदेश को आत्मसात करते हुए गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल, सेक्टर-5/बी, बोकारो में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन विद्यालय के भाई नंद लाल जी सभागार में अत्यंत उत्साह, अनुशासन और ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के व्यस्त और तकनीक-प्रधान जीवन में योग का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, बल्कि विद्यार्थियों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच, मानसिक शांति तथा भावनात्मक संतुलन विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए अवश्य निकालने तथा इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान संबंधी अभ्यासों का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन, पवनमुक्तासन, पद्मासन, सूर्य नमस्कार, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम तथा ध्यान (मेडिटेशन) का अभ्यास कर योग के प्रति अपनी सजगता और उत्साह का परिचय दिया।

पेटरवार स्थित नवनिर्मित वन विश्रामागार का मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया उद्घाटन

बिभा संवाददाता

बोकारो। मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र प्रसाद ने पेटरवार स्थित नवनिर्मित वन विश्रामागार का शुक्रवार को विधिवत फीता काटकर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर शुभ उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्पगुच्छ एवं नन्हा पौधा भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह नवनिर्मित वन विश्रामागार क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके निर्माण से क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, पर्यटकों एवं आम नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा होगी। मंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा एवं पर्यटन की अपार संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। ऐसे में आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ विकास पर्यटन को प्रोत्साहित करने, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह वन विश्रामागार क्षेत्र में आने वाले आगंतुकों के लिए एक उपयोगी एवं सुविधाजनक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। इस अवसर पर मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को वन विश्रामागार के समुचित रख-रखाव, स्वच्छता, सुरक्षा एवं बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा ऐसी जनोपयोगी परिसंपत्तियों का संरक्षण एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहें।

डी वाई स्कूल में पितृ दिवस मनाया गया

बिभा संवाददाता

बोकारो। डी. वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, बोकारो में पितृ दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पिता के योगदान, त्याग और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना जागृत करना था। कार्यक्रम की शुरूआत प्रार्थना से हुई, जिसके पश्चात छात्रों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। 'पिता और संतान' के रिश्ते पर आधारित लघु नाटिका विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

प्रभारी प्राचार्य मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा, पिता परिवार की वह नींव हैं जो बिना दिखे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाते हैं। पितृ दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। मुझे गर्व है कि हमारे विद्यार्थियों ने आज अपनी प्रस्तुतियों से इस भाव को सुंदरता से व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और अन्य कर्मचारियों का योगदान सराहनीय रहा।

डीपीएस बोकारो में समर कैंप का समापन, बच्चों ने सीखे खेलकूद, योग और संगीत से लेकर एआई इनोवेशन तक के गुर

बिभा संवाददाता

बोकारो। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों की रचनात्मकता को नया आयाम देने, उनके भीतर छिपी बहुमुखी प्रतिभा निखारने और उन्हें आधुनिक जीवन कौशलों से समृद्ध करने के उद्देश्य से दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), बोकारो में आयोजित समर कैंप का शुक्रवार को योग प्रशिक्षण के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस पूरे शिविर के दौरान सुनियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से बच्चों को खेल, कला, संगीत से लेकर 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीक के गुर सिखाए गए। इस बहुआयामी समर कैंप में विभिन्न आयु वर्ग के 300 से अधिक छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह, उमंग और ऊर्जा के साथ भागीदारी की। शिविर के दौरान जहां एक ओर बच्चों ने एथलेटिक्स और विभिन्न खेलकूद स्पधाओं में अपनी शारीरिक फिटनेस के लिए मैदान पर जमकर पसीने बहाए, वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (एआई) और डिजाइन थिंकिंग जैसी उन्नत चीजें सीखकर अपने नवाचारी व तकनीकी कौशल का संवर्द्धन किया। खेलकूद के सत्र में विद्यालय के वरिष्ठ और अनुभवी क्रीड़ा शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में बच्चों ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, जैवलीन थ्रो, हाई जंप, कराटे और जुम्बा का गहन व व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, साथ ही तैराकी की बारीकियों और उसके विभिन्न कौशलों को भी बेहद चाव से सीखा।

इस सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. एस. गंगवार ने इस प्रकार के ग्रीष्मकालीन शिविरों की महत्ता को आज के समय में बेहद अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि छुट्टियां केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और नई विधाएं सीखने का एक बेहतरीन अवसर होती हैं। समर कैंप बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर उनके भीतर छिपी अद्वितीय प्रतिभा को निखारने, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें एक मंच प्रदान करने में अमूल्य योगदान देते हैं। प्राचार्य ने शिविर में बच्चों की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि खेल, संगीत और आधुनिक तकनीक का यह अनूठा संगम विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। डीपीएस बोकारो विद्यार्थियों के इसी प्रकार के समग्र विकास और उनकी रचनात्मक मेधा को तराशने के लिए सदैव कटिबद्ध है, ताकि वे भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम बन सकें।

शिवा लॉज के कमरे में जमीन कारोबारी की संदिग्ध मौत, फॉरेंसिक जांच के बाद खुलेगा राज

बिभा संवाददाता

बोकारो। चास थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट स्थित चर्चित स्वीट इंडिया मिठाई दुकान के ऊपर संचालित शिवा लॉज के कमरा संख्या-15 में एक जमीन कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही चास थाना पुलिस के साथ चास के एएसपी वेदांत शंकर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान धनबाद जिले के बरोरा थाना क्षेत्र निवासी लक्ष्मण साव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह पहले अपने नाम से लॉज में ठहरे थे, लेकिन बाद में चास निवासी अजय कुमार के नाम से कमरा बुक कर वहीं रह रहे थे। इसकी पुष्टि एएसपी वेदांत शंकर ने की है।

होटल संचालक द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने तक शव काफी सड़-गल चुका था और कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे वहां ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मृतक के भाई ने आत्महत्या की आशंका को खारिज करते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि लक्ष्मण साव के साथ कोई साजिश या गलत घटना हुई है। मृतक जमीन कारोबार से जुड़े थे और उनका व्यवसाय बोकारो, धनबाद, रांची समेत कई शहरों में फैला हुआ था।

एएसपी वेदांत शंकर ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है, क्योंकि लॉज का रजिस्टर और अन्य अभिलेख सही तरीके से संधारित नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक जांच पूरी होने तक कमरा संख्या-15 को सील कर दिया गया है तथा पूरे लॉज को भी सील करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

बीएसई के सीईओ ने वेदांता की ऐतिहासिक लिस्टिंग की सराहना की; 'समुद्र मंथन' से की इसकी तुलना

बिभा संवाददाता

बोकारो। वेदांता समूह ने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी चार नव-विभाजित (डीमर्ज्ड) कंपनियों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध किया। इस कदम के साथ समूह ने पाँच स्वतंत्र और केंद्रित व्यवसायों की स्थापना की है, जो भारत के विकास के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित एक विशेष समारोह में मनाया गया, जिसमें उद्योग जगत के अग्रणी, निवेशक और अन्य हितधारक शामिल हुए।

इस अवसर पर बीएसई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) श्री सुंदररमन राममूर्ति ने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह बीएसई के स्थापना दिवस के साथ संयोगवश आई है। उन्होंने कहा कि यह केवल चार नई सूचीबद्ध कंपनियों का जन्म नहीं है, बल्कि भारत के पूंजी बाजार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरूआत भी है।

वेदांता के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल की साधारण पृष्ठभूमि और वेदांता की विकास यात्रा की तुलना प्राचीन भारतीय कथा 'समुद्र मंथन' से करते हुए श्री राममूर्ति ने कहा कि असाधारण उपलब्धियाँ अक्सर विनम्र शुरूआत से ही जन्म लेती हैं। उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्य अल्पारम्भः क्षेमकरः का उल्लेख करते हुए कहा कि जो कार्य छोटे स्तर पर शुरू होते हैं, वे समय के साथ असाधारण उपलब्धियों का रूप ले सकते हैं।

उन्होंने कहा, जो यात्रा एक छोटे से प्रयास के रूप में शुरू हुई थी, वह आज एक विराट स्वरूप ले चुकी है। वेदांता का कार्य धरती माता की सतह के नीचे छिपे प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को सामने लाना रहा है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से छिपे हुए रत्न और अमृत प्राप्त हुए, उसी प्रकार वेदांता ने पिछले कई दशकों में जिंक, एल्युमीनियम, तांबा, लौह अयस्क, तेल, गैस और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को खोजकर भारत की औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाया है। श्री राममूर्ति ने वेदांता के संस्थापक एवं चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल की दृढ़ इच्छाशक्ति और संघर्षशील नेतृत्व की भी सराहना की।

उन्होंने संस्कृत के श्लोक सुधां विना न प्रययुः विरामं, न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः का उल्लेख करते हुए कहा कि साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले कभी रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला, तब भी देवताओं ने हार नहीं मानी और अंततः अमृत प्राप्त किया। उसी प्रकार श्री अग्रवाल ने भी चुनौतियों और अवसरों के बीच अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया तथा भारत के भविष्य पर विश्वास रखते हुए निरंतर निवेश, विस्तार और मूल्य सृजन का कार्य जारी रखा।

श्री राममूर्ति ने श्री अनिल अग्रवाल के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि असली महानता हमेशा विनम्रता के साथ आती है। उन्होंने कहा कि अपनी असाधारण उपलब्धियों के बावजूद श्री अग्रवाल आज भी सादगी, सहजता और समाज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय देते हैं। उन्होंने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सामाजिक योगदान का भी उल्लेख किया और कहा कि नंद घर जैसी पहल के माध्यम से देशभर में 10,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे महिलाओं और बच्चों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है।

अपने संबोधन के समापन में श्री राममूर्ति ने कहा कि यह ऐतिहासिक लिस्टिंग दूरदृष्टि, साहस और दशकों की निरंतर मेहनत की विजय का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वेदांता के ये पाँच स्वतंत्र व्यवसाय आने वाले वर्षों में हजारों नए उद्यमों को जन्म देंगे, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे तथा भविष्य में अनेक नई कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पाण्डेय ने नवनिर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का किया उद्घाटन

बिभा संवाददाता

रामगढ़ः झारखंड सरकार की माननीय ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने शुक्रवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ के समीप नव निर्मित प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन रामगढ़ का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के उपरांत मंत्री ने भवन का निरीक्षण कर विभिन्न कार्यालय कक्षों, नागरिक सुविधा केंद्रों तथा उपलब्ध कराई गई आधारभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन तथा आम नागरिकों को त्वरित एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और आम जनता को केंद्र में रखकर विकास कार्यों को गति दे रही है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में नए कार्यालय भवनों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण इकाई हैं और बेहतर आधारभूत संरचना से कार्य संस्कृति एवं सेवा वितरण में सकारात्मक बदलाव आएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस अवसर पर रामगढ़ विधायक ममता देवी, उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज, सांसद प्रतिनिधि हजारीबाग, विधायक प्रतिनिधिगण, अन्य जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

नीट परीक्षा को लेकर हजारीबाग में परीक्षा केंद्रों के बाहर निषेधाज्ञा लागू

बिभा संवाददाता

हजारीबाग। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) का आयोजन 21 जून 2026 (रविवार) को हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र के 09 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर हजारीबाग श्री आदित्य पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिन परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी, उनमें संत कोलंबा महाविद्यालय, के.बी. महिला महाविद्यालय, आर.के. प्लस टू उच्च विद्यालय कटकमसांडी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ मेरु, के.एन. प्लस टू उच्च विद्यालय इचाक, संत कोलंबा महाविद्यालय वोकेशनल भवन, मार्खम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोंगा तथा बिहारी बालिका उच्च विद्यालय बड़म बाजार शामिल हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास लाठी, हथियार, आग्नेयास्त्र समेत अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर घूमने पर भी पाबंदी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता सुबोध कुमार सिंह का असामयिक निधन

रामगढ़(बिभा): भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ जिला कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के आकस्मिक निधन से भाजपा परिवार सहित पूरे रामगढ़ जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन का समाचार मिलते ही संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकताओं, शुभचिंतकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों में गहरा दुःख व्याप्त हो गया। भाजपा रामगढ़ जिला अध्यक्ष संजीव कुमार बावला ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुबोध कुमार सिंह एक कर्मठ, निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता थे। प्रत्यदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह वे प्रतिदिन की भाँति अपनी स्कूटी से अपने कार्यक्षेत्र की ओर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डिवाइडर से टकरा गए। दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। घटना के तुरंत बाद उन्हें सदर अस्पताल, रामगढ़ ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के पश्चात बेहतर चिकित्सा के लिए हॉप हॉस्पिटल रेफर किया गया। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। जिसने भी यह दुःखद समाचार सुना, वह स्तब्ध रह गया। आज शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार दामोदर नदी तट पर पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मित्रगण एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए और नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई।

अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद विभाग की सघन छापेमारी, 150 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त

हजारीबाग(बिभा): उपायुक्त हेमन्त सती के निदेर्शानुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, संचय एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग के निर्देशन तथा निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पसई एवं मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सीतागढ़ा में अलग-अलग घरों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घटनास्थल एवं आसपास के घरों में छिपाकर रखे गए लगभग 600 किलोग्राम किन्वयन योग्य जावा महुआ को विनष्ट किया गया। साथ ही शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, बर्तन आदि को नष्ट करते हुए लगभग 150 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद कर जब्त की गई। उत्पाद विभाग द्वारा मामले में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा रही है तथा उनके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी अभियान में निरीक्षक उत्पाद सौरव कुमार झा, अवर निरीक्षक उत्पाद भुवनेश्वर नायक, अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक एंटोनी बागे, उत्पाद आरक्षी अनूप कुमार सिंह तथा सशस्त्र गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल थे। जिला प्रशासन एवं उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पूज्य मुनिश्री 108 सुयश सागर जी महाराज से हजारीबाग के श्रद्धालुओं ने लिया मंगल आशीर्वाद

हजारीबाग(बिभा) : पूज्य मुनिश्री 108 सुयश सागर जी महाराज से हजारीबाग के कई श्रद्धालुओं ने मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने मुनिश्री से धर्म चर्चा करते हुए आगामी चौमासा प्रवास हजारीबाग में करने का आग्रह किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि मुनिश्री के सानिध्य में धार्मिक वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ समाज के लोगों को मिलेगा। उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि इस बार चौमासा के दौरान हजारीबाग में विराजमान होकर समाज को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करें।मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने वालों में जैन समाज के पूर्व महामंत्री पवन जैन अजमेरा, पूर्व संयुक्त महामंत्री राजीव छाबड़ा, उत्तम पाटोदी, टोनी छाबड़ा,सुनील लुहाड़िया,सुनील विनायका राजेश जैन सहित कई श्रद्धालु शामिल रहे।

सरकारी खजाने में 22.69 लाख की सेंध, खाताधारक गिरफ्तार, लेखापाल की तलाश में छापेमारी जारी

बिभा संवाददाता

खूँटी । जिले के तोरपा स्थित एसआईआरबी-02 वाहिनी मुख्यालय की लेखा शाखा में सरकारी राशि के गबन मामले पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। जो कि खूँटी में एक ट्रेजरी घोटाला का मामला एसआईआरबी-2 वाहिनी सारिदकेल में विगत दिनों हुआ था। जिसका उद्भेदन भी हुआ था। जिसमें लेखापाल के द्वारा अपने ही रिस्तेदार के खाते में पैसा डाला करता था। जिसका खुलासा होने के बाद पुलिस छापामारी में लगी थी। ये मामला सरकारी नियमों की अनदेखी कर 22 लाख 69 हजार रुपये एक निजी बैंक खाते में अवैध रूप से स्थानांतरित किये जाने का मामला था। मामले में पुलिस ने मुख्य खाताधारक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी लेखापाल की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के घोडाटाप निवासी 26 वर्षीय शुभम सिंह के रूप में हुई है। उसका चचेरा भाई अजित सिंह, जो लेखापाल है, इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है।

मामले का खुलासा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की त्रिस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद हुआ। जांच में गबन की पुष्टि होने पर तत्कालीन उपायुक्त सौरभ भुवानिया के निर्देश पर 21 मई को खूँटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद एसपी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया।

पुलिस पूछताछ में शुभम सिंह ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि उसके नाम से खोले गए बैंक खाते का संचालन अजित सिंह करता था। खाते में उसके मोबाइल नम्बर का उपयोग किया गया था और बदले में शुभम को कमीशन दिया जाता था। जिसमें थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी अजित सिंह की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर चाईबासा में आयोजित हुई रन फॉर योगा

बिभा संवाददाता

चाईबासा : प्रोजेक्ट जागृति बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम अभियान के तहत आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के निमित्त जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम ने रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर से किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी मैदान, चाईबासा में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं तथा युवा वर्ग ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने योग के महत्व एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्लोगन, पोस्टर एवं होर्डिंग के माध्यम से शहरवासियों को योग अपनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों एवं गणमान्यजनों को नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास स्वस्थ एवं तनावमुक्त जीवन का आधार है। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु आईएएस, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला शिक्षा अधीक्षक, उपसमाहर्ता नजारत, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

अड़की में करकरी नदी पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों की बैठक

खूँटी (बिभा)। जिले के अड़की प्रखंड अंतर्गत तोड़ांग पंचायत स्थित बांदूगढ़ा और लेबेद के बीच करकरी नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कनीय अभियंता को बुलाया गया था। जिसमें कनीय अभियंता व विधायक प्रतिनिधि मनोज मण्डल उपस्थित हुए। जिस बैठक में पुल निर्माण से संबंधित विभिन्न आशंकाओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि करीब एक वर्ष पूर्व 12 गाँवों के ग्रामीणों ने विधायक विकास कुमार मुण्डा को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में मिट्टी जाँच कराने की मांग की थी। इस पर पहल करते हुए विधायक प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मिट्टी जाँच का कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिल सके। बैठक में मुख्य रूप से झामुमो जिला प्रवक्ता सह विधायक प्रतिनिधि मनोज मंडल, कनीय अभियंता मनोज कुमार, शेखर मुंडा, डोमा मुंडा, बीरेंद्र मुंडा, प्रकहित मुंडा, बुधु मुंडा, कड़िया मुंडा, सुरेश मुंडा, करम सिंह मुंडा और गुरु मोहन मुंडा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी विभिन्न खाद्यान्न भंडारों, थोक एवं खुदरा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण

बिभा संवाददाता

लोहरदगा । शुक्रवार 19 जून को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा. मोईन अख्तर के द्वारा अपर बाजार तथा ईस्ट गोला रोड स्थित विभिन्न खाद्यान्न भंडारों, थोक एवं खुदरा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में मेसर्स केशरी स्टोर, मेसर्स माँ भगवती भंडार, मेसर्स कपिल प्रसाद गल्ला दुकान, मेसर्स मित्तल स्टोर एवं मेसर्स धनपति ट्रेडर्स में बेची जा रही खाद्य सामग्रियों तथा दस्तावेजों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों यथा मूंगफली, चना दाल, चावल, नमक, अरहर दाल, फिंगर चिप्स आदि का वैधानिक नमूना संग्रह किया गया। जांच के क्रम में सभी प्रतिष्ठान संचालकों को एफएसएसएआई द्वारा निर्गत फूड लाइसेंस को दुकान में प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया गया। भंडारण में खाद्यान्न से भरी बोरियों को फर्श पर रखने के बजाय लकड़ी के पट्टों/तख्तों का प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में भंडारण क्षेत्र में चूहों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों को पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किसी एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल कराने हेतु निर्देशित किया गया। सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया। जब्त किए गए वैधानिक नमूनों के असफल पाए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाएगा। इस प्रकार का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक कर्मी रजनीश कुमार मौके पर उपस्थित थे।

हजारीबाग में ईसीसीई एवं प्री-स्कूल शिक्षा प्रशिक्षण का आयोजन

बिभा संवाददाता

हजारीबागः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) एवं प्री-स्कूल शिक्षा विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त हजारीबाग द्वारा की गई तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रशिक्षण में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करना तथा खेल-आधारित एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना था।प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने समूहों में कार्य करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में उपयोग हेतु 10 प्रकार की शिक्षण-अधिगम सामग्री का निर्माण किया। इन सामग्रियों का उद्देश्य बच्चों के सीखने को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण एवं प्रभावी बनाना है।अपने संबोधन में डीडीसी ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को बच्चों के समग्र विकास की आधारशिला बताते हुए ईसीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। डीएसडब्ल्यूओ ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को क्षेत्र में लागू कर बच्चों के बेहतर विकास और सीखने के परिणाम सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन एवं सुविधा प्रदान करने का कार्य पीपीआईए फेलोज निदा जरीन एवं मनीष द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में ईसीसीई पाठ्यचर्या, आयु-उपयुक्त शिक्षण गतिविधियों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री-स्कूल शिक्षा के प्रभावी संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

फिल्म 'सेरेंग' में लव जिहाद और आदिवासी समाज का अपमानः बबलू मुंडा

बिभा संवाददाता

रांची : केन्द्रीय सरना समिति के तत्वावधान में झारखंड में नागपुरी फिल्म सेरेंग एवं नागपुरी एल्बम पर अश्लीलता के विरुद्ध होटल गांगा आश्रम में प्रेस वार्ता रखी गई। केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि नागपुरी फिल्म सेरेंग में मुस्लिम लड़का और मुंडा लड़की के बीच प्रेम प्रसंग और मुंडा लड़की का धर्म परिवर्तन कर कर शादी करने का दृश्य फिल्माया गया जिसमें लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने एवं पूरे फिल्म में उरांव, मुंडा अनुसूचित जनजाति पर अवध टिप्पणी कर अपमानित किया गया है फिल्म के निमार्ता, निर्देशक नायक, नायिका एवं उनके सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई करने एवं फिल्म में प्रतिबंध लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरना समिति के प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के अगुवाई में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉ आशा लकड़ा से दिल्ली स्थित आवास में मिलकर 23 मई 26 को इस फिल्म एवं नागपुरी एल्बम में हो रहे अश्लीलता के विरुद्ध मांग पत्र सौंपा था,उसी के आलोक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई एवं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को सात दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रुप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आप मामले और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

केन्द्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि इस करवाई के बाद भी नागपुरी फिल्म के निमार्ता, निर्देशक नागपुरी एल्बम में फुअड़ता, अश्लीलता एवं आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करता है तो आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले वैसे नागपुरी कलाकारों को सामाजिक दंड दिया जाएगा।

मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने कहा कि नागपुरी फिल्म निमार्ता निर्देशक जब भी नागपुरी फिल्म या एल्बम बनाएं तो अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों की मान सम्मान धर्म संस्कृति रीति रिवाज एवं परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाएं। केंद्रीय सरना समिति के प्रधान महासचिव अशोक मुंडा ने कहा कि नागपुरी फिल्म सेरेंग में आदिवासी समाज के प्रति जो दिखाया गया है वह हमारे धार्मिक सामाजिक एवं सामूहिकता के विपरीत जिसके कारण आदिवासी संस्कृति गौरव पूर्ण इतिहास अस्तित्व अस्मिता के ऊपर सोची समझी कुटरघात है। संदीप उरांव ने कहा कि इस फिल्म में आदिवासी समाज का चरित्र को जानबूझकर कलंकित किया गया है जिसके कारण आदिवासी समाज में दुष्प्रभाव पड़ेगा। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, मुख्य पाहन जगलाल पाहन, प्रधान महासचिव अशोक मुंडा, महासचिव महादेव टोप्पो, जगन्नाथ तिर्की, संदीप उरांव, अनीता गाड़ी, सुरेंद्र लिंडा, आकाश मुंडा, विशाल मंडा, आदि उपस्थित थे।

आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की समाजसेवी सचिन कुमार साहू ने की निंदा

बिभा संवाददाता

लोहरदगा। जिले के समाजसेवी सचिन कुमार साहू ने रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फरर) कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज और राज्य की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गंभीर घटना बताया है।उन्होंने कहा कि घटना के बाद झारखंड पुलिस ने तत्परता,तकनीकी जांच और खुफिया तंत्र के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की तथा उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों,जांच टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरे मामले का जल्द खुलासा संभव हो सका है जो सराहनीय है।इस दौरान सचिन कुमार साहू ने कहा कि झारखंड पुलिस की सक्रियता और पेशेवर कार्यशैली के कारण अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया गया,जिससे लोगों का कानून-व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को शांति,सौहार्द और आपसी भाईचारे को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए,ताकि राज्य में सुरक्षित और सकारात्मक माहौल कायम रहे।

फसल से आगे : किसान की नई आर्थिक आजादी

लेखक

शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो, किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शिता और किसान-हितैषी नीतियों ने कृषि को सिर्फ ह्लउत्पादन का क्षेत्रह्व नहीं रहने दिया, बल्कि किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बना दिया है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियों का फोकस केवल ह्लकितना उत्पादनह्व पर नहीं, बल्कि ह्लकिसान की वास्तविक आय कितनी, खेती कितनी टिकाऊ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मजबूतह्व पर आ गया है। इसी सोच से दलहनझ्रतिलहन मिशन, कॉटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धनझ्रधान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोधझ्रनवाचार; सबको एक ही व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है।

आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम-सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (ढट-ड्क्रअठ) के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुँच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (ढटऋइ) ने देशभर में करोड़ों किसान-आवेदनों को कवर करते हुए फसल के नुकसान की स्थिति में एक मजबूत बीमा कवच दिया है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि-अवसंरचना, वेयरहाउस और कोल्ड-चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुँच- तीनों को मजबूत किया है। कृषि अब सिर्फ खेत की मेड़ तक सीमित नहीं है। डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट, बागवानी, मधुमक्खी-पालन, खाद्य-प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रामीण उद्योग, सौर ऊर्जा और सेवा-क्षेत्र; सब मिलकर नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपासझ्र तीनों क्षेत्र हमारी पूरी क्षमता से पीछे रहे। हम दालों और तेलों के लिए आयात पर निर्भर रहे और कपास में भी किसानों को वैश्विक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय दलहन मिशन के माध्यम से तुअर, उड़द, मसूर, चना और अन्य दालों का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू चेन पर काम हो रहा हैझ्र उच्च-उपज किस्में, क्लस्टर आधारित खेती, प्रसंस्करण इकाइयाँ, टरढ का सुदृढ़ ढाँचा, सरकारी खरीद, भंडारण और निर्यात तक। लक्ष्य यह है कि भारत दालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने, आयात बिल घटे और किसानों को उच्च मूल्य वाली इन फसलों से स्थायी आय मिले। इसी तरह तिलहन मिशन के जरिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और पाम ऑयल जैसी फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह केवल पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, किसानों को बेहतर दाम और देश की तेल सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में व्यापक रणनीति है। इसके साथ-साथ कॉटन मिशन के तहत कपास की उच्च-उपज और कीट-रोधी किस्में, उन्नत कृषि-प्रणालियाँ, कीट-प्रबंधन, फसल विविधीकरण, टेक्सटाइल वैल्यूझ्रचेन से बेहतर जुड़ाव और गुणवत्ता सुधार पर काम हो रहा है। कपास भारत के लाखों किसानों के लिए नकदी फसल है; मिशन का उद्देश्य है कि किसान को उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके।

तेजी से बढ़ती रासायनिक निर्भरता, मिट्टी की थकान और भूजल पर दबावझ्र ये सब हमें आगाह कर रहे हैं कि खेती के तरीके बदलने होंगे। इसी समझ के साथ हमारे विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज किया जाए, उनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए।

यह परिवर्तन धीरे-धीरे, वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहा है। छोटे किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाकर देखें; उन्हें प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधनों पर आधारित पैकेज, प्रमाणन, ब्रांडिंग और बाजार-जुड़ाव में मदद दी जा रही है। उद्देश्य यह है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े, रासायनिक लागत घटे, जलवायु झटकों के सामने फसलें अधिक टिकाऊ हों और उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद, पोषक भोजन मिल सके।

भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ ज़िले अलग-अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री धनझ्रधान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन ज़िलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं का कन्वर्जेन्स कर एक समग्र पैकेज दिया जा रहा हैझ्र सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषिझ्रउपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाजार-जुड़ाव; सबको एक साथ जोड़कर। सोच यह है कि योजनाएँ अलग-अलग ह्लसाइलोह्व में न चलें, बल्कि किसान के खेत और गाँव को केंद्र में रखकर सब मिलकर काम करें। इससे नीति का फोकस केवल ह्लकितना उत्पादनह्व से आगे बढ़कर इस पर आया है कि कहाँ उत्पादन कम है, वहाँ लक्षित निवेश और प्रयास से कैसे बढ़ाया जाए, और उससे किसान की आय कैसे ऊपर उठे।

उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में कई जगहों पर मिट्टी और पानी पर दबाव बढ़ा है। असंतुलित उर्वरक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन और सीमित फसल चक्र ने खेत की सेहत को प्रभावित किया है। यदि समय रहते दिशा न बदली जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कमजोर खेत और थकी हुई मिट्टी छोड़ेंगे। इस चुनौती को देखते हुए ह्लखेत बचाओ अभियानह्व शुरू किया गया है। यह अभियान केवल मिट्टी बचाने का नहीं, बल्कि किसान की आय, भोजन की गुणवत्ता और भविष्य की खाद्य सुरक्षा की रक्षा का अभियान है। इसके पाँच मुख्य संदेश हैं- हर किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करे, डीएपी और यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करे और संतुलित ठढङ, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव एवं नैनो उर्वरकों को अपनाए, हरी खाद, जैविक खाद और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के विरुद्ध सतर्क रहे और प्रशासन को तुरंत सूचना दे तथा प्राकृतिक खेती और जलवायुझ्रअनुकूल पद्धतियों की ओर संगठित रूप से बढ़े। लक्ष्य यह नहीं कि उर्वरक अचानक कम कर दिए जाएँ, बल्कि यह है कि हर किसान सही मात्रा, सही समय और सही मिश्रण का उपयोग करे, ताकि मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहे, लागत घटे और उत्पादन भी सुरक्षित रहे।

इन सभी प्रयासों की रीढ़ विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने 2014झ्र25 के बीच लगभग 3,000 जलवायु-सहनशील फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें सूखा, बाढ़, लू, लवणीयता और अन्य तनावों को झेलने की क्षमता है। कुल मिलाकर 3,800 से ज्यादा उच्च-उपज किस्में और 200 से अधिक बायोफोर्टिफाइड किस्में जारी की गई हैं, जो उत्पादकता के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी मजबूत करती हैं। डिजिटल कृषि मिशन और ह्लएग्रीस्टैकह्व के तहत किसान पहचान (त्र्श्ी१ क्ळ२), फसल प्लॉटों का डिजिटलीकरण, ड्रोन-आधारित सेवाएँ, कीट-रोग निगरानी, मौसमझ्रआधारित और लोकेशनझ्रस्पेसिफिक सलाह जैसी व्यवस्थाएँ बन रही हैं। इससे लैब से लैंड और डेटा से निर्णय तक की दूरी तेजी से कम हो रही है। ई-नाम, किसान सारथी, ङश्ङ नेटवर्क, मोबाइल संदेश, व्हाट्सऐप समूह, सामुदायिक रेडियो और सोशल मीडियाझ्र इन सबके माध्यम से वैज्ञानिक, विस्तारकर्मी और किसानझ्रनेता सीधे किसान से संवाद कर पा रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास को भी एक साथ, समग्र दृष्टि से देखा जा रहा है। सड़क, बिजली, इंटरनेट, स्व-सहायता समूह, त्रढड, ग्रामीण उद्योग और कौशल विकासझ्र ये सभी कार्यक्रम जब कृषि के साथ कदमझ्रताल करके चलते हैं, तभी गाँवों में रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ती है। आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की खाद्य, पोषण और जलवायु चुनौतियों के बीच अपने कृषि-तंत्र को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट है-किसान की आय बढ़े, उसकी मेहनत का उचित सम्मान और मूल्य मिले, दालों, तिलहनों और कपास में आत्मनिर्भरता से पोषण, तेल और वस्त्र सुरक्षा मजबूत हो। ढट-ड्क्रअठ, ढटऋइ, प्राकृतिक खेती, खेत बचाओ अभियान और जलवायु-अनुकूल तकनीकों से खेत की मिट्टी, पानी और किसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री धनझ्रधान्य कृषि योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले ज़िलों में लक्षित निवेश से क्षेत्रीय असमानता घटे और हर किसान आगे बढ़े। विज्ञान, अनुसंधान और डिजिटल तकनीक से खेती कुशल, लचीली, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बने। जब खेत बचेगा, तब किसान बचेगा। जब किसान बचेगा, तब कृषि बचेगी और जब कृषि बचेगी, तब भारत का भविष्य सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यही हमारी नई कृषि यात्रा का सार हैझ्र फसल से आगे, किसान के विश्वास और ग्रामीण भारत की समृद्धि की ओर।

(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं।)

संपादकीय

टेलीग्राम पर बैन

मई महीने में नीट प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार अति- सतर्कता के मूड में नजर आ रही है। लीक प्रकरण के पश्चात निशाने पर आने के बाद सरकार कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। इसी कड़ी में चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाम लगाने के निर्णय को लेकर विवाद अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये संघर्ष कर रही है। हकीकत यह है कि मई में प्रश्नपत्र लीक होने से मची अफरातफरी और विपक्ष के नेताओं के निशाने पर आने के बाद केंद्र सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। निस्संदेह, इस परीक्षा में आयोजक एजेंसियों की विश्वसनीयता और बीस लाख से ज्यादा प्रतिभागियों का भविष्य दांव पर लगा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय महत्व की परीक्षाओं को लेकर नीट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एटीए द्वारा परीक्षार्थियों का भरोसा फिर से कायम करने की कवायद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में रविवार को होने वाली नीट की पुनःपरीक्षा से ठीक पहले, सरकार का चर्चित मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर कुछ अवधि के लिये प्रतिबंध लगाना, अति सतर्कता को ही दशार्ता है। सरकार के इस अतिरेक सावधानी वाले रवैये को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने इस कदम का पुरजोर बचाव किया है। सरकार की दलील है कि इस क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म का बॉट इंफ्रास्ट्रक्चर लीक हुई सामग्री का तेजी से बड़े पैमाने पर प्रसार करने में मददगार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में देशवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूरे प्लेटफॉर्म को कुछ दिनों के लिये ब्लॉक करने से आनुपातिकता और प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। लोगों का मानना है कि सतर्कता, सावधानी और तंत्र में सुधार कर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

चिंतन-मनन

आभार जताना सीखो

मेरी एक संत मित्र थीं विमल। गर्मी के दिन थे और हम लोग गंगा तट पर बैठे हुए थे। गंगा तट पर बैठने से बड़ी ठंडी हवा लग रही थी। यूं तो बहुत गर्मी थी। अचानक से उन्होंने अपने झोले से आम निकाले और आम उन्होंने गंगा जी में उतार दिए ताकि ठंडे हो जाएँ और जब ठंडे हो गए तो उन्होंने एक मुझे दिया एक स्वयं लिया। उन्होंने आम हाथ में पकड़ा है और आम को देखती जा रही हैं। देखते-देखते उन्होंने कहा, यह आम का पेड़ जाने किस किसान ने कब बोया होगा, कितने पेड़ मर-मरा जाते हैं। चलते ही नही लेकिन यह पेड़ चलता रहा। सब झेल गया, आंधी तूफान सब झेल गया। मरा नहीं स्वस्थ रहा। अभी वह बड़ा हुआ। अभी उस पर बौर आए। फिर उस पर फल लगे और जाने कितने ही बार इस पेड़ पर कितने ही फल लगे होंगे और जाने किस-किसने खाए होंगे। लेकिन यह एक आम उतरा, टोकरी में गया। टोकरी से मंडी, मंडी से ट्रेडर, ट्रेडर से रीटेलर। और फिर अंत में रेहड़ी वाले के पास इतने आम थे, पर मैंने चुन कर कुछ आमों को निकाला और गंगा तट पर ये जो आम लाई हूं और उनमें से एक आम आपको दे दिया। पर यह आम मेरे हिस्से में आया। तो यह आम मुझ तक कितनी लम्बी यात्रा कर के आ रहा है। भावविभोर हो कर विमल ने कहा कि परमात्मा ने इस फल को खासम-खास मेरे लिए ही उगाया था। इसको मैं कहती हूं- संवेदनशील होना। इतने खेत, इतने पेड़, इतने आम, इतने रीटेलर, इतने रेहड़ी वाले, करोड़ों आम निकलते हैं। पर उन करोड़ों आमों में से यह एक छंट कर मुझ तक पहुंचा। भगवान ने खासम-खास यह आम मेरे लिए उगाया है तो यह तो परमात्मा का प्रसाद है और वह आम से ऐसे बात कर रही थीं जैसे आम उसकी बात को सुन रहा हो। और उस आम से कहती हैं, जब मैं तुम्हें खाऊंगी तो बहुत रस लेकर खाऊंगी और जब तू मेरे भीतर जाएगा तो तू मेरे भीतर ईश्वरीय प्रेम को और जगा देगा। ईश्वर ने प्रसाद भेजा है और इस ईश्वरीय प्रसाद को खा कर (क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं उससे न केवल हमारा शरीर बनता है बल्कि हमारे मन का भी तो निर्माण इसी से होता है) मेरे मन में ईश्वरीय प्रेम निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो वह आम से प्रार्थना कर रही हैं कि, जब तू मेरे भीतर जाए तो मेरे भीतर प्रेम बढ़े। जिस प्रभु ने तेरे शरीर को बनाया है मेरे शरीर के लिए, तो जब तू मेरे भीतर जाए तो उस ईश्वर के प्रति मेरे प्रेम को और गहरा कर देना। खयाल रहे, कोई अकलमंद आदमी इस कहानी को सुने तो शायद कहे कि यह औरत तो पागल लगती है, आम से बात कर रही है। वह पेड़, फल से चर्चा नहीं कर रही है, उस आम के भीतर भी मौजूद भगवत्ता को और अपने भीतर भी उस भगवत्ता को महसूस करते हुए अपने मन को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है, जहां छोटे से छोटा काम भी ईश्वर स्मरण के बगैर नहीं किया जा रहा।

अमेरिका-ईरान युद्धः 7500 मौत, 162 लाख करोड़ का नुकसान फिर शांति विराम

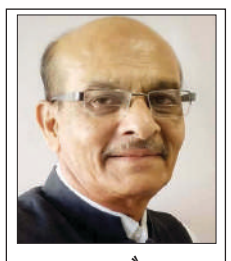

सनत जैन

मान्यता है इतिहास से सबक लिया जाता है। जो इतिहास से सबक लेते हैं, वे भविष्य में वह गलतियां नहीं करते हैं जो उनके पूर्वज कर चुके होते हैं। पर इतिहास से कोई सबक सीखता नहीं है, सभी को लगता है कि उनके पूर्वजों ने जो गलती की थी वह उनसे नहीं होगी। वह उनसे ज्यादा ताकतवर और समझदार हैं। इसलिए वह इतिहास की उन्हीं गलतियों को दोहराता है और एक बार फिर विनाश की ओर आगे बढ़ता है। विनाश के बाद विकास होने की गतिशीलता ही जन्म, मृत्यु और ब्रह्मांड को हमेशा क्रियाशील रखती है। यही कहा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। अमेरिका और इजराइल यह मानकर चल रहे थे कि एक सप्ताह के अंदर इजराइल की सत्ता को पलट देंगे। वहां पर उनकी मर्जी से नया राज कायम हो जाएगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल की मनमर्जी से चलेगा। उन्होंने ईरान के सुप्रीमो आयतुल्लाह खामेनेई और उनके बड़े-बड़े नेताओं की हमले में हत्या कर दी। एक स्कूल में हमला कर 165 से ज्यादा मासूम बच्चियों की हत्या कर दी। इसके कारण जो ईरान आंतरिक असंतोष झेल रहा था, सुप्रीमो खामेनेई और बच्चियों की हत्या के बाद ईरान एकजुट हो गया और उसने अमेरिका और इजराइल से पिछले 47 वर्षों में उसके साथ जो अत्याचार हुए थे इसका बदला लेने के लिए डू एंड डाई की स्थिति में आ गए।

अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति और अपने जीवन को बचाने के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उससे सारी दुनिया हैरान है। अमेरिका, ईरान युद्ध में अभी तक 7500 से ज्यादा मोतें हो चुकी हैं। 110 दिन चले इस युद्ध में जमीन पर फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी है। सारी लड़ाई ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से लड़ी गई। इसमें लगभग 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले कई दशकों में जो विकास हुआ था वह सब विनाश में तब्दील हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आपको सुपर हीरो मानकर चल रहे थे इस 110 दिन की लड़ाई में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इससे जो उनकी अजेय होने साख बनी हुई थी वह समाप्त हो गई। इजराइल को जो नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना कभी उसने नहीं की थी। गाजा में जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह से मारा गया था, ऐसा नरसंहार दुनिया के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लगता है ईश्वर ने उनके अहंकार और स्वयं को ईश्वर मानने की जो गलती की थी उसका दंड दिया है।

इस युद्ध में वैसे तो भारत का कोई लेना-देना नहीं था लेकिन जिस तरह से भारत ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है। गाजा के मामले में चुप्पी साधे रखी। इजराइल को भारत के प्रधानमंत्री ने अपना फादर लैंड बता दिया। इसकी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ रही है। भारत ने जहां ईरान जैसे पड़ोसी देश जो हर सुख-दुख में भारत के साथ होता था उसको खो दिया है। भारत की जनता को भी इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध कोई भी हो यह सिवाय विनाश के कुछ नहीं देता है। भारत में भी महाभारत युद्ध का एक इतिहास है। भगवान कृष्ण के होते हुए वह कौरवों से पांडवों को पांच गांव नहीं दिला पाए थे। युद्ध हुआ ना कौरव के हाथ कुछ लगा ना पांडवों के हाथ कुछ लगा। विनाश इतना बड़ा हुआ जिसका उल्लेख धर्म शास्त्रों में होने के बाद भी भारत पहली बार इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा रहकर एक तरह से पाप का भागी बन गया है। इसकी कीमत भारत की जनता को भी चुकानी पड़ रही है। बहरहाल जो भी घटनाएं होती हैं, उनसे सबक लिया जा सकता है। अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच में रोजाना हमले हो रहे हैं। भारी तबाही हो रही है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के इस युद्ध से यदि रूस और यूक्रेन कोई सबक ले लें और शांति विराम की पहल करें तो यह बहुत अच्छा कदम होगा। दुनिया के सभी देशों को इस युद्ध से सबक लेने की जरूरत है। यही कहा जा सकता है।

निर्णय लेने में ज्यादातर फिसड्डी क्यो रहती है कांग्रेस!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कार्यकताओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार जल्द घोषणा के संकेत मिलने के बावजूद अब तक हाईकमान की अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पुरानी टीम के साथ संगठन का काम चला कर रहे हैं।

प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने देहरादून पहुंचने पर स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद नई पीसीसी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी।लेकिन राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया ,हालांकि उन्होंने वर्चुअल सम्बोधन कर कार्यकर्ताओ का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की।प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

कांग्रेस हाईकमान प्रदेश संगठन की छोटी और प्रभावी टीम बनाकर नेताओं की जिम्मेदारियां तय करना चाहता है। हालांकि, वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने समर्थकों के नामों की लंबी सूची भेजे जाने के कारण कार्यकारिणी के गठन पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है।कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का वर्चुअल भाषण कांग्रेस कार्यकताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर गया है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता से संगठन को मजबूती मिलेगी।प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आमंत्रित तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं के मामले में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार सरकार को जवाब देगी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि राहुल के उदबोधन से संगठन को नई दिशा मिली है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती प्राप्त हुई।लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस समय से क्यो नही अपने निर्णय ले पाती।चाहे चुनाव में टिकट देने का मामला हो या फिर कार्यकारिणी गठन का मुद्दा कांग्रेस निर्णय लेने में ज्यादातर देरी ही करती है।साथ ही जमीन से जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ताओ के बजाए अवसरवादी आगे आकर कांग्रेस के चुनाव परिणामों को गुड़ गोबर कर देते है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने कांग्रेस की मौजूद चुनोतियाँ साफ दिखती है, गुटों में बंटी कांग्रेस इकाई का नेतृत्व करना, वह भी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बेहद कठिन कहा जा सकता है।वह भी तब जब कांग्रेस पार्टी सन 2017 और सन 2022 के दो विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, साथ ही राज्य की लगातार तीन लोकसभा चुनावों में भी एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है,जो पार्टी की कमजोर हालत को प्रमाणित करता है।दो बार के विधायक गणेश गोदियाल, जिन्हें कभी हरीश रावत का करीबी माना जाता था,का पुनः पदारूढ़ होने से उम्मीद है कि वे हरीश रावत को अपने से भी आगे करके चलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके है, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद उनकी जगह करन माहरा को दे दी गई,परन्तु कांग्रेस कोई चमत्कार नही कर पाई।

हरीश रावत ने स्वयं को पीछे करते हुए सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस को प्रीतम सिंह (जो पांच बार के विधायक हैं) के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। उनका यह बयान पार्टी में एकता का पहला कदम कहा जा सकता है।जब कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में थी, तब भी हरीश रावत लगातार संघर्षों में फंसे रहे, पहले एन.डी. तिवारी को उनका हक दे दिया गया,जिससे टकराव की स्तिथि बनी रही और बाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बनाकर फिर से हरीश रावत को किनारे करने की कोशिश की गई।लेकिन प्राकृतिक आपदा में विजय बहुगुणा के फेल हो जाने के कारण उनकी जगह सन 2014 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद पर रिप्लेस किया गया।यह बदलाव उस समय आया जब विजय बहुगुणा पर जून 2013 की केदारनाथ आपदा से निपटने को लेकर भारी आलोचना हो रही थी क्योंकि आपदा के समय विजय उत्तराखंड के बजाए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे।

पिछले दिनों करन माहरा को सीडब्ल्यूसी और प्रीतम सिंह को सीईसी में शामिल किया जाना, कांग्रेस हाईकमान द्वारा राज्य में प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, इसे हरीश रावत को उनकी नाखुशी के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व से जोड़कर रखने की रणनीति भी माना जा रहा है।अपनी बढ़ती उम्र में भी बेहद सक्रिय कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत के पास वर्तमान में कोई ठोस दायित्व नही है,फिर भी वे राज्य के सर्वाधिक सक्रिय नेता कहे जा सकते है।ऐसे में उनकी अनदेखी करके कांग्रेस कोई भी चुनाव फिलहाल नही लड़ सकती और यदि ऐसा हुआ तो फिर से कांग्रेस की लुटिया डूबने में देर नही लगेगी।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा भी है कि वे पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष तक बनने को तैयार है। कांग्रेस ही नही अन्य राजनीतिक दलों को भी उत्तराखंड के इस सर्वमान्य नेता का सम्मान करना चाहिए।

(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

तब बाढ़ में भी नहीं डूबेंगे धान के पौधे !

तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। अब जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीनों का पता लगाया है जिनके जरिए चावल के पौधे का विकास इस तेजी से बढ़ाया जा सकता है कि वह पानी में डूबे ही नहीं।

भारत में चावल उगाने वाले किसान जहां बरसात के लिए तरसते हैं, वहीं उससे बहुत डरते भी हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं, क्या बरसात ठीक वक्त पर आएगी, ज़्यादा तेज और लंबी तो नहीं होगी, कितनी बार फसल बरसात की वजह से खराब हो जाती है और हज़ारों किसानों के लिए भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों में भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।

अक्सर यह देखा गया है कि तेज बरसात की वजह से चावल के पौधे पानी में बिलकुल डूब जाते हैं। खेतों मे बढ़ता हुआ जलस्तर चावल के पौधों के लिए सामान?यतर अच्छा ही रहता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि पौधे के उपरी हिस्से हवा के संपर्क में बने रहें। हालांकि मानसूनी इलाकों में बरसात और बाढ की वजह से चावल के खेतों में पानी इतना ज?यादा भर जाता है कि धान के पौधे बिल्कुल डूब जाते हैं तथा इससे वे सड़ने लगते हैं और मर भी जाते हैं।

गौरतलब है कि गहरे पानी में उगनेवाले चावल की प्रजाति को जलजमाव से कोई समस्या नहीं होती। पानी के साथ-साथ उसके तने वाले डंठल भी बढ़ते जाते हैं।

जापान के नागोया विश्वविद्यालय के मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

गहरे पानी में उगने वाले चावल के पौधे, पानी की गहराई से ऊपर बने रहने के लिए, एक मीटर तक बढ़ सकते हैं। वे हवा के संपर्क में बने रहने के लिए ऐसा करते है। वे अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन उसके जरिए पौधा पानी की सतह से उपर पहुंच सकता है और ऑक्सीजन पा सकता है। यह कुछ ऐसा ही है कि जब आप गोताखोरी कर रहे होते हैं, तो पानी से ऊपर निकली एक नली से सांस लेते हैं।

बरसात के समय ऐसे चावल के तने 25 सेंटीमीटर प्रतिदिन की एक अनोखी गति से बढ़ सकते हैं। अशिकारी और उनकी टीम ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए इस चावल के जीनों से यह समझने की कोशिश की कि चावल बरसात के वक्त अपने विकास को किस तरह नियंत्रित करता है। अध्ययनों से अब तक जितना पता चला है वह यह है कि एक गैसीय विकास-हॉर्मोन एथीलिन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसाकि नीदरलैंड के उएतरेश्त विश्वविद्यालय के रेंस वोएसेनेक बताते हैं-

जब पौधा पूरी तरह पानी में डूब जाता है तब यह गैस ठीक तरह से मुक्त नहीं हो पाती। यू कहें कि वह पौधे में ही कैद हो जाती है। यानी पौधे में एथिलिन की मत्रा बढ़ने लगती है। यह पौधे के लिए संकेत है कि वह पानी में डूब रहा है और उसे कुछ करना है।

जापानी विशेषज्ञों ने पता लगाने की कोशिश की कि कौन से जीन इस स्थिति में सक्रिय होते हैं। उन्होने ऐसे जीन पाए जिनको वे गोताखोरी में इस्तेमाल होनेवाली नली के अनुरूप स्नोर्कल जीन कहते हैं। ये जीन तभी सक्रिय होते हैं जब पौधे के तने में एथिलिन की मात्रा बढ़ने लगती है। वे पौधे के विकास को तेज करने वाले दूसरे तत्वों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। मोतोयुकी अशिकारी कहते हैं-

हमने क्रॉमोसोम 1,3 और 12 पर यह तथाकथित नलिका जीन पाए। उन्हें यदि सामान्य चावल के पौधों में भी मिलाया जा सके, तो बरसात के वक्त सामान्य चावल के पौधे भी वही करेंगे जो गहरे पानी में उगने वाला चावल करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम चावल की हर प्रजाति को गहरे पानी में उगने वाले चावल की प्रजाति बना सकते हैं।

यानी इन जीनों की मदद से चावल की उस फसल को बचाया जा सकता है जो पानी की अधिकता के प्रति बहुत संवेदनशील है। जहां अक्सर बाढ आती है वहां के किसानों की इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक और समस्या भी दूर हो सकती है - गहरे पानी में उगने वाला चावल बहुत ही कम फसल देता है, प्रति हेक्टेयर सिर्फ एक टन जो उपजाऊ क़िस्मों की तुलना में सिर्फ 20 फीसदी के बराबर है। नीदरलैंड के विशेषज्ञ रेंस वोएसेनेक बहुत ही आशावादी हैं-

विकास के लिए जिम्मेदार इन जीनों के बारे में पता चल जाने के बाद अब हम चावल की अलग-अलग प्रजातियों के बीच प्रकृतिक संवर्धन के जरिए, यानी वर्णसंकर के जरिए भी इन जीनों को उनके पौधे में डाल सकते हैं। इसके लिए किसी जीन तकनीक जरूरत ही नहीं हैं।

जापान के विशेषज्ञों ने यह काम शुरू कर भी दिया है। उनके अध्ययनों से एक बार फिर पता चलता है कि पौधों के संवर्धन के लिए उनके जीनों में असामान्य गुणों की तालाश कितनी जरूरी है।

कुदरती खेती का एक अनूठा प्रयोग

भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रकृति की कृपा तथा हमारे किसानों कि आर्थिक मेहनत से हमारी भूमि सदा उपजाऊ रही है। प्राचीन समय में हमारी खेती प्राकृतिक संपदा व संसाधनों पर ही निर्भर थी और देश की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर पाती थी। जैसे-जैसे देश में शहरीकरण व औद्योगिकरण बढते गये , गांवों से लोग खेती को छोड़ शहरों की ओर आते गये। प्राकृतिक खेती पध्दति कम होती गई और रासायनिक खाद आदि का प्रयोग बढता गया। ज़मीन की उत्पादकता घटती गई और साथ ही किसान की आय भी। सन 1965 में भारत में हरित क्रांति आयी जिससे उपज तो बढी मगर रासायनिक उरवरक तथा अन्य उत्पादों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से मिटटी की उत्पादकता भी कम होती गयी।

यूरोप, अमरीका व एशिया में सन् 1940-50 के दकों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं पर बहुत प्रयोग किये गये। खेती कि ये विधायें भारत में सन 1980 के दशक से आगे बढी हैं। जैविक खेती की पद्धति में रासायनिक पध्दाथों का प्रयोग वर्जित है। प्राकृतिक खेती में केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं व संसाधनों का ही प्रयोग होता है। आधुनिक खेती या रासायनिक खेती प्रकृति के खिलाफ है। रासायनिक खादों व कीटनाशकों से हमारे खेतों की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और जैव तत्त्व मर रहे हैं और वह बंजर हो जाती है। कुदरती खेती प्रकृति के साथ होती है। यद्यपि प्राकृतिक खेती की शुरूआत जापान के कृषि वैज्ञानिक फुकुओवा ने की है लेकिन हमारे यहां भी ऐसी खेती होती रही है। मंडला के बैगा आदिवासी बिना जुताई की खेती करते हैं जिसे झूम खेती कहते हैं।

भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद ज़िले के एक फार्म मे लगभग पिछले 25 वर्षों से प्राक्रतिक खेती, जिसे कुदरती खेती भी कहते है, हो रही है। करीब 12 एकड़ के इस फार्म में सिर्फ 1 एकड़ में खेती की जा रही है। यहां बिना जुताई (नो टिलिग) और रासायनिक खाद के खेती की जा रही है। बीजों को मिट्टी की गोली बनाकर बिखेर दिया जाता है और वे उग आते हैं। यह सिर्फ खेती की एक पद्धति भर नहीं है बल्कि जीवनशैली है। यहां का अनाज, फल पानी और हवा शुध्द है। यहा कुआं है, जिसमें पर्याप्त पानी है। बिना जुताई के खेती मुश्किल है, ऐसा लगना स्वाभाविक है। पहली बार सुनने पर विश?वास नहीं होता लेकिन देखने के बाद सभी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। दरअसल, इस पर्यावरणीय पद्धति में मिट्टी की उर्वरता उत्तारोतर बढ़ती जाती है।

बाकी के 11 एकड़ में सुबबूल (आस्टेलियन अगेसिया) का जंगल है। सुबबूल एक चारे की प्रजाति है। इस जंगल से मवेशियों का चारा और लकड़ियां मिल जाती हैं। लकड़ियों की टाल है, जहां से जलाऊ लकड़ी बिकती हैं, जो फार्म की आय का मुख्य स्रोत है। एक एकड़ जंगल से हर वर्ष करीब ढाई लाख रूपये की लकड़ी बेच लेते हैं।

गेहूं के खेतों में हवा के साथ गेहूं के हरे पौधे लहलहाते हैं। खेत में फलदार और अन्य जंगली पेड़ हैं जिनके नीचे गेहूं की फसल होती है। आम तौर पर खेतों में पेड़ नहीं होते हैं लेकिन यहां अमरूद, नीबू और बबूल के पेड़ हैं जिन के कारण खेतों में गहराई तक जड़ों का जाल बुना रहता है। इससे भी जमीन ताकतवर बनती जाती है। अनाज और फसलों के पौधे पेड़ों की छाया तले अच्छे होते हैं। छाया का असर जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर करता है। चूंकि यहां जमीन की उर्वरता अधिक है, इसलिए पेड़ों की छाया का फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।

इन खेतों में पुआल, नरवाई, चारा, तिनका व छोटी-छोटी टहनियों को पड़ा रहने देते हैं, जो सड़कर जैव खाद बनाती हैं। खेत में तमाम छोटी-बड़ी वनस्पतियों के साथ जैव विविधताएं आती -जाती रहती हैं। और हर मौसम में जमीन ताकतवर होती जाती है। इस जमीन में पौधे भी स्वस्थ और ताकतवर होते हैं जिन्हें जल्द बीमारी नहीं घेरती।

यहां जमीन को हमेशा ढककर रखा जाता है। यह ढकाव हरा या सूखा किसी भी तरह से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस ढकाव के नीचे अनगिनत जीवाणु, केंचुए और कीड़े-मकोड़े रहते हैं और उनके ऊपर-नीचे आते-जाते रहने से जमीन पोली और हवादार व उपजाऊ बनती है।

आमतौर पर किसान अपने खेतों से अतिरिक्त पानी को नालियों से बाहर निकाल देते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जाता। बारिश में कितना ही पानी गिरे, वह खेत के बाहर नहीं जाता। खेतों में जो खरपतवार, ग्रीन कवर या पेड़ होते हैं, वे पानी को सोखते हैं। इससे एक ओर खेतों में नमी बनी रहती है, दूसरी ओर वह पानी वाश?पीकृत होकर बादल बनता है और बारिश में पुन् बरसता है। इसके विपरीत, जब जमीन की जुताई की जाती है और उसमें पानी दिया जाता है तो खेत में कीचड़ हो जाती है। बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता और तेजी से बहता है। पानी के साथ खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इस तरह हम मिट्टी की उपजाऊ परत को बर्बाद कर रहे हैं और भूजल का पुनर्भरण भी नहीं कर पा रहे हैं। साल दर साल भूजल नीचे चला जा रहा है।

यहां खेती भोजन की जरूरत के हिसाब से होती हैं, बाजार के हिसाब से नहीं। जरूरत एक एकड़ से ही पूरी हो जाती है। यहां से अनाज, फल और सब्जियां मिलती हैं, जो परिवार की जरूरत पूरी कर देती हैं। जाड़े मे गेहूं, गर्मी में मक्का व मूंग और बारिश में धान की फसल ली जाती है। कुदरती खेती में भूख मिटाने के साथ समस्त जीव-जगत के पालन का विचार है। इससे मिट्टी-पानी का संरक्षण होता हैं। इसे ऋषि खेती भी कहते हैं क्योंकि ऋषि मुनि कंद-मूल, फल और दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, बहुत कम जमीन पर मोटे अनाजों को उपजाते थे। वे धरती को अपनी मां के समान मानते थे, उससे उतना ही लेते थे जितनी जरूरत थी। अत- कुदरती खेती का यह प्रयोग सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

श्रीनगर सीमेंट फैक्ट्री में चिमनी फटने से आग, 7 मजदूर झुलसे, एक गंभीर

श्रीनगर (एजेंसी)। श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में गुरुवार देर रात चिमनी में आग लगने से सात मजदूर झुलस गए। इनमें एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य छह अस्पताल में उपचाराधीन हैं। गुरुवार देर रात हुए इस हादसे में फैक्ट्री की चिमनी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां काम कर रहे श्रमिक आग और तेज गर्मी की चपेट में आ गए। फैक्ट्री प्रबंधन और राहत दल ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर सभी घायलों को श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे मजदूर को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे मजदूर की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी छह मजदूरों की स्थिति स्थिर है। इस बीच पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि फैक्ट्री में निर्धारित सुरक्षा मानकों और अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था या नहीं। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आया है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर : आरोप-प्रत्यारोप का दौर

पटना (एजेंसी)। बिहार में एक नया राजनीतिक विवाद तब खड़ा हो गया जब कोर्ट के आदेश पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के खिलाफ पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। यह मुकदमा अनुष्का के भाई आकाश यादव ने दर्ज कराया है, जिनका नाम सार्वजनिक रूप से तेज प्रताप से जोड़ा जाता रहा है। बिहार पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है। एएसपी दिव्यांजलि जायसवाल के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और उन्होंने सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। पुलिस का कहना है कि ये धमकियां कथित तौर पर अमेरिका के एक नंबर से फोन करके दी गई थीं। एफआईआर के मुताबिक, यह घटना 6 जून को हुई थी, जब तेज प्रताप और उनके सहयोगी मोतीलाल यादव कथित तौर पर पाटलिपुत्र इलाके में आकाश यादव के घर गए थे, जबकि आकाश खाटू श्याम की तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जबरन घर में घुसने की कोशिश की और वहां मौजूद परिवार के सदस्यों को धमकी दी। आकाश यादव की ओर आरोप लगाया गया है कि उनके परिवार को लेकर धमकियां दी गईं और बाद में उन्हें मोतीलाल और एक अन्य व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को एक आपराधिक गिरोह का सदस्य बताया। शिकायत के अनुसार, कॉलर ने उन्हें तेज प्रताप के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ भी न बोलने की चेतावनी दी।

शोपियां में लापता तीन युवक विस्फोटक के साथ गिरफ्तार, आतंकी संगठन से संबंध का शक

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान 31 मई से लापता चल रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में इनके तार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका जाहिर की गई है। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किए युवकों के पास से दो हैंड ग्रेनेड, 2.5 किलोग्राम पीईके (प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी), चार मोबाइल फोन और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित पोस्टर बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारियां दक्षिण कश्मीर जिले के पुडसू इलाके से की गईं। गिरफ्तार युवकों की पहचान एजाज अहमद खांडे, अरबाज अहमद मीर और नासिर अहमद डार के रूप में हुई है, जो सभी शोपियां जिले के बेगामा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, ये तीनों 31 मई से अपने घरों से लापता थे और माना जा रहा है कि वे हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए थे। वर्तमान में पुलिस इन तीनों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि आतंकी मॉड्यूल, भर्ती प्रक्रिया और उनके सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस ने संकेत दिया है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां या सामग्री की बरामदगी हो सकती है। जांच एजेंसियां इनके सीमा पार के आतंकी आकाओं से संभावित संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं, जो क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार एनकाउंटर पर बीजेपी ने उठाए सवाल, शाह और सीएम से जांच की मांग

भोजपुर (एजेंसी)। बिहार के भोजपुर जिले में हुए एक पुलिस एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी मांग की है। बीजेपी नेता सिन्हा ने घटना पर दुख जताकर कहा कि जनता के मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं का निष्पक्ष उत्तर सामने आना चाहिए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन को स्वागतयोग्य बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि न्याय केवल प्रारंभिक कार्रवाई से पूरा नहीं होता। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी आशंका की गुंजाइश न रहे। सिन्हा ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का दायित्व है, लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में अधिकारों के दुरुपयोग या लापरवाही की पुष्टि होती है, तब दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास से भी जुड़ा है। दूसरी ओर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एनकाउंटर को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी की पुलिस प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पण के उपरांत गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई, जो हृदय विदारक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौबे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस निर्मम हत्या पर संज्ञान लेने और हत्यारे पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उच्चस्तरीय जांच का आदेश देने की अपील की। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी आग्रह किया कि वे 48 घंटे के भीतर हत्यारों को जेल भेजकर बिहार में सुशासन का परिचय दें।

दल-बदल रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, सीजेआई ने पूछा पार्टी का नाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजनीतिक दलों में नेताओं के दल-बदल को रोकने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने याचिका पर सुनवाई से इंकार कर याचिकाकर्ता से पूछा कि वे किस पार्टी की बात कर रहे हैं। याचिका में नेताओं के भ्रष्टाचार और दल-बदल में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

वकील सी.आर. जया सुकिन ने बताया कि देश में पार्टियों के नेता या रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या धमकियां देकर परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ताकि उन्हें पार्टी बदलने पर मजबूर कर सके। सुकिन ने तर्क दिया कि यह लोकतंत्र को तबाह करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक राज्य पूर्वी भारत में और दूसरा मध्य भारत में है, जहाँ पार्टी नेता लगातार दल बदल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि विधानसभा अध्यक्षों को नेताओं के इस्तीफे की जांच करनी चाहिए, क्योंकि वे अक्सर मीडिया के सामने इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं।

याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई ने सवाल किया, आप किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रहे हैं? आपके राज्य में तब पार्टियां बदलती रहती हैं। उन्होंने याचिका को अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित बताकर खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है और इसतरह के मामलों में अदालत के दखल देने का कोई आधार नहीं दिखाता है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब देश के विभिन्न हिस्सों में दल-बदल की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 सांसदों ने वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी से अलग होकर नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर लिया। राज्य में विधायकों ने भी अपना अलग गुट बना लिया है और कोर्ट ने भी रीताब्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के छह सांसद जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं और शिवसेना को अपना समर्थन दे सकते हैं। ये संकेत तब और पुख्ता हुए जब गुरुवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक में 9 में से केवल 6 सांसद ही उपस्थित हुए।

सपा पर हमलावर राजभर की पार्टी में टूट का दावा, खुद के तीन विधायक बागी!

लखनऊ (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट के दावों के बीच, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमलावार हैं। राजभर ने दावा किया था कि 23 सपा सांसद उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संपर्क में हैं। हालांकि, अब उनके बेटे अरुण राजभर के डिबेट के दौरान खुद सुभासपा में आंतरिक कलह और टूट की खबरें सामने आई हैं। डिबेट के दौरान, अरुण ने सपा पर निशाना साधकर शिवपाल सिंह यादव के भाजपा से संपर्क साधने की बात कही, लेकिन पत्रकार ने पलटकर उनकी अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या और निष्ठा पर सवाल उठा दिए। पत्रकार के पूछने पर कि उनकी पार्टी के कितने विधायक सपा का झंडा लगाकर घूमते हैं, अरुण ने स्वीकार किया कि उनके 7 विधायकों में से तीन विधायक इसतरह के हैं। इस पर पत्रकार ने कहा कि आपकी पार्टी खुद ही टूट गई है। इन तीन विधायकों में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी शामिल हैं, जो सुभासपा का झंडा नहीं लगाते। इसके अतिरिक्त, ओम प्रकाश राजभर द्वारा जगदीश नारायण राय से नाराजगी का जिक्र भी किया गया, यह दर्शाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं दावा किया गया है कि सुभासपा के दो-तिहाई विधायक अखिलेश यादव के पास हैं और सपा जब चाहे उनकी पार्टी का अपने में विलय कर सकती है। हालांकि, अरुण राजभर ने दावे को सिरे से खारिज कर अपनी सफाई देकर कहा कि केवल झंडा लगाने से पार्टी नहीं टूटती। इस घटनाक्रम ने जहां सुभासपा के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े हुए हैं, वहीं विडंबना भी साफ दिखाई दे रही है कि जो पार्टी दूसरों में टूट का दावा कर रही थी, वह खुद ही बगावत के आरोपों से जूझ रही है।

अयोध्या राम मंदिर: सुरक्षा पर 11 माह में 10 करोड़ खर्च, फिर भी चोरी

-जांच के घेरे में कई बड़े और ताकतवर लोग

अयोध्या (एजेंसी)। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के बीच अब सुरक्षा चूक और करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद कथित चोरी का मामला गरमा गया है। बीते 11 महीनों में मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद दान पेटियों में अनियमितता की शिकायत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में अब विशेष जांच दल की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका दायरा सिर्फ कथित चोरी तक सीमित न रहकर पूरे सिस्टम को खंगाल रहा है, जिससे कई बड़े नाम जांच के घेरे में आ गए हैं।

17 साल से एक ही जगह तैनात आरएमओ जांच के घेरे में इस जांच में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर (आरएमओ) का है। यह वही अधिकारी है जिसके जिम्मे मंदिर परिसर की सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जिम्मेदारी है। सूत्र बताते हैं कि यह अधिकारी लगभग 17 वर्षों से मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इतने लंबे समय तक उसका तबादला न होना भी जांच के दायरे में है। एसआईटी सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, रिकॉर्डिंग सिस्टम, बैकअप व्यवस्था, डेटा संरक्षण और तकनीकी नियंत्रण से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीकी से जानकारी जुटा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के सबसे सुरक्षित धार्मिक परिसरों में से एक, जहां सैकड़ों कैमरे और बहुस्तरीय सुरक्षा मौजूद है, वहां यह चूक आखिर कैसे संभव हुई? शुरुआत में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर केंद्रित रही यह जांच अब अपना दायरा बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी अब उन लोगों की भूमिका भी समझने की कोशिश कर रही है जो मंदिर की सुरक्षा, निगरानी और प्रवेश व्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। इसमें तकनीकी स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि किसी भी बड़े परिसर में होने वाली गतिविधियों को समझने के लिए केवल घटना नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। यह जांच अब केवल चढ़ावे की कथित चोरी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र, प्रवेश नियंत्रण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा का विषय बन गई है। 10 करोड़ के सुरक्षा कवच के बावजूद हुई यह सेंधमारी अयोध्या की प्रतिष्ठा और पारदर्शिता पर गहरे सवाल छोड़ रही है, जिसके जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएंगे।

200 लोगों से पूछताछ की तैयारी

200 लोगों से पूछताछ की तैयारी, श्रद्धालुओं के मन में भी सवाल इस मामले में अब तक 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और सूत्रों के अनुसार, लगभग 200 लोगों से पूछताछ की योजना पर काम चल रहा है। कई कर्मचारियों को दोबारा बुलाया गया है और उनके बयान फिर से दर्ज किए जा रहे हैं, जो जांच की गंभीरता को दर्शाता है। रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच भी इस मामले की चर्चा साफ सुनाई दे रही है और उनके मन में भी यही सवाल है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित धार्मिक स्थलों में से एक में ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई।

विपक्षी दलों की बगावत से मानसून सत्र में दिख सकता है राजनीतिक बदलाव का असर

-महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराने के कुछ ही कदम दूर है एनडीए

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजनीति ने पिछले दो हफ्तों में एक ऐसा नया मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस पूरे राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा असर संसद के आगामी मानसून सत्र में देखने को मिल सकता है, जहां सरकार एक बार फिर महिलाओं के आरक्षण पैकेज से जुड़े संविधान संशोधन और परिसीमन बिल को पास कराने की तैयारी में है।

बता दें इसी साल अप्रैल के महीने में एकजुट विपक्ष के चलते लोकसभा में यह अहम बिल मात्र 54 वोटों की कमी की वजह से गिर गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अगर यह बिल दोबारा संसद में आता है तो इसके पास होने की संभावना तेज हो गई है। इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुई बगावत और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मंडराते संकट को माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत करते हुए अपना एक अलग गुट बना लिया है और वे एक नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं, जो अब सीधे तौर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में भी ऐसी बगावती ऊहापोह देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नौ सांसदों में से छह सांसद पाला बदलकर शिंदे की शिवसेना के साथ जाने की तैयारी में हैं।

ऐसे में एक तरफ टीएमसी के सांसद और दूसरी ओर उद्धव गुट के सांसदों का बिखराव और बगावत देखने को मिलेगा तो यह कहना थोड़ा भी गलत नहीं होगा कि इन तमाम सियासी उलटफेर का सीधा फायदा केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार को मिल सकता है, जो मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच सकती है। अब इस सियासी उठा-पटक के बीच लोकसभा के गणित को समझें तो कुल 543 सीटों में से दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि 3 सीटें फिलहाल खाली हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में इस समय टीएमसी के बागी सांसदों को मिलाकर एनडीए के पास कुल 318 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 184 और गैर-गठबंधन दलों के पास 38 सांसद मौजूद हैं। नियम के मुताबिक बिल पास होने के लिए सदन में वोटिंग के वक्त मौजूद सांसदों की संख्या मायने रखती है और पिछले अनुभवों के आधार पर देखें तो सरकार को दो-तिहाई का आंकड़ा छूने के लिए 54 और वोटों की जरूरत थी। देखा जाए तो अब इस जादुई आंकड़े को हासिल करना सरकार के लिए आसान हो गया है, क्योंकि टीएमसी के 20 बागी और उद्धव गुट के 6 संभावित बागी सांसदों के आने से यह कमी घटकर सिर्फ 28 वोटों की रह जाएगी।

इसके अलावा एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यह हुआ है कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके का कांग्रेस से नाता टूट चुका है और वह विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और डीएमके के बीच बातचीत चल रही है और अगर डीएमके की मांगें मान ली जाती हैं, तो उसके 22 सांसदों के समर्थन के साथ एनडीए का आंकड़ा 348 तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे बहुमत के लिए केवल छह और वोटों की दरकार होगी।

चूंकि बचे संभावित 6 वोटों के लिए केंद्र की एनडीए सरकार की रणनीति अहम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बयानों के मुताबिक इस आखिरी 6 वोटों की कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी की नजर विपक्षी गठबंधन की कुछ बेहद छोटी पार्टियों पर है, जिनमें महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है।

वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है और एनडीए के पास अभी 150 सांसद हैं। अगर यहां भी डीएमके के 8 सांसदों का समर्थन मिल जाता है, तो यह आंकड़ा 158 हो जाएगा और वहां भी सरकार बहुमत से सिर्फ छह वोट दूर रह जाएगी, जिसे टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव और अन्य छोटे दलों के सहयोग से आसानी से हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर यदि केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में यह जादुई आंकड़ा जुटाने में कामयाब रहती है, तो आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की न सिर्फ धमाकेदार वापसी होगी बल्कि देश में एक देश एक चुनाव जैसे बड़े और कड़े कानूनों को लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

बसपा सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी पूंजीपतियों या धन्नसेठों के सहारे नहीं

-मायावती ने दिया- 5 लाख मुलाकात, 3.35 करोड़ टिकट वाले दावों पर कड़ा बयान

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उत्तरप्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कथित वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में, पाल को कथित तौर पर बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती से मुलाकात के लिए पाँच लाख और पार्टी का विधानसभा टिकट हासिल करने के लिए 3.35 करोड़ रुपये की बात करते दिखाया गया है। इन गंभीर आरोपों पर अब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़कर इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

पूर्व सीएम मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने वाली, गरीब, शोषित-पीड़ित और उपेक्षितों के संवैधानिक हक व न्याय के लिए

प्रतिबद्ध सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बसपा बड़े-बड़े पूंजीपतियों या धन्नासेठों के सहारे नहीं, बल्कि अपने लोगों के तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है। यह बात संकीर्ण, जातिवादी, साम्प्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों को फूटी आँख नहीं सुहाती, और इसकारण वे चुनाव नज़दीक आने पर तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर बसपा व उसके नेतृत्व को बदनाम करने में लग जाते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि मीडिया का एक वर्ग अन्य पार्टियों की चुनावी जुगाड़ से ध्यान भटकाने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि बसपा को मिलने वाला आर्थिक सहयोग कानूनी तौर पर उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही खर्च होता है, जो किसी से छिपा नहीं है। मायावती ने बताया कि विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य छोटे-बड़े पदाधिकारी भी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने में जुटे हैं। उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि इन सवालों को उनकी पूरी फेस वैल्यू पर लिए बिना, उसकी गहराई में जाना उचित नहीं है।

बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे विरोधी पार्टियों के इसतरह के प्रायोजित षड्यंत्रों का शिकार न हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें। उन्होंने कहा कि बसपा की जबरदस्त तैयारियों को देखकर ही विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। मायावती ने अपने बयान का अंत जय भीम, जय भारत के नारे के साथ किया।

क्या फिर टूटेगी एनसीपी? अब शरद पवार के नेता सुनेत्रा पवार की पार्टी के संपर्क में

-शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर ऐसी किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश में

मुंबई (एजेंसी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के कई नेता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, अब तक किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर दावा नहीं किया है। खास बात है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद जल्द ही पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी में दरार हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने बताया है कि एनसीपी (एसपी) के कुछ सांसद एनसीपी के साथ संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि इसे लेकर गतिविधियां जारी हैं। खबर है कि चर्चा में सांसद पार्थ पवार भी मौजूद थे। फिलहाल, ये नेता कौन हैं, इसे लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो सकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि सीनियर पवार जल्द ही सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। इन घटनाक्रमों से चिंतित होकर, शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर ऐसी किसी भी स्थिति को टालने की कोशिश में हैं। प्रस्तावित बैठक में वह सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं और शिकायतों को सुनेंगे और आंतरिक संवाद को मजबूत करेंगे। अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि ये सांसद राज्यसभा से हैं या लोकसभा से। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं। जबकि, एनसीपी के पास सिर्फ 1 ही सांसद है। इधर, राज्यसभा में शरद पवार ही सांसद हैं। एनसीपी के मामले में यह आंकड़ा 4 पर है। रिपोर्ट के मुताबिक छह बागी सांसद शुक्रवार को पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। इनके शिवसेना में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों ही गुट स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शिवसेना यूबीटी के छह सांसद इस अवसर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल होंगे। व्हिप जारी होने के बावजूद इन सांसदों ने अपनी पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था।

अल-नीनो का बढ़ता खतरा: भारत के लिए अगले पांच महीने चुनौतियों से भरे

-कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा प्रभाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में इस वर्ष मॉनसून की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी धीमी रही है, जिसने देश के कई हिस्सों में चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 जून की शुरुआत में भले ही केरल पहुंच गया हो, लेकिन इसकी आमद सामान्य से कुछ विलंब से हुई, और प्रारंभिक बारिश भी कई क्षेत्रों में कमजोर दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अब एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अल-नीनो का पूरा प्रभाव अभी तक देखा नहीं गया है, और आने वाले जुलाई से नवंबर तक के महीने भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसका सीधा असर कृषि, जल संसाधनों और समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 में अल-नीनो जून में अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा, लेकिन जुलाई-अगस्त में इसके मध्यम होने और सितंबर तक मजबूत होने की प्रबल संभावना है। एनओएए और आईएमडी जैसे प्रमुख मौसम संगठनों के अनुसार, जुलाई-अगस्त तक अल-नीनो के पूरी तरह विकसित होने की संभावना 80-90 प्रतिशत से भी अधिक है। पिछले कई दशकों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि अधिकांश अल-नीनो वर्षों में भारत को औसत से कम बारिश मिली है।

पिछले माह सामान्य से कम रही बारिश

जून 2026 के पहले दो हफ्तों में कई राज्यों में बारिश सामान्य से काफी कम रही। महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्यों में 70-80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि मध्य भारत और कुछ उत्तरी हिस्सों में भी बारिश का स्तर नीचे रहा। आईएमडी के अनुसार, जून महीने में भी औसत से कम बारिश रहने की संभावना है। मॉनसून की इस देरी और कमजोर शुरुआत ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अल-नीनो का असली और गहरा असर जुलाई से सितंबर के बीच दिखेगा, जब मॉनसून अपनी चरम अवस्था में होता है। यदि अल-नीनो मजबूत होता है, तो अगस्त-सितंबर में बारिश में और भी कमी आ सकती है। इससे देश के जलाशयों में पानी की कमी, नदियों के सूखने और भूजल स्तर में गिरावट जैसी गंभीर समस्याएं और विकराल रूप ले सकती हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, जहाँ लगभग 50-60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। खरीफ सीजन (जून-सितंबर) में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालें जैसी महत्वपूर्ण फसलें बोई जाती हैं। कम बारिश से इन फसलों की पैदावार में भारी कमी आ सकती है। पिछले अल-नीनो वर्षों में सूखे के कारण किसानों की आय घटी, उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा और कई जगहों पर आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ीं। 2026 में यदि बारिश 90 प्रतिशत या उससे कम रहती है, तो खाद्यान्न उत्पादन में 10-15 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे देश के सामने खाद्य सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को अनाज का आयात बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में वर्षा आधारित खेती अधिक होती है। छोटे किसान, जिनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वे इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पशुपालन भी प्रभावित होगा, क्योंकि चारे की कमी हो सकती है। कम बारिश का सीधा मतलब है जल संकट का गहराना। देश के कई शहरों और गांवों में पहले से ही पानी की समस्या है, और मॉनसून कमजोर रहने पर पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की कमी और बढ़ेगी। बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट पानी पर निर्भर करते हैं। अल-नीनो से तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है।

टीबी मुक्त भारत अभियान को मिलेगी नई गति

झारखंड ने केंद्र से मांगी टू-नेट व सीबी नाट मशीनें

बिभा संवाददाता

रांची : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रगति पोर्टल के माध्यम से ₹टीबी मुक्त भारत₹ एवं ₹मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य₹ कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियों एवं चुनौतियों की समीक्षा की गई तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य में टीबी जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पर टू-नेट एवं सीबी नाट मशीनें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक जांच मशीनों की संख्या बढ़ने से टीबी रोगियों की शीघ्र एवं सटीक पहचान संभव होगी, जिससे समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा और टीबी उन्मूलन अभियान को नई गति मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। निश्चय पोर्टल के माध्यम से टीबी रोगियों की पहचान, पंजीकरण, उपचार और नियमित निगरानी की जा रही है। साथ ही टीबी ऐप के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर जांच और उपचार का लाभ उठा सकें।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा टीबी उन्मूलन के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर हासिल करना है।

समीक्षा बैठक के दौरान टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों की पहचान, जांच, उपचार, दवा उपलब्धता, संपर्क अनुरेखण तथा सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर सेवाएं, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशुओं की देखभाल, नियमित टीकाकरण, पोषण कार्यक्रम तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने, टीबी मुक्त भारत अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से ही देश को टीबी मुक्त बनाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की। साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने, तकनीक के बेहतर उपयोग तथा लाभार्थियों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आवश्यक सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित समीक्षा आवश्यक है।

रांची में आज बिजली कटौती, कई इलाकों में दोपहर तक बंद रहेगी सप्लाई

रॉंची। राजधानी रॉंची में शनिवार 20 जून को बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस कार्य कराया जाएगा। इसके चलते कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओल्ड टाटीसिलवे, गोंदलीपोखर, प्लांडू, कोचाटोली, विकास, कुचू, चाईबगान और रामपुर (सिल्ली) फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। वहीं हिन्दपीढ़ी क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक एलटी लाइन से संबंधित काम किया जाएगा। इस दौरान ग्वालाटोली, कुर्बान चौक, बड़ी मस्जिद, एलएफ रोड, जीटी रोड, गुरुनानक स्कूल, नाला रोड और लोअर पीपी कंपाउंड समेत आसपास के इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरी काम पहले ही निपटा लें। काम पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

उधवा : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन

बिभा संवाददाता

उधवा। उधवा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय मोहर्रम लॉज में शुक्रवार को कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मो. बदरूद्दोजा के अध्यक्षता में कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 56 वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही संविधान रक्षा का संकल्प लिया गया। तत्पश्चात साहिबगंज युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तनवीर राजा के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उधवा में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस दौरान तनवीर राजा ने कहा कि राहुल गांधी भारत के गरीब,हाशिए पर पड़े और पिछड़े नागरिकों के निर्विवाद नेता है। बेजुबानों की आवाज, कमजोरों के लिए ताकत का स्तंभ, हमारे संविधान के संरक्षक, सर्वोत्कृष्ट न्याय योद्धा और भारत के गौरवशाली भविष्य की सबसे उज्ज्वल उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संविधान में बताए गए मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता है। सबसे खराब गालियों का सामना किया है,हर तरफ से हमलों का सामना किया,लेकिन वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और कभी भी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। विपक्ष चाहे उन्हें कितना भी उपहास या अपमान क्यों न सहना पड़े। आज हमारे देश में उनके रूप में एक विवेकशील रक्षक और एक ऐसा नेता है। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण कुमार,जिला महासचिव सह प्रखंड प्रभारी ऐनुल हक अंसारी,जिला सचिव सईद अख्तर, रब्बानी सेख, जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर आरिफ आलम सहित अन्य मौजूद थे।

महीनों बाद मिली खोई खुशी : तालझारी पुलिस ने बरामद कर लौटाए चोरी के मोबाइल

बिभा संवाददाता

तालझारी । पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच के दम पर दो लोगों की खोई हुई उम्मीद शुक्रवार को फिर लौट आई। तालझारी थाना पुलिस ने चोरी हुए दो मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए, जिसके बाद दोनों लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं थाना प्रभारी नितेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि टेक्निकल सेल की सहायता से थाना क्षेत्र से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। जांच के बाद मोबाइल के वास्तविक मालिकों की पहचान की गई और उनसे संपर्क कर थाना बुलाया गया। कहा बरामद मोबाइल में एक फोन गढ़वा निवासी रवि केसरी का था। जो दीपावली के दौरान चोरी हो गया था। वहीं दूसरा मोबाइल कहलगांव निवासी अरसद खान का था। जो कहलगांव रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ था। शुक्रवार दोपहर दोनों को तालझारी थाना बुलाकर उनके मोबाइल विधिवत वापस सौंप दिए गए। वहीं मोबाइल मिलने के बाद दोनों ने तालझारी पुलिस और थाना प्रभारी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस की मेहनत से उनका भरोसा और मजबूत हुआ है।

थाना प्रभारी ने कहा कि आधुनिक तकनीक और पुलिस की सतत निगरानी के कारण चोरी हुए मोबाइलों को ट्रैक कर बरामद करने में सफलता मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल चोरी या गुम होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि तकनीक और पुलिस की तत्परता मिलकर लोगों की खोई संपत्ति को वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही।

संक्षिप्त खबरें

जैप -9 में स्वास्थ्य शिविर : जवानों की हुई जांच, बांटी गयी जीवन रक्षक दवाएं

साहेबगंज(बिभा)। जवानों के बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को जैप-9 परिसर में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व शहरी क्षेत्र के चिकित्सक पदाधिकारी डॉ. अमित कुमार ने किया। जहां जवानों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच की गई तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का वितरण किया गया। वहीं शिविर के दौरान जवानों की ब्लड प्रेशर, शुगर एवं मलेरिया जांच की गई। चिकित्सकों ने जवानों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श भी दिए और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी। कार्यक्रम के समापन पर जैप-9 के डीएसपी अजय केरकेट्टा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर जवानों के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भविष्य में भी प्रत्येक माह दो बार स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का आग्रह किया। वहीं शिविर को सफल बनाने में फार्मासिस्ट मोनू मैथ्यू मुर्मू,लैब टेक्नीशियन अमित यादव, एएनएम भवानी कुमारी साहा, खुशबू कुमारी तथा एमटीएस दिनेश मरांडी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही।

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने देश की पहली आयुष्मान लाभार्थी मंजू देवी को किया सम्मानित

रांची(बिभा): केंद्र की मोदी सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के बिरसा चौक (हटिया) निवासी श्रीमती मंजू देवी जी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती ममता देवी और निवर्तमान पार्षद श्री कृष्णा महतो भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

मांडर(बिभा) : मांडर पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के मामले में आरोपी मंसूर अंसारी (37) को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी फुसराटांड़ गांव का निवासी तथा इब्राहिम अंसारी का पुत्र बताया गया है। पीड़िता की ओर से बुधवार को मांडर थाना में आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पर आरोप है कि उसने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

जीवन बीमा देता है दीर्घकालिक मूल्य, इसके लाभ सामयिक चिंताओं की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं

जमशेदपुर : जीवन बीमा उद्योग जीवन बीमा की अधिक संतुलित समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहा है। उद्योग का जोर इस बात पर है कि इसके वित्तीय सुरक्षा, संरक्षा और अनुशासित बचत जैसे दीर्घकालिक लाभ उन छिटपुट चिंताओं की तुलना में कहीं अधिक बड़े हैं जो कभी-कभी सामने आती हैं, जिनमें मिस-सेलिंग यानी गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के मामले भी शामिल हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस कमेटी - लाइफ इंश्योरेंस ग्राहकों और हितधारकों को प्रोत्साहित करती है कि वे जीवन बीमा को तत्काल या अल्पकालिक परिणामों के चश्मे से देखने के बजाय एक दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा उपकरण के रूप में देखें। इंश्योरेंस अवेयरनेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेश राव ने कहा, जीवन बीमा को समय के साथ मूल्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है–वित्तीय सुरक्षा, परिवारों के लिए संरक्षण और अनुशासित बचत के माध्यम से। हालांकि मिस-सेलिंग जैसी चिंताएं मौजूद हैं और उद्योग द्वारा इनका समाधान किया जाना आवश्यक है, लेकिन वे पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं, जो लाखों पॉलिसीधारकों को महत्वपूर्ण मूल्य देना जारी रखे हुए है। महत्वपूर्ण रूप से, जीवन बीमा एकमात्र ऐसा वित्तीय उपकरण है जो 'फ्री-लुक पीरियड' की सुविधा देता है। यह सुविधा पॉलिसीधारकों को खरीद के बाद अपनी पॉलिसी की समीक्षा करने और यदि वे महसूस करते हैं कि यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसे वापस करने की अनुमति देती है। यह विशेषता खरीद के समय पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है।

कार्रवाई : आरपीएफ पुलिस ने किया दो शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार, 4 मोबाइल बरामद

बिभा संवाददाता

बरहरवा। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बीते गुरुवार की रात्रि को स्टेशन परिसर से दो शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से आरपीएफ पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक सुरेश पासवान और सिपाही सुजीत कुमार सिंह की टीम देर रात करीब 02:15 बजे स्टेशन पर सघन गश्ती कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म संख्या- 03 पर खड़ी विश्वभारती पैसेंजर ट्रेन की जांच के क्रम में कोच के अंदर दो युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते पाए गए। आरपीएफ टीम को देखते ही दोनों युवकों ने कोच से कूदकर भागने की कोशिश की,लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान चांद शेख (25 वर्ष) और इस्तेफाक शेख (30 वर्ष) के रूप में हुई है। जो मूल रूप से झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले है। तलाशी के दौरान इनके पास से चोरी के 04 कीमती मोबाइल फोन मिले,जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 53,488 रूपया आंकी गई है। कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि इनमें से दो मोबाइल उन्होंने बरहरवा स्टेशन के द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय (वेटिंग हॉल) में सो रहे यात्रियों की जेब से उड़ाए थे। जबकि बाकी के दो मोबाइल टिकट काउंटर के पास सो रहे लोगों से चुराए थे। आरपीएफ ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में बरामद सभी मोबाइलों को विधिवत जब्त कर लिया है। आवश्यक कागजी और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद,दोनों आरोपियों को जब्त सामान के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) बरहरवा को सौंप दिया गया है। आरपीएफ कमांडेंट ने टीम की इस कामयाबी की सराहना की है। इसके साथ ही आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और असामाजिक तत्वों तथा आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष गश्ती अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

मसकलैया विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान, छात्रों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प

बिभा संवाददाता

तालझारी। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश देने के उद्देश्य से शुक्रवार को दूसरे दिन भी तालझारी थाना प्रभारी नितेश कुमार पांडेय ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय मसकलैया में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी नितेश कुमार पाण्डेय ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इसके खिलाफ जनजागरण का संदेश दिया। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि नशा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता को कमजोर कर देता है। इसके कारण न केवल व्यक्ति का भविष्य प्रभावित होता है,बल्कि परिवार और समाज भी इसकी मार झेलता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों व परिजनों को भी इसके प्रति जागरूक करें। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि शिक्षा, खेलकूद और सकारात्मक सोच ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिक्षकों ने भी छात्रों को अनुशासित जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अभियान के अंत में सभी विद्यार्थियों ने नशा नहीं करने तथा अपने आसपास के लोगों को भी नशे के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। मौके पर विद्यालय के प्रधान शिक्षक सुमित कुमार,बमबम कुमार सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाव को लेकर थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को किया जागरूक

बिभा संवाददाता

बरहरवा । कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार ने शुक्रवार को संत जेवियर्स स्कूल में कोटालपोखर में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर स्टीफन राज की उपस्थिति में विद्यार्थियों को ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाव को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे की बढ़ती समस्या के प्रति सचेत करना तथा उन्हें स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को बताया कि नशीले पदार्थों का सेवन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है,बल्कि मानसिक,सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ड्रग्स,उनके दुष्प्रभावों तथा उनसे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों को ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूर रहने की सलाह दी जो उन्हें नशे की ओर आकर्षित कर सकते है। साथ ही विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर स्टीफन राज ने इस कार्यक्रम को काफी फायदेमंद और जागरूक बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को अपने आसपास नशे से संबंधित कोई गतिविधि दिखाई दे तो वह तुरंत अपने अभिभावकों या शिक्षकों को इसकी सूचना दें। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर डॉक्टर स्टीफन राज ने थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

किसान क्रेडिट कार्ड व खेत बचाओ अभियान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बिभा संवाददाता

राजमहल। किसानों को सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराने तथा उनकी फसलों को विभिन्न प्रकार की क्षति से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजमहल प्रखंड सभागार में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एवं खेत बचाओ अभियान विषय पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ सह सीओ मोहम्मद युसूफ ने किया। कार्यक्रम में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक,साहिबगंज,प्रखंड कृषि पदाधिकारी,प्रखंड तकनीकी प्रबंधक,प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक,झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के प्रतिनिधि तथा कृषि समन्वयक निकेश कुमार सहित कृषि एवं बैंकिंग विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहें। कार्यक्रम के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले कम ब्याज दर वाले ऋण, आवेदन प्रक्रिया,पात्रता मानदंड तथा योजना से मिलने वाले विभिन्न लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि केसीसी योजना किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर कृषि कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जागरूकता कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत फसलों को कीट एवं रोगों से बचाने,आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने,समय पर कृषि प्रबंधन करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और उन्नत तकनीकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं वित्तीय योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं,आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाएं तथा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि जागरूकता और तकनीकी जानकारी के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते है और खेती को अधिक लाभकारी बना सकते है कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने कृषि ऋण,फसल सुरक्षा, सरकारी योजनाओं तथा खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं अधिकारियों के समक्ष रखी। विशेषज्ञों ने किसानों के सवालों का समाधान करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।राजमहल प्रखंड में आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने,आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। इससे किसानों को कृषि ऋण,फसल प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की बेहतर जानकारी प्राप्त हुई। जो भविष्य में कृषि उत्पादन और आय वृद्धि में सहायक होगी।

रांची नगर निगम ने 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक किया जब्त, प्रतिष्ठान पर लगा जुर्माना

बिभा संवाददाता

रांची : स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल रांची के निर्माण की दिशा में रांची नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्रवाई करते हुए 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। यह कार्रवाई न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी नई गति प्रदान करती है।

रांची नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर सहायक नगर आयुक्त श्री राहुल यादव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने दिनांक 18 जून 2026 को (प्रातः 6 बजे) अपर बाजार स्थित शनि मंदिर, कार्ट सराय रोड में मेसर्स डिस्पो वर्ल्ड के परिसर में औचक निरीक्षण एवं छापामारी की।

छापामारी के दौरान प्रतिष्ठान से कुल 17 कार्टन में लगभग 480 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री बरामद की गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। जब्त सामग्री के नमूनों को जांच हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को भेजा गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2026) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो पर्यावरणीय मानकों और विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए संबंधित प्रतिष्ठान पर नियमानुसार 52,000 रुपए का जुमार्ना अधिरोपित किया गया है तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है।

भारत/अफगानिस्तान : अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में राहुल, जायसवाल और राणा पर रहेगी नजर

चेन्नई (एजेंसी)। पहले दो मैच में धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

जायसवाल ने 2025 के बाद वनडे टीम में वापसी की है लेकिन वह लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल चार रन ही बना पाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इससे पहले जो आखिरी वनडे खेला था उसने उन्होंने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद स्थिति काफी बदल गई है और अब ईशान किशन की वापसी ने शीर्ष क्रम में एक और दावेदार को जोड़ दिया है। किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

कप्तान शुभमन गिल ने जायसवाल को जगह देने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और शतक जड़ा। लेकिन जब विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के बाद वापसी करेंगे तो उनका तीसरे नंबर पर खेलना पक्का है। इससे गिल के पास रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। किशन और श्रेयस अय्यर क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जायसवाल को सीमित अवसरों का पूरा फायदा उठाना होगा।

जायसवाल के लिए इस मैच में बड़ा स्कोर बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति एक और असफलता को शायद ही बर्दाश्त करेगी। अगर चयनकर्ता सूर्यकुमार यादव को टी20 विश्व कप में टीम को जीत दिलाने के बावजूद टीम से बाहर कर सकते हैं तो अन्य खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा जा सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जायसवाल की वनडे में किस्मत उनके हाथ में ही है।

राहुल का मामला बिल्कुल अलग है। लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम में अय्यर की वापसी का मतलब है कि 34 वर्षीय राहुल को अब अधिकतर मौकों पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी होगी। राहुल लंबे समय तक पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इस पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने पांचवें नंबर पर खेलते हुए 38 मैचों में 63.2 के औसत से 1517 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। इसके विपरीत छठे नंबर पर उन्होंने 15 मैचों में 41.5 की औसत से 332 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है।

BCCI ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इस मैच के लिए हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकता है, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति में निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का विकल्प भी मिलेगा।

इससे टीम प्रबंधन को ब्रिटेन के दौरे से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करने का मौका मिलेगा। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो उसने इस

श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले दो वनडे में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उसकी टीम हालांकि जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके लिए उसे खेल के तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टीम इस प्रकार हैं

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा।

अफगानिस्तान : हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।

ब्रॉड ने अपनी सर्वकालिक टेस्ट एकादश में भारत से केवल विराट को शामिल किया

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने समय के खिलाड़ियों की सर्वकालिक टेस्ट एकादश का चयन किया है। इस टीम में उन्होंने कई बड़े दिग्गजों को शामिल किया है पर इसमें भारत से केवल विराट कोहली को ही शामिल किया गया है। ब्रॉड की इस टीम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के चार-चार खिलाड़ी शामिल हैं, वहीं दो श्रीलंकाई खिलाड़ी भी इस सूची का हिस्सा हैं।

ब्रॉड ने अपनी टीम में श्रीलंका के कुमार संगकारा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को भी शामिल किया है। संगकारा को ब्रॉड ने उन्हें अपनी टीम में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को नंबर तीन पर और विराट कोहली को नंबर चार पर रखा गया है। कोहली का चयन इस एकादश में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय के रूप में अहम है, जो उनकी विश्वस्तरीय बल्लेबाजी दिखाता है।

इस एकादश में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं मिली है जबकि ब्राड ने अपने खेल के अंतिम दिनों में उनके खिलाफ गेंदबाजी भी की थी। वहीं मध्य क्रम में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ को नंबर पांच पर चुना गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज जैक्स कैलिस को नंबर छह पर शामिल किया गया है। कैलिस इस टीम के एकमात्र ऑलराउंडर हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को नंबर सात पर रखा गया है। डिविलियर्स अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देते हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त विकेटकीपिंग कवर भी प्रदान करते हैं।

दूसरी ओर गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को इसकी कमान सौंपी गयी है। उनका साथ दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन देंगे। स्टेन जो अपनी पीढ़ी के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी टीम में जगह मिली है। श्रीलंका के स्पिन जादूगर मुथैया मुरलीधरन को टीम का अकेला विशेषज्ञ स्पिनर रखा गया है। मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं।

ब्रॉड की सर्वकालिक टेस्ट एकादश इस प्रकार है:

ग्रीम स्मिथ, कुमार संगकारा (विकेट कीपर), रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जैक्स कैलिस, एबी डिविलियर्स, मिशेल जॉनसन, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, मिशेल स्टार्क।

महिला टी20 विश्व कप 2026 : वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड को सात रनों से हराया

लंदन (एजेंसी)। वेस्टइंडीज ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के 12वें मुकाबले में स्कॉटलैंड को सात रनों से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में विजेता का फैसला 19वें ओवर में हुआ। स्कॉटलैंड टीम इस मैच में एक समय जीत के करीब थी पर अंत में इंडीज टीम ने बाजी पलट दी। वेस्टइंडीज की टीम इस जीत के साथ ही आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं स्कॉटलैंड तीसरे स्थान पर फिसल गयी है।

इस मैच में स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 153 रन बनाये। उसकी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। एक समय आधी टीम 85 रनों पर ही सिमट गयी थी पर इसके बाद नंबर-7 पर उतरीं स्टेफनी टेलर ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए केवल 19 गेंदों में ही 4 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से 47 रन बना दिये। इससे टीम 153 रनों तक पहुंच पाई। इसके बाद जीत के लिए मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की शुरुआत काफी अच्छी रही। पहले विकेट के लिए उन्होंने 51 रन बनाये पर इसके बाद जब विकेट गिरने शुरु हुए तो टीम ने 58 रनों पर ही 4 विकेट खो दिये। 74 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सलामी बल्लेबाज डार्सी कार्टर एक छोर पर डटी रहीं और उन्होंने 8 चौकों की सहायता से 59 रनों की अहम पारी खेली, जिससे स्कॉटलैंड की उम्मीदें बंधी रहीं और वह मैच में बनी हुई थी। अब आखिरी ओवर में स्कॉटलैंड को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और उनके पास 2 विकेट बचे थे। वेस्टइंडीज की कियाना जोसेफ ने 20वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 9 रन दिये और 2 विकेट लिए। इस प्रकार वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड की पारी को अंतिम गेंद पर 146 रन पर समेट दिया और यह रोमांचक मुकाबला 7 रनों से जीत लिया।

आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारत की नजरें चिली को हराकर फाइनल में जगह बनाने पर

आकलैंड (एजेंसी)। टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम निचली रैंकिंग वाली चिली के खिलाफ स्नढ्ढा नेशंस कप सेमीफाइनल में उसी लय को कायम रखना चाहेगी ताकि स्नढ्ढा प्रो लीग में वापसी की ओर अगला कदम रख सके। भारत ने पूल ए में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

मेजबान न्यूजीलैंड पूल बी में सारे मैच जीतकर शीर्ष पर रहा और दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका से खेलेगा। भारतीय टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में वापसी के लिये नेशंस कप जीतना ही होगा जिससे वह पिछले साल बाहर हो गई थी। पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ दस अंक लेने के बाद भारत प्रो लीग में सबसे नीचे रहा और नेशंस कप में खिसक गया था। आठ देशों के एफआईएच नेशंस कप के विजेता को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलेगी।

मौजूदा रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा चिली पर भारी है। विश्व रैंकिंग में भारत नौवें और चिली 13वें स्थान पर है लेकिन आधुनिक हॉकी में रैंकिंग उतना मायने नहीं रखती। सेमीफाइनल से पहले मुख्य कोच शोर्ड मारिन को कुछ पहलुओं पर काम करना होगा। 17वीं रैंकिंग वाली उरूग्वे को हराने के लिये भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उरूग्वे ने बढत बना ली थी लेकिन दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल किए और दीपिका सोरेंग ने फील्ड गोल

करके भारत को जीत दिलाई।

ड्रैग फ्लिकर दीपिका शानदार फॉर्म में है और चार गोल कर चुकी है। नवनीत कौर, कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम्सियामी भी एक एक गोल कर चुके हैं । भारत के लिये एकमात्र फील्ड गोल दीपिका सोरेंग ने किया है। भारत को अगले मैचों में और फील्ड गोल करने होंगे । इसके लिये फॉरवर्ड पंक्ति को मौके बनाकर फिनिशिंग तक ले जाना होगा।

टी20 में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने डु प्लेसी

टेक्सास । टेक्सास सुपर किंग्स टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने शुरु हुई में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2026 के पहले ही मैच में शानदार शतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 साल के डु प्लेसी अब टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक उम्र में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं। डु प्लेसी ने ये शतक सिएटल ऑर्कास के खिलाफ लगाया था। इस मैच में डु प्लेसी की टीम 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। डु प्लेसी ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 113 रन बनाये। इससे उनकी टीम नौ गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज करने में सफल रही। इस शानदार पारी के साथ ही वह टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गये हैं। डु प्लेसी की उम्र अभी 41 साल और 340 दिन है।

वेस्टइंडीज से हार के बाद रोने लगी स्कॉटलैंड की डिरसी कार्टर

लंदन । स्कॉटलैंड को यहां हुए आईसीसी महिला टी20 विश्वकप के एक रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इसमें 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम अंतिम दो ओवरों में खराब प्रदर्शन के कारण हार गयी। जीत के करीब पहुंचकर मिली हार से स्कॉटलैंड की टीम की एक खिलाड़ी डिरसी कार्टर डगआउट में ही रोने लगी। कार्टर रोने वाला वीडियो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कार्टर ने इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 रनों की पारी खेली थी पर वह 19वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुईं थी। अगर वह खेलती तो टीम शायद जीत जाती। 19वें ओवर की पहली गेंद पर डार्सी कार्टर आउट हुईं तो स्कॉटलैंड की उम्मीदें टूट गयीं।

कनाडा और मेक्सिको फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचे

वैंकूवर/ एस्टाडियो ग्वाडालाजारा (एजेंसी)। फीफा विश्व कप 2026 के आज खेले गये मुकाबलों में सह-मेजबान मैक्सिको और कनाडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल कर टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। जोनाथन डेविड की हैट्रिक की बदौलत कनाडा ने फीफा विश्वकप 2026 के ग्रुप चरण में कतर पर 6-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया।

मैच का शुरुआती गोल 16वें मिनट में रिबाउंड पर साइल लारिन ने किया और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। यह टूर्नामेंट में उनका दूसरा गोल था। कतर के गोलकीपर महमूद अबुनादा ने डेविड के वॉली शॉट को पंच करके रोक दिया, लेकिन गेंद लारिन के पास गिरी, जिसे उन्होंने गोल में डाल दिया। इसके बाद डेविड ने 29वें मिनट में दाएं पैर से शानदार वॉली मारकर

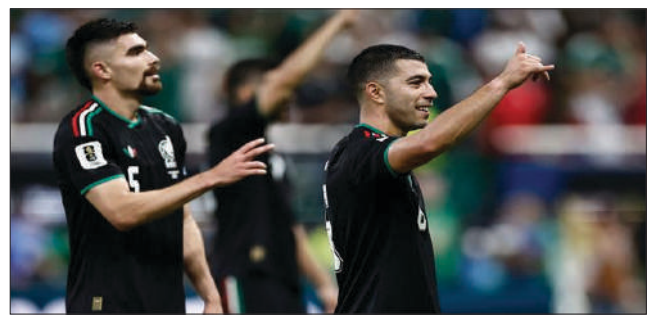

बढ़त को दोगुना कर दिया।

पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में कनाडा ने 3-0 की बढ़त बना ली, जब डेविड ने 48वें मिनट में क्रॉसबार से टकराकर आई गेंद पर गोल दाग दिया। चोटिल कोने के स्थान पर आए नाथन सलीबा ने 64वें मिनट में फ्री किक पर गोल करके स्कोर 4-0 कर दिया। 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए शॉट को आत्मघाती गोल में बदल दिया। डेविड ने स्टॉपेज टाइम में हैट्रिक पूरी की और इस विश्व कप में एक मैच में तीन गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के साथ शामिल हो गए।

इस जीत के साथ कनाडा के अंक बढ़कर चार हो गए हैं और वह गोल अंतर के आधार पर स्विट्जरलैंड से आगे है । इस जीत के साथ ही कनाडा का नॉकआउट चरण में स्थान सुनिश्चित कर लिया है। बुधवार को वैंकूवर में स्विट्जरलैंड के खिलाफ होने वाले अपने अंतिम ग्रुप मैच में कनाडा की टीम का दबदबा रहेगा। एक अन्य मैच में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के राउंड-ऑफ-32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज यहां खेले गये ग्रुप ए के मुकाबले के शुरुआती चरणों में मेक्सिको का दबदबा रहा, लेकिन बाद में दक्षिण कोरिया ने गेंद को नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और हाफ टाइम की सीटी बजने तक उसका दबदबा रहा। लेकिन कोरियाई गोलकीपर किम सेउंग-गिम की एक बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए मेक्सिको के लुइस रोमो ने मैच के दोबारा शुरू होने के तुरंत बाद एकमात्र गोल दाग दिया। इसी जीत के साथ मेक्सिको अपने में दो मैचों में छह अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गया है।

एफआईएच प्रो लीग में जर्मनी के हाथों अंतिम क्षणों में 2-1 से हारी भारतीय हॉकी टीम

रॉटरडैम । भारतीय पुरुष हॉकी टीम को यहां हुए एफआईएच प्रो लीग 2025-26 के एक रोमांचक मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम मैच में अधिकांश समय हावी रही पर अंतिम क्षणों में जर्मनी को एक गोल दागने के करण जीत मिल गयी। भारतीय टीम को मैच के 38वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल कर 1-0 की बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही हमले शुरु कर दिये थे। जिससे जर्मनी दबाव में आ गयी। वहीं भारतीय रक्षापंक्त ने जर्मन के जवाबी हमलों को नाकाम कर दिया। दूसरे क्वार्टर में, भारतीय टीम ने अपनी तेजी और बढ़ा दी हालांकि वह अवसरों को गोल में नहीं बदल पायी। तीसरे क्वार्टर के अंत तक, भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बनाए रखी। जर्मनी को इस दौरान कुछ पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय गोलकीपर ने उन्हें विफल कर दिया। इससे मैच में भारतीय टीम की 1-0 की बढ़त बरकरार रही। वहीं चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारतीय टीम ने कई हमले किये जिससे उसे बढ़त को दोगुना करने के अवसर मिले। पर टीम इसका लाभ नहीं उठा पायी। वहीं जस्टस वीगैंड ने जर्मनी की ओर से पहला गोल कर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। खेल के अंतिम पलों में मैच ड्रॉ होता दिख रहा था तभी जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसका जिसे गोल में बदलन में जैकब ब्रिला ने कोई गलती नहीं की। इस प्रकार 60वें मिनट में किये इस निर्णायक गोल से जर्मनी की 2-1 से जीत तय हो गयी। अब भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में रविवार को मेजबान नीदरलैंड्स का सामना करेगी।

फीफा विश्वकप: रोनाल्डो का साथ नहीं दे रहा फुटबॉल

स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए सबसे बुरा एहसास यह नहीं था कि उन्होंने उस टीम के खिलाफ गोल नहीं किया जिसने उनके जन्म से पहले आखिरी बार वर्ल्ड कप खेला था; या यह कि उनके दो प्रयास कमजोर और दिशाहीन थे; या यह कि वे टीम पर बोझ लग रहे थे। असल में फुटबॉल का उनसे प्यार खत्म होता नजर आ रहा है, गेंद उनसे दूर भाग रही है, नजरों से बच रही है और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वापस लौट जाती थी।

बुधवार को ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मैच ष्ठक्र कांगो के साथ 1-1 से ड्रॉ रहा जिसका नतीजा रोनाल्डो के खराब प्रदर्शन जैसा ही फीका था। 41 साल की उम्र में जब टीम में कई बेहतरीन अटैकिंग खिलाड़ी हों, तो हर खराब प्रदर्शन पर सवाल उठते हैं। हर खराब दिन के साथ, ऐसा लगता है कि वे अपने करियर के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। उम्र और कम होती फुर्ती के बावजूद रोनाल्डो में अभी भी गेंद को सही जगह हिट करने और उसे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाने की काबिलियत है। लेकिन कांगो के खिलाफ, वे ऐसा नहीं कर पाए।

68वें मिनट में फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ने रोनाल्डो की तरफ एक 'कट-बैक' पास दिया, जो उनसे थोड़ा पीछे था। हो सकता है कि यह उनकी पसंद की जगह से एक गज दूर रहा हो, लेकिन अपने बेहतरीन दिनों में वे अपने शरीर को सही ढंग से मोड़कर सबसे अच्छी पोजीशन बना लेते थे। अगर ऐसा नहीं भी होता, तो भी वे हमेशा अपने शानदार बूट से गेंद को सही जगह मार देते थे। यहां, उन्होंने शॉट मारा जो 'नियर पोस्ट' से काफी दूर चला गया। उन्होंने गुस्से में मुंह बनाया, यह सोचते हुए कि उनका 'टच' (गेंद पर नियंत्रण) कैसे उनका साथ छोड़ गया।

सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि उनका प्रयास खराब था, बल्कि यह थी कि उन्होंने ब्रूनो फर्नांडीस के पैरों के पास से गेंद छीन ली थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मिडफील्डर उनके बगल में था, जिसके पास ज्यादा जगह और बेहतर एंगल था। लेकिन रोनाल्डो की फितरत गोल करने में मदद करने की नहीं, बल्कि खुद गोल करने की है। जब 'टच' साथ छोड़ देता है, तो सहज समझ (instincts) भी धोखा दे जाती है। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने फर्नांडीस की जगह में दखल दिया हो।

कोचिंग स्टाफ को इस लगातार हो रही गड़बड़ी का समाधान ढूंढना होगा। छह मिनट बाद उनके खेल में आती गिरावट का एक और पक्का सबूत मिला। कॉन्सेकाओ ने एक और बेहतर कट-बैक दिया, लेकिन रोनाल्डो ने उसे गलत तरीके से मारा और गेंद दूर चली गई। शॉट जल्दबाजी में और बिना ताकत के था, शायद एक्सल तुआनजेबे के चैलेंज की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ये ऐसे पल थे जिन्होंने उन्हें शायद ही कभी परेशान किया हो। वे पैरों के बीच से भी गोल कर सकते थे, शर्ट खींचने वालों और चालाकी से गेंद छीनने वालों से बेपरवाह होकर, उन्हें ताकत और चतुराई से पछाड़ देते थे। यहां, वे परेशान थे, शक से घिरे हुए थे।

विरोधाभास

एक अजीब विरोधाभास है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका करियर अटूट आत्मविश्वास पर बना था, अब खुद पर ही शक करने लगा है। शायद यही उनकी परेशानी की जड़ है - खुद पर इतना पक्का भरोसा कि वे अपनी कमजोर होती काबिलियत की सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं। रोनाल्डो अब वो नहीं रहे जो वे खुद को समझते हैं।

वे अभी भी अद्भुत रूप से फिट हैं, और उनमें वर्ल्ड चैंपियन बनने का जबरदस्त जुनून है - एक ऐसा खिताब जो उन्होंने कभी नहीं जीता। लेकिन वे उस महान खिलाड़ी का मजाक बना रहे हैं जो वे कभी हुआ करते थे। वे एक हेवी मेटल बैंड के बूढ़े लीड सिंगर की तरह हैं जो अपने अतीत की भारी-भरकम शान में जी रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनकी आवाज अब लड़खड़ा रही है।

जब वे गोल नहीं कर पाते, तो वे टीम के लिए बोझ बन जाते हैं - वे न तो क्रिएटिव काम में शामिल होते हैं और न ही डिफेंस में, उनका प्रभाव का दायरा सीमित हो जाता है। कुछ आंकड़े उनके खराब खेल को दिखाते हैं। उन्होंने 90 मिनट में सिर्फ 20 पास दिए, जो खेल में तेरहवें नंबर पर थे। डिफेंस में उनका योगदान सिर्फ एक था। आगे बढ़ने वाले एक्शन सिर्फ दो थे। वे कभी-कभी लिंक-अप प्ले के लिए पीछे आते थे लेकिन अपने साथियों की रफ़्तार का मुकाबला नहीं कर पाते थे। उनकी सुस्ती पूरी टीम की रफ़्तार धीमी कर रही है, जिसमें बेहतरीन अटैकर और मिडफील्ड कंडक्टर शामिल हैं।

इसके अलावा, वे कांगो की हाई लाइन के आगे घात लगाकर बैठे रहते थे, फिर अंदर आकर गेंद लेने के लिए पीछे हटते थे, और लाइन के पीछे खेले जाने वाले क्रॉस का इंतजार करते थे। उनके

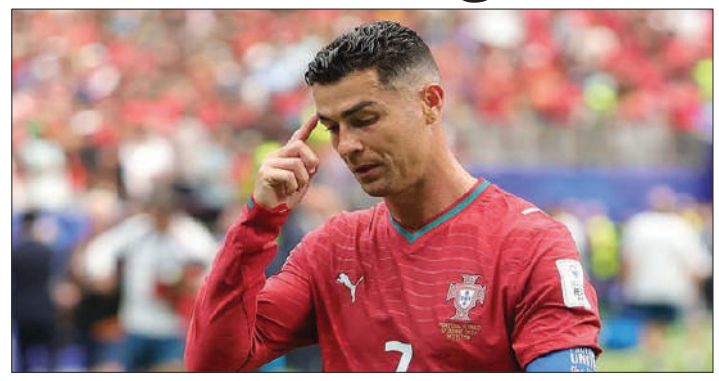

साथियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। वे फेरारी के बीच फंसी एक पुरानी मॉरिस माइनर कार की तरह थे।

मेसी से तुलना

लियोनेल मेसी से तुलना तो होगी ही। मेसी रोनाल्डो से धीमे हैं, लेकिन वे ज़्यादा मौके बनाते हैं; उनकी जगह की समझ (स्पेशल अवेयरनेस) बेहतर है, उनके पास (गेंद दूसरे को देना) डिफेंस को भेदने वाले होते हैं, और जब उनके पैरों में ज़्यादा जान नहीं बचती, तब भी उनकी चाल-ढाल डिफेंडरों को अपनी जगह से हटने पर मजबूर कर देती है। मेसी के आस-पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो उम्र के साथ आई कमियों की भरपाई कर देते हैं। रोनाल्डो के आस-पास बेहतरीन टेक्नीशियन हैं, लेकिन वे उन चीजों की भरपाई नहीं कर सकते जो रोनाल्डो अब नहीं दे पाते। यही पुर्तगाल की बड़ी उलझन है। बेशक, रोनाल्डो अकेले ऐसे पुर्तगाली फुटबॉलर नहीं थे जिनका दिन बहुत खराब रहा, लेकिन टीम की मुश्किलों में उनकी भूमिका अहम थी।

पुर्तगाल के लिए खिताब की मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए रोनाल्डो वाली पहेली को सुलझाना होगा। कड़े फैसले लेने होंगे कि उन्हें सब्स्टीट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या बुधवार को रॉबर्टो मार्टिनेज ने जितनी देर से उन्हें बदला था, उससे पहले ही बदल दिया जाए। मैनेजर ने उनका बचाव किया, जैसा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा करते आए हैं। उन्होंने कहा, 'हम क्रिस्टियानो के साथ उनकी उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके लक्षणों और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं।' हालाँकि, असल स्थिति कुछ और ही कहती है। ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल का उनसे मोहभंग हो गया है। फुटबॉल के ऐसा करने से पहले ही पुर्तगाल को इसका कोई समाधान ढूंढ लेना चाहिए।

डब्ल्यूटीसी में 6,500 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने रुट

लंदन । इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां दूसरे किकेट टेस्ट क्रिकेट में अपनी 46 रनों की पारी के दौरान ही एक बड़ा रिकार्ड अपने नाम कर लिया। रुट अपनी इस पारी के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) इतिहास में 6,500 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले और एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पता चलता है कि टेस्ट में रुट के प्रदर्शन में कितनी निरंतरता है। उनकी करीब कोई भी अन्य बल्लेबाज नहीं है। दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के नाम 4,564 रन हैं। रूट ने अपने 76वें डब्ल्यूटीसी मैच की 139वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि डब्ल्यूटीसी इतिहास में उनके नाम सबसे अधिक 23 शतक दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद स्टीव स्मिथ के नाम 14 शतक हैं। रूट ने इस दौरान 51 से अधिक की शानदार औसत से रन बनाए हैं, जिसमें 22 अर्धशतक और 262 रन का अधिकत स्कोर भी शामिल है। रूट मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकल (चैंपियनशिप चक्र) में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने इस मामले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने महज 8 मैचों में 79.16 की बेमिसाल औसत से 950 रन बनाए हैं। इस चक्र में रूट और गिल दोनों के नाम संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 5-5 शतक दर्ज हैं। रूट की निरंतरता जबरदसत है। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सीजन से ही जमकर रन बना रहे हैं। 2023-25 चक्र में 22 टेस्ट मैचों में 54.66 की औसत से 1,968 रन बनाकर वह शीर्ष स्कोरर रहे थे।

राष्ट्र की सुरक्षा : आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता के 12 वर्ष

बिहान भारत

पिछले 12 वर्षों में, भारत के व्यापक आतंकवाद-विरोधी बदलाव, आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृढ़ दृष्टिकोण को दिखाते हैं। मजबूत कानूनी ढाँचे, संस्थागत सुधार और खुफिया जानकारी के एकीकरण ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच इंटर-एजेंसी समन्वय को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई, आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क का खात्मा और पुलिस एवं सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण ने राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ किया है। साइबर सुरक्षा क्षमताओं के विस्तार ने उभरते डिजिटल खतरों के विरुद्ध तैयारियों को और मजबूत किया है। इन निरंतर प्रयासों ने आंतरिक सुरक्षा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है, जिनमें आतंकी घटनाओं में कमी, नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मृत्यु संख्या में कमी और सार्वजनिक सुरक्षा, विकास परिणामों और राष्ट्रीय लचीलेपन में सुधार शामिल हैं।

ठोस निर्णय और निर्णायक कार्यों का एक दशक

पिछले बारह वर्षों में, भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में सबसे व्यापक बदलावों में से एक को शुरू किया है। सरकार ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़कर एक सक्रिय, समग्र सरकारी दृष्टिकोण विकसित किया। आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। जांच एजेंसियों को सशक्त बनाया गया। सीमा निगरानी को मजबूत किया गया। सुरक्षा संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। राजनयिक पहल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया और आतंकवाद को प्रायोजित करने की वैश्विक कीमत को उजागर किया।

बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों से एक ऐसा परिवर्तन आया है जिसे तीन परस्पर जुड़े परिणामों के माध्यम से समझा जा सकता है। विश्वास इसका उद्देश्य निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से जनता का विश्वास बहाल करना है। विकास इसका उद्देश्य एक मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा संरचना का विकास करना है। जन-कल्याण इसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है जिसमें विकास, गरिमा और सामान्य जीवन फल-फूल सके।

ये परिणाम आकस्मिक नहीं थे। ये कूटनीति की सीमाएँ समाप्त होने पर सैन्य सटीकता के साथ कार्रवाई करने की तत्परता के फलस्वरूप प्राप्त हुए। ये ऐतिहासिक विधायी सुधारों के माध्यम से प्राप्त हुए जिन्होंने जाँच एजेंसियों को अधिक प्रभावी उपकरण और व्यापक पहुँच प्रदान की। ये प्रौद्योगिकी-आधारित खुफिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राप्त हुए जिन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र को वास्तविक समय में आपस में जोड़ा। इस अवधि में भारत का आतंकवाद-विरोधी रिकॉर्ड एक ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जिसने आतंकवाद के प्रबंधन से आगे बढ़कर उसे बनाए रखने वाली परिस्थितियों को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए।

हालांकि, इन सब की शुरूआत बिना किसी पूर्वधारणा के नहीं हुई। मई 2014 में जब सरकार ने सत्ता संभाली, तो उसे दशकों की उपेक्षा, संस्थागत खामियों और कई मोर्चों पर अनसुलझे संघर्षों से ग्रस्त सुरक्षा व्यवस्था विरासत में मिली। विरासत में मिली व्यवस्था को समझना, भविष्य में हासिल की गई व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है। सरकार के सामने चुनौतियाँ सामान्य नहीं थीं। वे व्यवस्थागत, एक साथ घटित होने वाली और गंभीर थीं।

चुनौती परिदृश्य

2014 में भारत एक चौराहे पर खड़ा था। आंतरिक सुरक्षा का माहौल एक साथ कई मोर्चों पर बुरी तरह से खंडित था। पिछले दशक में (2004-2014) के दौरान 7,217 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले चार दशकों में आतंकवाद, विद्रोह और उग्रवाद के कारण लगभग 92,000 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। मौजूदा चुनौतियों के लिए क्रमिक सुधारों की नहीं, बल्कि व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ जम्मू और कश्मीर यह एक लगातार बढ़ती हुई चुनौती रही है। पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी (ISI) लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सहित नामित आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन आतंकी समूहों का इस्तेमाल देश की शांति और स्थिरता को भंग करने के लिए किया जाता है। 2008 के मुंबई हमलों में 166 लोगों की जान गई थी, जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने क्रकके सक्रिय समर्थन से अंजाम दिया था। इस तरह की आतंकी घटनाओं ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की विनाशकारी क्षमता को प्रदर्शित किया, फिर भी एक विश्वसनीय निवारक सिद्धांत के अभाव में जवाबदेही तय करना मुश्किल बना रहा। साथ ही, कश्मीर अलगाववादी सीमा पार से मिलने वाले समर्थन और स्थानीय मोबिलाइजेशन नेटवर्क द्वारा समर्थित इन घटनाओं ने देश में शांति और शासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। 2010 से 2014 तक, औसतन हर साल 2,654 संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं। ऑवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के नेटवर्क, घुसपैठ करने वाले उग्रवादियों को सक्रिय समर्थन प्रदान करते थे। अनुच्छेद 370 के तहत शासित पूर्ववर्ती राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे ने ऐसी संरचनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं, जिनसे प्रभावी शासन और सुरक्षा प्रतिक्रिया जटिल हो गई थी।

आतंकी समूह प्रचार, भर्ती, वित्तपोषण और परिचालन समन्वय के लिए सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे थे।

2014 के बाद इस्लामिक स्टेट (ISIS) के वैश्विक उदय ने भारत की सुरक्षा चिंताओं में एक नया आयाम जोड़ दिया। ऑनलाइन कट्टरपंथ और चरमपंथी प्रचार के बढ़ने से भारतीय नागरिकों के बीच भर्ती का खतरा पैदा हो गया और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर स्व-कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने वाले कम तीव्रता वाले हमलों का खतरा बढ़ गया। इस बदलते खतरे के परिदृश्य के कारण सुरक्षा एजेंसियों को कट्टरपंथ-विरोधी गतिविधियों, साइबर निगरानी और खुफिया समन्वय में नई क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पड़ी।

किसी भी लिहाज से, 2014 में विरासत में मिली सुरक्षा स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। पिछले दशक में हजारों आतंकवादी घटनाएं घटी थीं; जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद का सिलसिला जारी था; उग्रवाद के कारण लोगों की जान जाती रही; और कानूनी ढांचे में व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की क्षमता सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों का अभाव था। इन चुनौतियों की गंभीरता को देखते हुए भारत के सुरक्षा सिद्धांत, संस्थागत क्षमताओं और परिचालन प्रतिक्रिया तंत्र में मौलिक बदलाव की आवश्यकता थी।

भारत की आतंक-विरोधी नीतिः आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का नया युग

सत्ता संभालने के पहले दिन से ही सरकार ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के एक ही, अटल सिद्धांत का पालन किया। उद्देश्य केवल आतंकी हमलों का जवाब देना ही नहीं था, बल्कि आतंकी तंत्र की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त करना था। प्रमुख उपायों में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही, आतंकी वित्तपोषण पर नकेल कसना, निवारक अभियान, घुसपैठ की रोकथाम, आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करना, सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण, CASO अभियानों को तेज करना, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना, रणनीतिक नाकेबंदी और शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए दिन-रात क्षेत्र पर नियंत्रण शामिल हैं।

बारह वर्षों से अधिक समय में, यह रणनीति चार अलग-अलग स्तंभों पर आधारित होकर आकार लेती गई। पहला स्तंभ निर्मित किया गया विधायी सशक्तीकरण, मजबूत आतंकवाद-विरोधी कानूनों, और व्यापक कानूनी सुधारों के माध्यम से। दूसरा स्तंभ मजबूत संस्थाएँ खुफिया नेटवर्क और जांच क्षमताएं। तीसरे स्तंभ ने एक सिद्धांत स्थापित किया जो था सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और बेहतर सीमा प्रबंधन। चौथा स्तंभ एक मजबूत बहुपक्षीय और कूटनीतिक आतंक-विरोधी संरचना जो आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत की स्थिति को मजबूत करे।

ये चारों स्तंभ पूरी तरह से विकसित होकर सामने नहीं आए। इन्हें धीरे-धीरे बनाया गया, परिचालन में परखा गया और अनुभव के माध्यम से परिष्कृत किया गया। 2026 तक, बारह वर्षों के विधायी सुधार, संस्थागत निर्माण, परिचालन सिद्धांत और कूटनीतिक जुड़ाव ने आतंकवाद-विरोधी अभ्यास का एक ऐसा ठोस ढांचा तैयार कर दिया था जिसे संहिताबद्ध किया जा सके। वह संहिताबद्धता जिस रूप में सामने आई उसे कहा गया - प्रहारः भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति। प्रहार नीति पिछले दशक में निर्मित सिद्धांतों का अधिक्रमण नही करती अपितु यह बारह वर्षों के शासन द्वारा स्थापित सिद्धांतों और प्रथाओं को समेकित, व्यवस्थित और औपचारिक सैद्धांतिक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, समग्र सरकारी समन्वय, मानवाधिकार-आधारित प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक एकीकृत राष्ट्रीय सिद्धांत में समाहित करती है। ये पिछले बारह वर्षों में व्यवहार में प्रदर्शित सभी चीजों को औपचारिक रूप से व्यक्त करती है।

आगे चारों स्तंभों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करते हैं। ये सभी मिलकर यह कहानी बयां करते हैं कि कैसे भारत ने प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा नीति से हटकर एक सक्रिय, लचीली और सिद्धांत-आधारित आतंकवाद-विरोधी संरचना की ओर कदम बढ़ाया।

स्तंभ 1: विधायी सशक्तीकरण

आतंकवाद के प्रभावी निवारण के लिए एक मजबूत कानूनी आधार आवश्यक है। 2014 से, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जांच, अभियोजन और निवारण को मजबूत करने के लिए प्रमुख विधायी सुधार किए हैं। इन उपायों ने सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त बनाया है, आतंकवाद विरोधी कानूनों को सख्त किया है, आतंकवाद के वित्तपोषण को बाधित किया है और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाया है।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

UAPA संशोधन ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके भारत के आतंकवाद-विरोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। यह इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण विधायी सुधार है, जिसे संसद ने 2 अगस्त 2019 को पारित किया और 14 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया। इस संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत न केवल संगठनों बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया। संशोधन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने का अधिकार भी दिया। इसने एनआईए के महानिदेशक को आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति की जब्ती या कुर्की को मंजूरी देने में सक्षम बनाया। अधिनियम ने NIA के अधिकार क्षेत्र को मानव तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और भारत के बाहर किए गए ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए विस्तारित किया जो भारतीय हितों को प्रभावित करते हैं।

57 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया. इनमें मसूद अजहर (JeM), हाफि ज सईद (LeT), जकी-उर-रहमान लखवी (LeT), वियतनाम इब्राहिम और गुरपतवंत सिंह पन्नून (सिख फॉर जस्टिस), हरदीप सिंह निज्जर (खालिस्तान टाइगर फोर्स), और वाधवा सिंह बब्बर (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) सहित प्रमुख खालिस्तानी गुरगे शामिल हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम, 2019

NIA संशोधन अधिनियम में संशोधन करके ठक्ष्म के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अब यह एजेंसी भारत के बाहर भारतीय हितों के विरुद्ध किए गए आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने में सक्षम है। इसकी जांच शक्तियों का विस्तार करते हुए इसमें साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थों से जुड़े मानव तस्करी के मामले भी शामिल किए गए हैं। इस संशोधन के तहत NIA के महानिदेशक को एजेंसी द्वारा की जा रही जांच के मामलों में संपत्ति की जब्ती और कुर्की को सीधे मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना

PMLA में लगातार किए गए संशोधनों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आतंकवाद से जुड़ी परिसंपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने के लिए अधिक प्रभावी साधन प्रदान किए हैं; जिनमें जम्मू और कश्मीर में हवाला चैनल, खालिस्तानी नेटवर्क द्वारा क्रिप्टोकरेंसी-आधारित वित्तपोषण और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े गैंगस्टर नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई जबरन वसूली की रकम शामिल है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 - नया युग

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया है और नए आपराधिक कानूनों के तहत कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं।

भारत सरकार (BNS) आतंकवादी कृत्य को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो घातक हिंसा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश, अपहरण या नकली मुद्रा के प्रचलन जैसे साधनों के माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में कानून में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अन्य आतंकवादी अपराधों के लिए, इसमें न्यूनतम पांच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान है।

बीएनएस एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आतंकवादियों की साजिश रचना, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, उन्हें शरण देना (कुछ सीमित छूटों के साथ) और आतंकवादी गतिविधियों से प्राप्त संपत्ति या आय को अपने पास रखना अपराध घोषित करता है। ये प्रावधान आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने, उसकी जांच करने और उस पर मुकदमा चलाने के लिए भारत की कानूनी क्षमता को काफी मजबूत करते हैं।

शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019

शस्त्र संशोधन अधिनियम, 2019 ने अवैध शस्त्र नेटवर्क को निशाना बनाकर आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत किया। इस अधिनियम ने प्रतिबंधित शस्त्रों और गोला-बारूद की अवैध तस्करी, अवैध कब्जे, निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। साथ ही, सुरक्षा बलों से हथियार चोरी करने और संगठित अपराध गिरोहों में संलिप्तता के लिए भी गंभीर दंड निर्धारित किए गए। सीमा पार शस्त्र तस्करी पर रोक लगाकर और डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणालियों के माध्यम से आग्नेयास्त्रों की पता लगाने की क्षमता में सुधार करके, इस अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया जो देशभर में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

इन विधायी उपायों ने भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक कानूनी उपकरण प्रदान किए हैं। इन सुधारों ने संस्थागत क्षमता को मजबूत किया है, इंटर-एजेंसी समन्वय में सुधार किया है और आतंकवाद का निर्णायक रूप से मुकाबला करने की क्षमता को बढ़ाया है।

दूसरा स्तंभः नए भारत के लिए संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

सशक्त संस्थाएँ एक प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की रीढ़ होती हैं। पिछले बारह वर्षों में, भारत ने आतंकवादी खतरों का तेजी से पता लगाने, बेहतर समन्वय स्थापित करने और उनसे निपटने के लिए अपनी जाँच, खुफिया और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के आधुनिकीकरण में निवेश किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी - क्षमता संवर्धन

मुंबई आतंकी हमलों के बाद 2008 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम के तहत स्थापित की गई यह भारत की प्रमुख आतंक-विरोधी जांच एजेंसी है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन का दायित्व सौंपा गया है, जिनमें आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण, आतंकी संबंधों से जुड़े संगठित अपराध, साइबर आतंकवाद और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अन्य अपराध शामिल हैं।

2014 से, सरकार ने एनआईए के जनादेश, परिचालन क्षमताओं और संस्थागत बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है। एनआईए के बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। 2014-15 में 91.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 394.66 करोड़ रुपये हो गया। एक दशक में यह चार गुना से अधिक की वृद्धि है।

मुकदमों की प्रक्रिया में तेजी लाने और दोषसिद्धि दर में सुधार करने हेतु विशेष एनआईए न्यायालयों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क विकसित किया गया है। राज्यों में 47 और केंद्र शासित प्रदेशों में 6 ऐसे न्यायालय कार्यरत किये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एनआईए का विस्तार देशभर में 21 शाखा कार्यालयों के माध्यम से किया गया, जिनमें जम्मू और गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल है। एनआईए द्वारा 2014 के बाद आतंकवाद के वित्तपोषण के 32 मामले दर्ज.किए गए, जबकि 2014 से पहले एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था।

क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, 2019 से अब तक 108 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे 4,471 अधिकारियों को लाभ हुआ है। स्थापना राष्ट्रीय आतंकवाद डेटाबेस संलयन और विश्लेषण केंद्र (NTDFAC) उन्नत विश्लेषण के माध्यम से डेटा-संचालित जांच को बढ़ाया गया है, जबकि फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के साथ घनिष्ठ समन्वय ने वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह और फोरेंसिक जांच को मजबूत किया है।

क्या आप जानते हैं: NIA अब एक विश्वस्तरीय प्रसिद्ध जांच एजेंसी के रूप में उभरी है, जिसका दोषसिद्धि दर 92.70 प्रतिशत है जो विश्वभर की आतंक-विरोधी एजेंसियों में सबसे उच्च स्थान पर है।

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) और खुफिया एकीकरण

खुफिया ब्यूरो (IB) के अधीन कार्यरत बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) भारत में वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय करने का सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। यह आतंकवाद-विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून प्रवर्तन संगठनों सहित 28 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को एक साथ लाता है। एमएसी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित सहायक बहु-एजेंसी केंद्रों (SMAC) का सहयोग प्राप्त है, जो स्थानीय खुफिया जानकारी को संसाधित करते हैं और राज्य पुलिस तथा अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

पिछले एक दशक में, MAC-SMAC नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत की खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली को काफी मजबूती मिली है। यह प्रणाली अब दूरस्थ जिलों और परिचालन इकाइयों तक उन्नत अंतिम-छोर कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित, वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। हाल ही में, 500 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से इस नेटवर्क का एक बड़ा तकनीकी उन्नयन किया गया है। उन्नत हार्डवेयर अवसंरचना, तीव्र नेटवर्क क्षमताएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) से लैस विश्लेषणात्मक उपकरणों ने खुफिया आकलन और खतरे की पहचान की गति, सटीकता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इन प्रगति ने इंटर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया है और उभरते सुरक्षा खतरों को रोकने और उनसे निपटने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है।

क्या आप जानते हैं:गृह मंत्रालय ने बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) ढांचे के अंतर्गत 22 जनवरी 2025 को साइबर बहु-एजेंसी केंद्र (CyMAC) की स्थापना की। CyMAC भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर जासूसी, उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और अन्य साइबर जोखिमों से निपटने के लिए वास्तविक समय समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)

NATGRID एक सुरक्षित खुफिया जानकारी साझा करने वाला प्लेटफॉर्म है जो आव्रजन, बैंकिंग, दूरसंचार और यात्रा रिकॉर्ड सहित कई सरकारी डेटाबेस को अधिकृत सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जोड़ता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी तक रियल-टाइम पहुंच प्रदान करता है, जिससे एजेंसियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने, आतंकी नेटवर्क का पदार्फाश करने, वित्तपोषण के स्रोतों का पता लगाने और खुफिया जानकारी पर आधारित त्वरित जांच में सहायता मिलती है। विभिन्न स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके, NATGRID भारत की आतंकवाद-विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है।

क्या आप जानते हैंः मार्च 2026 तक, NATGRID एक सुरक्षित खुफिया जानकारी साझा करने वाले मंच के माध्यम से 11 केंद्रीय उपयोगकर्ता एजेंसियों, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और 11 डेटा-प्रदान करने वाले संगठनों को जोड़ता है। यह NIA और राज्य ATS के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस (OCND) भी विकसित कर रहा है। वहीं इसका उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरण GANDIVA आतंकवाद विरोधी और आपराधिक जांचों में सहायता के लिए बहु-स्रोत डेटा संग्रह और खुफिया विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)

CCTNS को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया है, जिससे आपराधिक और आतंकी संदिग्धों से संबंधित डेटा को राज्यों के बीच साझा करना संभव हो गया है। इससे उन सूचनाओं के अवरोधों में काफी कमी आई है, जो पहले राज्यों की सीमाओं के पार समन्वित कार्रवाई को सीमित करते थे। भारतभर के सभी 17,798 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले AI-संचालित इकोसिस्टम के साथ CCTNS 2.0 का नया संस्करण वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया था।

क्या आप जानते हैं?

देश की आतंक विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2021 से 2026 के बीच पुलिस और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर 6,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता (ASUMP) योजना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, निगरानी तकनीक, IED-रोधी उपकरणों, फोरेंसिक अवसंरचना और उन्नत संचार प्रणालियों से लैस करने के लिए 4,846 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, आधुनिकीकरण योजना-IV (1,523 करोड़ रुपये) उन्नत निगरानी प्रणालियों और सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की परिचालन तत्परता को बढ़ाया जा रहा है। ये निवेश खतरे का पता लगाने, खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और निष्क्रिय करने की क्षमता में सुधार करते हैं।

संस्थाओं को मजबूत करने से भारत की आतंकवाद-विरोधी व्यवस्था एक अधिक एकीकृत, प्रौद्योगिकी-आधारित और खुफिया जानकारी पर केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। बेहतर समन्वय, उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं और आधुनिक प्रवर्तन तंत्रों ने सुरक्षा खतरों को रोकने, उनकी जांच करने और उनसे निपटने की राष्ट्र की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

तीसरा स्तंभः सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अभियान – रणनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन

दशकों से भारत को अपनी सीमाओं के पार से प्रायोजित और समर्थित लगातार सीमा पार आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। 2014 से, देश ने आतंकवादी हमलों का जवाब देने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सैन्य सटीकता, रणनीतिक संकेत और राजनयिक उपायों को मिलाकर एक अधिक आक्रामक और निवारक-आधारित सुरक्षा नीति अपनाई है।

सर्जिकल स्ट्राइक 2016

29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उरी आतंकी हमले और नियंत्रण रेखा (LoC) के पार आतंकी लॉन्च पैडों से मिली विश्वसनीय खुफिया जानकारी के जवाब में, भारतीय सेना ने भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूर्व-एंपटिव कार्रवाई करने की भारत की तत्परता को प्रदर्शित किया और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने वालों पर दंड लगाने के एक नए सिद्धांत की स्थापना की। इन हमलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रणनीतिक संयम से हटकर एक सक्रिय और निवारक-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्पष्ट बदलाव का संकेत दिया।

बालाकोट स्ट्राइक 2019

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र पर सटीक हवाई हमला किया। आसन्न आतंकवादी हमलों से संबंधित विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, इस अभियान में आतंकवादी संरचनाओं और प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। बालाकोट हवाई हमले ने भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया और सीमा पार आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के उसके संकल्प को प्रदर्शित किया।

ऑपरेशन सिंदूर, 2025

अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में, भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में स्थित आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था। इस ऑपरेशन ने आतंकवादी खतरों के स्रोत पर ही कार्रवाई करने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति त्वरित, सटीक और आनुपातिक प्रतिक्रियाओं की भारत की नीति को और मजबूत किया।

इन अभियानों ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में एक मौलिक बदलाव ला दिया। एक स्पष्ट सिद्धांत स्थापित किया कि आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप त्वरित, सुनियोजित और बहुआयामी कार्रवाई की जाएगी, जिससे आतंकवाद को रोकने की क्षमता मजबूत होगी और अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी पुष्ट होगी।

चौथा स्तंभः बहुपक्षीय और कूटनीतिक आतंक-विरोधी संरचना

आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय खतरा है जिसे केवल घरेलू कार्रवाई से नहीं हराया जा सकता। पिछले एक दशक में, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाने, आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने और सुरक्षा एवं न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सशक्त कूटनीति को बहुपक्षीय भागीदारी के साथ जोड़ा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)

एफएटीएफ धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने के लिए विश्व का प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है। 2010 में सदस्य बनने के बाद से, भारत ने आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए एफएटीएफ प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग किया है। भारत ने आतंकवादियों को वित्तीय सहायता रोकने में पाकिस्तान की कमियों को लगातार उजागर किया है, जिससे उसके क्षेत्र से संचालित होने वाले आतंकवादी नेटवर्कों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित हुई है। साथ ही, भारत ने घरेलू स्तर पर धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी उपायों को मजबूत किया है और आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्कों को बाधित करने के वैश्विक प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। सरकार ने गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम प्रकोष्ठ (सीएफटी प्रकोष्ठ) का गठन किया है, जो धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी मुद्दों से निपटने वाली अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

आतंकवाद पर नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

अप्रैल 2018 में पेरिस में शुरू हुआ और नवंबर 2019 में मेलबर्न में जारी रहा ह्यनो मनी फॉर टेररह्न (NMFT) मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। मेलबर्न सम्मेलन में, राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मानकों के निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक प्रवर्तन की वकालत की।

भारत ने मेजबानी की तीसरी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में (18-19 नवंबर 2022) सरकार ने भारत की छह-स्तंभ वाली आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी रणनीति, सुदृढ़ कानून और निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना, संपति जब्ती, नई प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर अंकुश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित किया। इसने संशोधित यूएपीए, सुदृढ़ ठक्ष्म और पुनर्गठित वित्तीय खुफिया जानकारी पर भी प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT)

भारत ने मूल रूप से नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) का प्रस्ताव रखा था और आतंकवाद के खिलाफ एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए इसे शीघ्र अपनाने का आह्वान करता रहता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करना

एक दशक से अधिक समय तक चीन के वीटो के बाद, भारत ने मई 2019 में खीट के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में सफलता प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत थी जिसने अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों, संपति जब्ती और हथियार प्रतिबंधों को संभव बनाया।

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण (2025)

26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जिससे एनआईए को हमले के पीछे की पूरी साजिश की नए सिरे से जांच करने में मदद मिली।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आतंक-विरोधी सहयोग

भारत के 27 देशों और 5 बहुपक्षीय मंचों (SCO, BIMSTEC, BRICS, यूरोपीय संघ (EU), QUAD-CTWG) के साथ आतंक विरोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG-CT) पूरी तरह से कार्यरत हैं; और ट्यूनीशिया के साथ एक स्वतंत्र संवाद भी है।

क्या आप जानते हैं?

भारत ने प्रमुख साझेदारों के साथ समर्पित संयुक्त कार्य समूहों (JWG) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आतंक-विरोधी सहयोग को और मजबूत किया। 2024 में, भारत ने वाशिंगटन डी.सी. में आतंकवाद-विरोधी विषय पर अपना 20वां भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह और नई दिल्ली में अपना 16वां भारत-ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह आयोजित किया। इन वार्ताओं में आतंकवाद के वित्तपोषण, सीमा पार आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और प्रौद्योगिकी से संबंधित उभरते सुरक्षा खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इंटरपोल के साथ समन्वय

BHARATPOL पोर्टल इसे 7 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। यह CBI (भारत के लिए इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में) को भारत में सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार, साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी और आतंकवाद सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?

आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर दिल्ली घोषणा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-विरोधी समिति (CTC) द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक में, भारत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

इस घोषणापत्र में तीन प्रमुख खतरे वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।मानवरहित हवाई प्रणालियों (ड्रोन) का दुरुपयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का आतंकवादी शोषण, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भुगतान प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।और डिजिटल चैनलों के माध्यम से आतंकवाद का वित्तपोषण करना।

इसमें सदस्य देशों को डिजिटल आतंकवाद के खतरे से निपटने में सहायता करने के लिए गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक ढांचा निर्धारित किया गया और उभरती प्रौद्योगिकियों के आतंकवादी दुरुपयोग से निपटने के लिए सिफारिशें तैयार करने का आदेश दिया गया। घोषणापत्र में भारत के इस दीर्घकालिक रुख की पुष्टि की गई कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

भारत के राजनयिक प्रयासों ने आतंकवाद-विरोधी गतिविधियों को वैश्विक प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है और आतंकवादी तत्वों और उनके प्रायोजकों के लिए अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को मजबूत किया है। बहुपक्षीय मंचों और रणनीतिक साझेदारियों में निरंतर भागीदारी के माध्यम से, भारत वैश्विक आतंकवाद-विरोधी एजेंडा को आकार देने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बारह वर्षों के सुधारों के परिणाम झ्र बढ़ता विश्वास, अधिक सुरक्षा

निरंतर बहुआयामी कदमों और समग्र आतंक-विरोधी उपायों के चलते केंद्र सरकार पिछले 12 वर्षों में आंतरिक सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने और 140 करोड़ भारतीयों के बीच विश्वास बढ़ाने में सफल रही है। 2014 से लागू किए गए उपायों ने हर मोर्चे पर स्पष्ट परिणाम दिए हैं। देश में आतंकी हमलों और उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में भारी गिरावट आई है और विकास की गति फिर से तेज हुई है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद, जम्मू और कश्मीर पिछले एक दशक में सुरक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आतंकवादी घटनाओं में 2004-2014 के दौरान 7,217 की तुलना में 2014-2024 के दौरान 2,242 की कमी आई।। इसके अतिरिक्त, आतंकवादी हमलों से जुड़ी घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है, जो 2018 में 228 से घटकर 2025 में मात्र 12 रह गई हैं। यह भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति की बढ़ती प्रभावशीलता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली को दर्शाता है।

हताहत नागरिक आतंकी घटनाओं से संबंधित मृत्यु संख्या 2018 में 55 से घटकर 2025 में 28 हो गई। सुरक्षा बलों की मौतें इसमें और भी तेजी से गिरावट आई, जो 2018 में 91 से घटकर 2025 में मात्र 16 रह गई, यानी 82 प्रतिशत से अधिक की कमी। दीर्घकालिक रुझान भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः जहां 2004 और 2014 के बीच 1,060 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 2015 और 2025 के बीच यह संख्या घटकर 542 रह गई, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों और बल सुरक्षा उपायों की बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाती है।

पत्थरबाजी की घटनाएं, जो 2010 से 2014 के बीच औसतन प्रतिवर्ष लगभग 2,654 थीं, 2020 तक 87 प्रतिशत से अधिक कम हो गईं और 2022 से लगभग शून्य बनी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार से जम्मू और कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों और जनजीवन में पुनर्जीवन संभव हुआ है। इस प्रगति को दर्शाते हुए, लगभग 80,000 करोड़ रुपये की 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 51,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका है और 53 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जम्मू और कश्मीर में जनजीवन में उल्लेखनीय रूप से सामान्य स्थिति लौट आई है। संगठित हड़तालों और बंद की संख्या 2018 में 52 घटनाओं से घटकर 2023 से अप्रैल 2026 तक शून्य हो गई है। बेहतर स्थिरता ने रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत 2019 से मई 2026 के बीच 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित की गईं और पिछले चार वर्षों में ही स्वरोजगार योजना के तहत 9.81 लाख से अधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

जम्मू और कश्मीर में 2024 में 2.3 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो इसके इतिहास में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आगंतुकों की यह अभूतपूर्व आमद क्षेत्र के सुरक्षा माहौल में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है और जमीनी स्तर पर शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति के सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक है। हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में निवेश प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां इस क्षेत्र ने सात दशकों में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया, वहीं 2016-17 और 2025-26 के बीच ही लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास और बेहतर कारोबारी माहौल को दर्शाता है।.

आंतरिक इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी - पूर्व-निवारण के माध्यम से रोकथाम

भारत के आंतरिक इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में पिछले एक दशक में काफी कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव रहा है। मजबूत खुफिया नेटवर्क से खतरों का पता लगाने में सुधार हुआ है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से त्वरित कार्रवाई संभव हो पाई है। प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और लक्षित अभियानों ने आतंकी साजिशों को अंजाम देने से पहले ही नाकाम करने में मदद की है। इस निवारक दृष्टिकोण ने शहरी केंद्रों में सुरक्षा को मजबूत किया है और बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान वाले हमलों के जोखिम को कम किया है।

2013 के हैदराबाद धमाकों के बाद के दशक में बड़े शहरी आतंकवादी हमलों की लगभग पूरी तरह से अनुपस्थिति रही। यह पिछले दशक के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें संसद पर हमला, मुंबई ट्रेन बम विस्फोट, हैदराबाद धमाके और 26/11 हमले जैसी घटनाएं हुईं। NIA और राज्य खुफिया एजेंसियों की समयबद्ध कार्रवाई से ISIS से प्रेरित कई साजिशों को नाकाम किया गया। इन अभियानों ने भारत की खुफिया-आधारित आतंकवाद-विरोधी रणनीति की बढ़ती प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया।

परिणामस्वरूप, 2014 से 2018 के बीच भीतरी इलाकों में आतंकवादी हमले बहुत कम रहे, केवल छिटपुट घटनाएं ही दर्ज की गईं। यह निरंतर गिरावट देशभर में बेहतर निवारक क्षमताओं और मजबूत सुरक्षा समन्वय को दर्शाती है।

निरंतर सुधारों और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत ने आंतरिक सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। आतंकी घटनाओं, उग्रवादी हिंसा और हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है। संस्थागत क्षमता में वृद्धि से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार हुआ है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और शासन में नागरिकों का विश्वास मजबूत हुआ है।

निष्कर्ष

पिछले बारह वर्षों में, भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के मार्गदर्शन में अपनी आतंकवाद-विरोधी संरचना में व्यापक परिवर्तन किया है। सरकार ने कानूनी ढाँचे को मजबूत किया है, जाँच संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है और खतरों का समय पर पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए इंटर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA),(IB) और राज्य पुलिस बलों जैसी एजेंसियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, विस्तारित अधिकार क्षेत्र और बेहतर फोरेंसिक एवं खुफिया क्षमताओं से सशक्त बनाया गया है। रीयल-टाइम डेटा एकीकरण प्लेटफॉर्म और उन्नत संचार प्रणालियों ने परिचालन दक्षता में और सुधार किया है। साथ ही, राजनयिक और बहुपक्षीय प्रयासों ने आतंकी नेटवर्क के वित्तपोषण और सीमा पार खतरों के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत किया है। इन निरंतर प्रयासों से आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है और जनता का विश्वास बढ़ा है। यह दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई से सक्रिय रोकथाम की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में उभरती चुनौतियों के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा लचीली, अनुकूलनीय और भविष्य के लिए तैयार बनी रहे और लचीलापन लगातार मजबूत होता रहे।

रेल मंत्री ने छपरा-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बिहार में बुलेट ट्रेन लाने की घोषणा

बिहान भारत

छपरा। जिले के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन तब ऐतिहासिक बन गया, जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन से आनंद विहार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई ट्रेन सेवा की शुरूआत से क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने इसे दिल्ली-एनसीआर से बेहतर रेल संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

इससे पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विशेष ट्रेन से छपरा पहुंचे और स्टेशन परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छपरा की धरती ऐतिहासिक और प्रेरणादायी रही है। इसी धरती ने देश को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा महान व्यक्तित्व दिया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूडी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में रेलवे विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार को रेलवे परियोजनाओं के

लिए सीमित बजट मिलता था, लेकिन अब रेल बजट को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।

रेल मंत्री ने कहा कि इस बढ़े हुए बजट का परिणाम पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। राज्य में नई रेल लाइनों का निर्माण, तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का कार्य, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण तथा स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में बिहार में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस और 14 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का सफल संचालन हो रहा है। आने वाले वर्षों में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लखनऊ-वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी मार्ग पर विकसित किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र चार घंटे 41 मिनट में पूरी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य को प्रतिवर्ष लगभग आठ से दस हजार करोड़ रुपये रेलवे विकास के लिए आवंटित किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बिहार के 38 में से 36 जिले प्रभावी रूप से रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के समग्र विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दोपहर लगभग 2:25 बजे केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नियमित परिचालन के तहत गाड़ी संख्या 12527 छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को रात 8:50 बजे छपरा से प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 2:00 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12528 आनंद विहार-छपरा एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को शाम 4:25 बजे आनंद विहार से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:40 बजे छपरा पहुंचेगी।

यह सुपरफास्ट ट्रेन बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। नई रेल सेवा से छात्रों, किसानों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को विशेष सुविधा मिलेगी तथा सारण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में सांसद राजीव प्रताप रूडी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव, सच्चिदानंद राय, विधायक जनक सिंह, विनय सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ धुमल, छोटी कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार तथा मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी भी समारोह में मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

नीट परीक्षा के लिए रेलवे की बड़ी पहल: आसनसोल मंडल चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, कई ट्रेनों को मिला अस्थायी ठहराव

आसनसोल(बिभा): आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट (यूजी)-2026 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए विशेष ट्रेन व्यवस्था की गई है। दिनांक 21 जून 2026 को 22321 हूल एक्सप्रेस को विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अंडाल एवं सिउड़ी खंड के बीच सभी स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंच सकें। इसी प्रकार, 05573 सरायगढ़-देवघर विशेष ट्रेन भी उसी दिन बांका एवं देवघर खंड के बीच सभी स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव करेगी, जिससे नीट परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को लाभ मिलेगा। बीरभूम क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा हेतु, दिनांक 21 जून 2026 को 08 डिब्बों वाली विशेष मेमू ट्रेन (03539/03540) अंडाल एवं सैंथिया के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन अंडाल से प्रातः 10:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा काजोराग्राम, सिदुली, उखरा, पांडाबेश्वर, भीमगड़ा, पांचरा, दुबराजपुर, चिनपाई, कचुजोर, सिउड़ी, कुनुरी एवं महिषादहाड़ी स्टेशनों पर ठहरते हुए सैंथिया 12:15 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में यह ट्रेन सैंथिया से 18:15 बजे प्रस्थान कर अंडाल 20:15 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार, झारखंड क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा हेतु, दिनांक 21 जून 2026 को 08 डिब्बों वाली विशेष मेमू ट्रेन (03541/03542) जसीडीह एवं दुमका के बीच देवघर एवं बासुकीनाथ होकर चलाई जाएगी। यह ट्रेन जसीडीह से प्रातः 09:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा देवघर, मोहनपुर, सिरसा नूंथर हॉल्ट, घोरमारा, धनपतडीह, चंदनपहाड़ी, बासुकीनाथ, जामा एवं न्यू मदनपुर स्टेशनों पर ठहरते हुए दुमका 11:15 बजे पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन दुमका से 18:30 बजे प्रस्थान कर जसीडीह 20:15 बजे पहुंचेगी। इन विशेष व्यवस्थाओं का उद्देश्य नीट (यूजी)-2026 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाना है। आसनसोल मंडल सभी विद्यार्थियों एवं यात्रियों से अपील करता है कि वे इन विशेष ट्रेन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें तथा आरामदायक एवं परेशानी मुक्त यात्रा हेतु अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं।

मंडल रेल प्रबंधक ने बरवाडीह क्षेत्र का किया निरीक्षण

धनबाद(बिभा): मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र द्वारा बरवाडीह क्षेत्र एवं इसके समीपवर्ती स्टेशनों का विस्तृत निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे संरक्षा, परिचालन व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों तथा विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए इस क्रम में उन्होंने मंगरा, बरवाडीह एवं छीपादोहर स्टेशनों पर नव-निर्मित स्टेशन भवनों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की साथ ही मंगरा-बरवाडीह-मैकलुस्कीगँज रेल खंड के मध्य विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया गया इस अवसर पर मंडल के अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में 820 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

बिहान भारत

कोलकाता: राज्य की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदल देने वाले एक ऐतिहासिक अवसर में, दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अपराह्न 3:15 बजे हुगली जिले के तारकेश्वर पहुंचेंगे, जहां वे विकास की तीव्र गति पर पश्चिम बंगाल विषय के अंतर्गत लगभग 820 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम राज्य के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक परिवर्तन के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा का प्रमुख आकर्षण लगभग 590 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही विशाल रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, आवागमन तथा जनकल्याण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी हावड़ा में 99 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक 300-बेड वाले नए मंडलीय रेलवे अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। यह आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नत

निदान सुविधाओं, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों तथा विशिष्ट चिकित्सीय सेवाओं से सुसज्जित होगा, जिससे हजारों रेलवे कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यातायात बाधाओं को दूर करने तथा सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री पूर्व मेदिनीपुर जिले के हाउर और राधामोहनपुर के बीच 71 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले रोड ओवर ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना यात्रियों और माल परिवहन दोनों के लिए निर्बाध एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करेगी।इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री हावड़ा में 421 करोड़ की लागत से विकसित रणनीतिक महत्व की संकराइल-सांतरागाछी लिंक लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह महत्वपूर्ण रेलवे संपर्क परियोजना परिचालन क्षमता में वृद्धि, क्षेत्रीय रेल यातायात के विस्तार, बढ़ती लॉजिस्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा दैनिक यात्रा समय में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पश्चिम बंगाल के परिवहन तंत्र को तीव्र विकास की दिशा में अग्रसर करेगी।

साथ ही, प्रधानमंत्री तारकेश्वर से ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का शुभारंभ करेंगे। वे देशभर के किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहुंचाने वाली बहुप्रतीक्षित पीएम-किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण तथा जलवायु संबंधी जोखिमों से सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का शुभारंभ करेंगे तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी लागू करेंगे। स्वस्थ एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन का शुभारंभ करेंगे तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरूआत करेंगे। ग्रामीण एवं तटीय विकास को नई गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -क्क्क (पीएमजीएसवाई-क्क्क) के अंतर्गत विभिन्न दूरस्थ जिलों में निर्मित 315 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन करेंगे, जिससे गांवों और शहरी आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा। पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नदिया जिले के हरिणघाटा में अत्याधुनिक बकरी वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला एवं वीर्य बैंक, फ्रेजरगंज में विस्तारित आधुनिक मत्स्य बंदरगाह तथा बीरभूम जिले के साईंथिया में आधुनिक मत्स्य बाजार का उद्घाटन करेंगे। उच्च क्षमता वाले रेलवे नेटवर्क, कृषि में डिजिटल सुधार, बेहतरीन हेल्थकेयर यूनिट और ज्यादा पैदावार देने वाली पशुपालन तकनीक को एक साथ लाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक स्थिति को बदल रहे हैं और राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक शानदार और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता बना रहे हैं।।

ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित चाइल्डलाइन के सुपुर्द किया गया

बिहान भारत

प्रयागराज । मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त दीपक कुमार आजाद के नेतृत्व में प्रयागराज मंडल का रेलवे सुरक्षा बल बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ह्यनन्हे फरिस्तेह्न के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में अकेले, लापता, भटके हुए अथवा संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत प्रयागराज मंडल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2026 से 15 जून 2026 तक कुल 315 बच्चों को रेलगाड़ियों एवं रेलवे परिक्षेत्र से सुरक्षित बचाया गया। इन बच्चों में ऐसे बालक एवं बालिकाएँ शामिल थे जो अपने परिजनों से बिछड़ गए थे, घर से भटककर रेलवे परिसर में पहुँच गए थे अथवा अन्य कारणों से असुरक्षित स्थिति में पाए गए थे।

इसी क्रम में 18 जून 2026 को प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग स्टाफ को एक नाबालिक बालिका गुमसुम अवस्था में मिली, जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रयागराज छिवकी को सुपुर्द किया गया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि वह घर से नाराज होकर अपना सामान लेकर निकल गई थी और प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बालिका को सुरक्षित संरक्षण में लेकर आवश्यक पूछताछ एवं काउंसलिंग की गई। इसके उपरांत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बालिका को अग्रिम विधिक कार्यवाही एवं देखभाल हेतु चाइल्डलाइन की महिला केस वर्कर को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया।

रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के माध्यम से भटके हुए एवं असहाय बच्चों को संरक्षण प्रदान कर उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है।

रेलवे प्रशासन यात्रियों एवं आमजन से अपील करता है कि यदि किसी बच्चे को रेलवे स्टेशन अथवा ट्रेन में अकेला, परेशान या संदिग्ध परिस्थिति में देखें तो तत्काल रेलवे सुरक्षा बल, हेल्पलाइन 139 अथवा निकटतम रेलवे कर्मचारी को सूचित करें, जिससे समय रहते उसकी सहायता सुनिश्चित की जा सके।

आरपीएफ ने 18 बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा

बिभा संवाददाता

रांची : रेलवे सुरक्षा बल फ्लाइंग टीम रांची एवं आरपीएफ पोस्ट रांची के कैंपिंग स्टाफ द्वारा ऑपरेशन ‡सतर्क‡ के तहत नामकुम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 18626 एक्सप्रेस के आगमन के दौरान सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व उपनिरीक्षक रवि शेखर द्वारा किया गया। उनके साथ आरक्षक प्रदीप, आरक्षक हेमंत, आरक्षक डी.के. जीतरवाल तथा आरक्षक इन्द्रेश कुमार सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को एक ट्रॉली बैग एवं एक पिट्ठू बैग के साथ ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया। संदेह के आधार पर उसे रोककर उसके सामान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल 18 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम जीशान कुमार (19 वर्ष), पिता- राजेश कुमार, निवासी- भरावपर, मुरारपुर, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा (बिहार) बताया। शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने स्वीकार किया कि वह उक्त शराब को रांची से खरीदकर बिहार ले जा रहा था, जहां उसे अधिक कीमत पर बेचने की योजना थी। इसके उपरांत सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए उपनिरीक्षक रवि शेखर द्वारा शराब की बोतलों को जब्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 33,000/- है। गिरफ्तार व्यक्ति एवं जब्त शराब को आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग, रांची को सुपुर्द कर दिया गया।

अब स्टेशन मास्टर को अधिक पावर देगा भारतीय रेलवे, हुई चर्चा

बिहान भारत

नई दिल्ली : केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें स्टेशन मास्टरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही, भारतीय रेल नेटवर्क में सुरक्षित, अधिक कुशल और यात्री-केंद्रित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे पर विचार-विमर्श भी किया गया।

रेलवे स्टेशनों के सुचारू संचालन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, यात्री सुविधाओं के प्रबंधन और सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में स्टेशन मास्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समीक्षा के दौरान, स्टेशन मास्टरों के दैनिक कार्यों में आने वाली प्रचालनगत और प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान करने एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समाधान विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में स्टेशन मास्टरों की भूमिका को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक और प्रचालनगत शक्तियों में वृद्धि, करियर में उन्नति के बेहतर अवसर और प्रबंधन के उच्च स्तरों तक पहुंचने के अधिक अवसरों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इन उपायों का उद्देश्य स्टेशन मास्टरों को त्वरित निर्णय लेने, यात्री सेवा में सुधार करने और स्टेशन की अवसंरचना, स्टाफ कार्यालयों, कॉलोनियों और अन्य संबंधित सुविधाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में सक्षम बनाना है।

बढ़ती प्रचालनगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मल्टी-ट्रैक और उच्च-घनत्व वाले खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति पर चर्चा केंद्रित रही, जहां यातायात स्तर और प्रचालनगत जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्टेशन मास्टर पद में रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की आवश्यकता की भी समीक्षा की गई, जिसमें इन रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने पर जोर दिया गया।

कार्यकुशलता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करते हुए, स्टेशन मास्टरों के लिए मोबाइल ऐप आधारित कागज रहित कार्य प्रणाली शुरू करने पर चर्चा हुई। बैठक में एकीकृत स्टेशन प्रबंधन प्रणाली के विकास की भी समीक्षा की गई, जिससे रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और स्टेशनों पर यात्रियों से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

रेल मंत्री ने आधुनिक कौशल विकास और क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया। अधिकारियों ने वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेटर और अन्य आधुनिक प्रशिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से प्रशिक्षण पद्धतियों को उन्नत करने पर चर्चा की, ताकि स्टेशन मास्टरों को निरंतर जटिल होते रेलवे संचालन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

स्थानीय मुद्दों के त्वरित समाधान और यात्रियों की सुविधा में सुधार के लिए, स्टेशन मास्टरों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। स्टेशन स्तर पर अधिक अधिकार मिलने से समय पर रखरखाव, यात्रियों की आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर स्टेशन प्रबंधन की उम्मीद है।

बैठक में स्टेशन मास्टरों के लिए कैरियर में प्रगति के अवसरों को बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार किया गया, जिससे भारतीय रेल में उच्च स्तर के प्रबंधन और नेतृत्व पदों तक उनकी पहुंच बढ़ सके। चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस महत्वपूर्ण प्रचालनगत श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिक प्रेरक और विकासोन्मुखी कार्य वातावरण बनाना था।

सुरक्षा संबंधी मुद्दों की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य बिंदु रेल संचालन में महिला स्टेशन मास्टरों और महिला पॉइंट्समैनों की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर बेहतर सुरक्षा उपकरण और उपयोग में सरल उपकरण उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य रेलवे के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, अधिक सुलभ और अधिक कुशल कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है।

समीक्षा बैठक के दौरान जिन पहलों पर चर्चा हुई, वे भारतीय रेल की स्टेशन मास्टरों को बेहतर मानव संसाधन सहायता, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रशिक्षण और अधिक निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसका उद्देश्य देश भर के लाखों यात्रियों के लिए अधिक उत्तरदायी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार स्टेशन प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना है।

चुनार-चोपन रेल खंड के समपार फाटक संख्या-19 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के लिए लगाए गए गर्डर

बिहान भारत

प्रयागराज । मण्डल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेल एवं सड़क यातायात को अधिक सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। चुनारझचोपन रेल खंड पर लूसा के निकट स्थित समपार फाटक संख्या-19 के यतायात सुगम बनाने के लिए निमार्णाधीन रोड ओवर ब्रिज के रेलवे भाग पर स्टील गर्डरों के सफल लांचिंग/स्थापना का कार्य संपन्न किया गया।

निमार्णाधीन आरओबी की कुल लंबाई 585 मीटर है, जबकि रेलवे हिस्से की लंबाई 36 मीटर तथा चौड़ाई 7.5 मीटर है। यह

परियोजना चुनार नगर को राज्य राजमार्ग-35 (मिजार्पुरझसोनभद्र मार्ग) से बेहतर एवं निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के बाद समपार फाटक पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी तथा सड़क एवं रेल दोनों यातायात की सुरक्षा और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

निर्माण कार्य के दौरान आधुनिक तकनीकों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया। विशाल क्रेनों की सहायता से स्टील गर्डरों को निर्धारित स्थान पर स्थापित किया गया। यह कार्य रेलवे एवं निर्माण एजेंसियों के समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस महत्वपूर्ण कार्य के सफल निष्पादन में उप मुख्य अभियंता (ब्रिज/लाइन), प्रयागराज, आई.पी.एस. यादव; सहायक कार्यकारी अभियंता (ब्रिज/लाइन), प्रयागराज लाल बहादुर तथा ब्रिज लाइन टीम की विशेष भूमिका रही। टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर इस महत्वपूर्ण चरण को पूरा किया गया।

रोड ओवर ब्रिज के पूर्ण होने के उपरांत क्षेत्र के निवासियों, व्यापारिक गतिविधियों तथा यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही यह परियोजना क्षेत्रीय विकास एवं बेहतर यातायात अवसंरचना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट, भोसले गली, हरिहर सिंह रोड, बरियातू, रांची-834009 (झारखंड) दूरभाष: 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा शिवा साई पब्लिकेशन प्रा.लि. (एसएच प्रिंटर प्रा.लि.), काठीटांड रातु, नियर टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप, रातु, रांची - 835222 झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू** (*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली ।**
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com